चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित

दिल्ली, 25 अप्रैल–01 मई 2011

मूल्य 5 रुपये

अन्ना को अन्ना ही रहने दो

पेज-3

अब तो फ़ैसले की घड़ी है

पेज-5

घटता पानी बढ़ती प्यास

पेज-7

साई की महिमा

पेज-12

सरकार ने देश को बेच डाला

26 लाख करोड़ का महा घोटाला

भारत का सबसे बड़ा घोटाला EXCLUSIVE

क्या सर्वोच्च न्यायालय इस महाघोटाले को अनदेखा कर देगा? संसद से हमें बहुत ज़्यादा आशा नहीं है, क्योंकि उसकी समझ में जब तक आएगा, तब तक उसके 5 साल पूरे हो जाएंगे. जनता बेबस है, उसे हमेशा एक महानायक की तलाश रहती है और अब महानायक पैदा होने बंद हो चुके हैं. अब एक ही महानायक है और वह है देश का सुप्रीम कोर्ट, उसी के चेतने का इंतज़ार है.

सिद्धार्थ राय

अगर 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला देश के सभी घोटालों की जननी है तो आज जिस घोटाले का चौथी दुनिया पर्दाफाश कर रहा है, वह देश में हुए अब तक के सभी घोटालों का पितामह है. चौथी दुनिया आपको अब तक के सबसे बड़े घोटाले से रूबरू करा रहा है. देश में कोयला आवंटन के नाम पर करीब 26 लाख करोड़ रुपये की लूट हुई है. सबसे बड़ी बात है कि यह घोटाला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही नहीं, उन्हीं के मंत्रालय में हुआ. यह है कोयला घोटाला. कोयले को काला सोना कहा जाता है, काला हीरा कहा जाता है, लेकिन सरकार ने इस हीरे का बंदरबांट कर डाला और अपने प्रिय-चहेते पूंजीपतियों एवं दलालों को मुफ्त ही दे दिया. आइए देखें, इतिहास की सबसे बड़ी लूट की पूरी कहानी क्या है.

सबसे पहले समझने की बात यह है कि देश में कोयला उत्खनन के संबंध में सरकारी रवैया क्या रहा है. 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए देश में कोयले का उत्खनन निजी क्षेत्र से निकाल लिया और इस एकाधिकार को सरकार के अधीन कर दिया. मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. शायद इसी कारण देश में कोयले का उत्पादन दिनोंदिन बढ़ता गया. आज यह 70 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 493 (2009) मिलियन मीट्रिक टन हो गया है. सरकार द्वारा कोयले के उत्खनन और विपणन का एकाधिकार कोल इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया है. इस कारण अब कोयला नोटिफाइड रेट पर उपलब्ध है, जिससे कोयले की कालाबाज़ारी पर बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया गया. लेकिन कैप्टिव ब्लॉक (कोयले का संशोधित क्षेत्र) के नाम पर कोयले को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की सरकारी नीति से इसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा और यह काम यूपीए सरकार की अगुवाई में हुआ है.

सबसे बड़ी बात है कि यह घोटाला सरकारी फाइलों में दर्ज है और सरकार के ही आंकड़े चीख-चीखकर कह रहे हैं कि देश के साथ एक बार फिर बहुत बड़ा धोखा हुआ है. यह बात है 2006-2007 की, जब शिबू सोरेन जेल में थे और प्रधानमंत्री ख़ुद ही कोयला मंत्री थे. इस काल में दासी नारायण और संतोष बागडोदिया राज्यमंत्री थे. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोयले के संशोधित क्षेत्रों को निजी क्षेत्र में सबसे अधिक तेजी से बांटा गया. सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोयले की खानें सिर्फ 100 रुपये प्रति टन की खनिज रॉयल्टी के एवज़ में बांट दी गईं. ऐसा तब किया गया, जब कोयले का बाज़ार मूल्य 1800 से 2000 रुपये प्रति टन के ऊपर था. जब संसद में इस बात को लेकर कुछ सांसदों ने हंगामा किया, तब शर्मसार होकर सरकार ने कहा कि माइंस और मिनरल (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1957 में संशोधन किया जाएगा और तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं की जाएगी. 2006 में यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया और यह माना गया कि जब तक दोनों सदन इसे मंजूरी नहीं दे देते और यह बिल पास नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं की जाएगी. लेकिन यह विधेयक चार साल तक लोकसभा में जानबूझ कर लंबित रखा गया और 2010 में ही यह क़ानून में तब्दील हो पाया. इस दरम्यान संसद में किए गए वादे से सरकार मुकर गई और कोयले के ब्लॉक बांटने का गोरखधंधा चलता रहा. असल में इस विधेयक को लंबित रखने की राजनीति बहुत गहरी थी. इस विधेयक में साफ़-साफ़ लिखा था कि कोयले या किसी भी खनिज की खदानों के लिए सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. अगर यह विधेयक लंबित न रहता तो सरकार अपने चहेतों को मुफ्त कोयला कैसे बांट पाती. इस समयावधि में लगभग 21.69 बिलियन टन कोयले के उत्पादन क्षमता वाली खदानें निजी क्षेत्र के दलालों और पूंजीपतियों को मुफ्त दे दी गईं.

प्रधानमंत्री ने टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले की ज़िम्मेदारी मंत्री पर डाल दी. उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था. आदर्श घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला भी दूसरों ने किया, लेकिन अब उनके ही कोयला मंत्री रहते हुए जो महा घोटाला हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? इस सवाल का जवाब जनता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ज़रूर जानना चाहेगी.

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

इस दरम्यान प्रधानमंत्री भी कोयला मंत्री रहे और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उन्हीं के नीचे सबसे अधिक कोयले के ब्लॉक बांटे गए. ऐसा क्यों हुआ? प्रधानमंत्री ने हद कर दी, जब उन्होंने कुल 63 ब्लॉक बांट दिए. इन चार सालों में लगभग 175 ब्लॉक आनन-फानन में पूंजीपतियों और दलालों को मुफ्त में दे दिए गए.

वैसे बाहर से देखने में इस घोटाले की असलियत सामने नहीं आती, इसलिए चौथी दुनिया ने पता लगाने की कोशिश की कि इस घोटाले से देश को कितना घाटा हुआ है. जो परिणाम सामने आया, वह स्तब्ध कर देने वाला है. दरअसल निजी क्षेत्र में कैप्टिव (संशोधित) ब्लॉक देने का काम 1993 से शुरू किया गया. कहने को ऐसा इसलिए किया गया कि कुछ कोयला खदानें खनन की दृष्टि से सरकार के लिए आर्थिक रूप से कठिन कार्य सिद्ध होंगी. इसलिए उन्हें निजी क्षेत्र में देने की ठान ली गई. ऐसा कहा गया कि मुनाफ़े की लालसा में निजी उपक्रम इन दूरदराज़ की और कठिन खदानों को विकसित कर लेंगे तथा देश के कोयला उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी. 1993 से लेकर 2010 तक 208 कोयले के ब्लॉक बांटे गए, जो कि 49.07 बिलियन टन कोयला था. इनमें से 113 ब्लॉक निजी क्षेत्र में 184 निजी कंपनियों को दिए गए, जो कि 21.69 बिलियन टन कोयला था. अगर बाज़ार मूल्य पर इसका आकलन किया जाए तो 2500 रुपये प्रति टन के हिसाब से इस कोयले का मूल्य 5,382,830.50 करोड़ रुपये निकलता है. अगर इसमें से 1250 रुपये प्रति टन काट दिया जाए, यह मानकर कि 850 रुपये उत्पादन की क़ीमत है और 400 रुपये मुनाफ़ा, तो भी देश को लगभग 26 लाख करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ. तो यह हुआ घोटालों का बाप. आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला और शायद दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होने का गौरव भी इसे ही मिलेगा. तहक़ीक़ात के दौरान चौथी दुनिया को कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे, जो चौंकाने वाले खुलासे कर रहे थे. इन दस्तावेजों से पता चलता है कि इस घोटाले की जानकारी सीएजी (कैग) को भी है. तो सवाल यह उठता है कि अब तक इस घोटाले पर सीएजी चुप क्यों है?

देश की खनिज संपदा, जिस पर 120 करोड़ भारतीयों का समान अधिकार है, को इस सरकार ने मुफ्त में अनैतिक कारणों से प्रेरित होकर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कोयला घोटाले से लाभान्वित बड़ी कंपनियों के नाम

- हिंडाल्को
- जयप्रकाश असोसिएट्स
- एस्सार पावर
- भूषण पावर स्टील
- जीवीके पावर
- जिंदल पावर एंड स्टील
- आर्सेलर मित्तल
- अदानी पावर
- जीएमआर एनर्जी
- रिलायंस एनर्जी
- टाटा स्टील
- स्ट्रैटेजिक एनर्जी
- अकलतारा पावर लि.
- एसकेएस इस्पात
- पावर फाइनेंस कॉर्प. उड़ीसा
- लांको ग्रुप लिमिटेड
- नवभारत पावर लिमिटेड
- आरकेएम पावरजेन
- वीज़ा पावर लिमिटेड
- ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमि.
- गुजरात अंबुजा सीमेंट
- जय बाला जी इंडस्ट्री

नोट: यह लिस्ट 184 कंपनियों की है, जिन्हें मुफ्त में कोयला खदानें मिलीं.

(पूरी लिस्ट www.chauthiduniya.com पर देखें)

यह बिल उन बाबुओं की संपत्ति को जब्त करने की ताकत देता है, जिन्होंने अवैध तरीके से, भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कमाया है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

मुखिया विहीन बैंकिंग सेक्टर

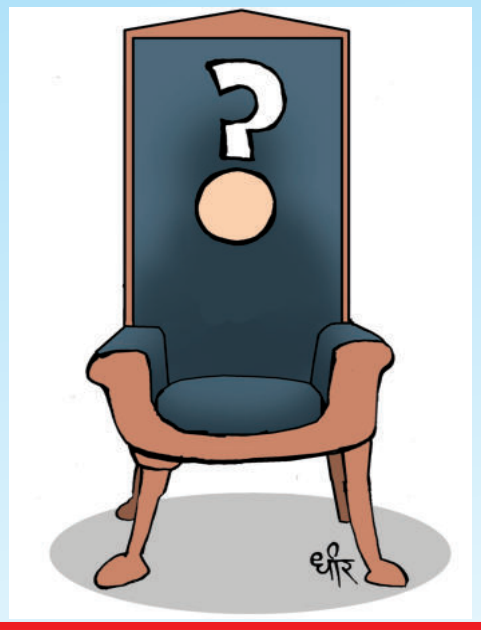

पिछले 9 महीने से पंजाब एंड सिंध बैंक के सीएमडी का पद रिक्त है, लेकिन अब तक इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के बीच जारी तनातनी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है. अब तक ये दोनों मिलकर यह तय नहीं कर पाए हैं कि चली आ रही परंपरा के अनुसार इस पद पर एक सिख को बैठाया जाए या नहीं. लेकिन सिर्फ़ यही एक पद नहीं है, जिसे लेकर इतनी किचकिच मची हुई है. अभी भी बैंकिंग सेक्टर के कई ऐसे हाई प्रोफाइल पद भरे जाने बाकी हैं, लेकिन फाइल है कि एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के चक्कर ही काट रही है. सूत्र बताते हैं कि सिडबी के नए सीएमडी सुशील मनहोत का नाम तय होने में 9 महीने से ज़्यादा का वक़्त लगा. नाबार्ड में भी उच्च पद पर नियुक्ति को लेकर पिछले साल से चल रहा साक्षात्कार अभी भी जारी है, लेकिन सरकार किसी फाइनल नाम पर नहीं पहुंच सकी है. आईडीबीआई के डिप्टी एमडी की नियुक्ति को लेकर भी यही स्थिति है. इस पद के लिए नवंबर 2009 में साक्षात्कार हुए थे. केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर सरकार ने अप्रत्याशित रूप से जल्दबाजी दिखाई थी. ओ पी भट्ट के रिटायर होने के तुरंत बाद ही इस पद पर प्रतीप चौधरी को नियुक्त कर दिया गया था.

नीतीश के नक़्शे क़दम पर शिवराज

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ नीतीश कुमार की लड़ाई को चारों ओर से सराहना मिली. जब नीतीश सरकार ने 2009 में एक बिल पास करके दागी नौकरशाहों की संपत्ति जब्त करने की व्यवस्था की, तब इस क़ानून की न सिर्फ़ चर्चा हुई, बल्कि जमकर तारीफ़ भी मिली. नीतीश सहित सबने यह माना कि इस क़ानून ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनवाने में सहायता की. अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का एक बिल पास किया है. यह बिल उन बाबुओं की संपत्ति को ज़ब्त करने की ताक़त देता है, जिन्होंने अवैध तरीक़े से, भ्रष्टाचार के ज़रिए पैसा कमाया है. नया स्पेशल कोर्ट बिल 2011 यह सुनिश्चित करेगा कि पटवारी से लेकर मुख्य सचिव तक के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के किसी मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में जल्द से जल्द हो. भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों पर राज्य सरकार की चिंता जायज़ है. पिछले कुछ समय में बड़े पैमाने पर नौकरशाहों द्वारा भ्रष्टाचार में शामिल होने की ख़बरें सामने आई हैं. हाल में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी और उनकी पत्नी टीनू को अवैध तरीक़े से 350 करोड़ रुपये की कमाई के लिए गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा कई अन्य बड़े बाबुओं से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले (भ्रष्टाचार के) भी सामने आए. हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की यह पहल भी उसी तरह रंग लाए, जैसे बिहार में नीतीश कुमार का प्रयास.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

अरविंद बनेंगे जेएस

आंध्र प्रदेश कैडर और 1991 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार अभी खाद्य एवं जन वितरण विभाग में निदेशक पद पर तैनात हैं. उन्हें संयुक्त सचिव बनाकर वित्तीय सेवा विभाग में भेजा जा सकता है. वह के वी इपेन की जगह ले सकते हैं.

शैलेष की जगह राकेश

वर्ष 1987 बैच के आईए एंड एएस अधिकारी राकेश मोहन युवा मामलों के विभाग में शैलेष की जगह लाए जा सकते हैं. शैलेष 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इस विभाग में उनका वर्तमान कार्यकाल मई 2011 में ख़त्म हो रहा है.

गोपाल डीआईपीपी के निदेशक

वर्ष 2001 बैच के आईईएस अधिकारी गोपाल प्रसाद को डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोमोशन में निदेशक बनाए जाने की खबर है. वह शशि रंजन कुमार की जगह नियुक्त किए जाएंगे.

हरिंदर होंगे निदेशक

वर्ष 1991 बैच के आईटीएस अधिकारी हरिंदर कुमार ऑफिसियल लैंग्वेज विभाग में निदेशक का पद संभाल सकते हैं. वह 1983 बैच के आईएसएस अधिकारी राकेश कुमार की जगह लेंगे.

तीन महीने का सेवा विस्तार

उत्तर प्रदेश कैडर और 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार अभी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं. उन्हें तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया है.

26 लाख करोड़ का महा घोटाला

स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए देश में कोयले का उत्खनन निजी क्षेत्र से निकाल लिया और इस एकाधिकार को सरकार के अधीन कर दिया. मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. शायद इसी कारण देश में कोयले का उत्पादन दिनोंदिन बढ़ता गया. आज यह 70 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 493 (2009) मिलियन मीट्रिक टन हो गया है. सरकार द्वारा कोयले के उत्खनन और विपणन का एकाधिकार कोल इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया है. इस कारण अब कोयला नोटिफाइड रेट पर उपलब्ध है, जिससे कोयले की कालाबाज़ारी पर बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया गया. लेकिन कैप्टिव ब्लॉक (कोयले का संशोधित क्षेत्र) के नाम पर कोयले को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की सरकारी नीति से इसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा और यह काम यूपीए सरकार की अगुवाई में हुआ है.

पृष्ठ एक का शेष

बांट दिया. अगर इसे सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया अपना कर बांटा जाता तो भारत को इस घोटाले से हुए 26 लाख करोड़ रुपये के राजस्व घाटे से बचाया जा सकता था और यह पैसा देशवासियों के हितों में ख़र्च किया जा सकता था.

यह सरकार जबसे सत्ता में आई है, इस बात पर ज़ोर दे रही है कि विकास के लिए देश को ऊर्जा माध्यमों के दृष्टिकोण से स्वावलंबी बनाना ज़रूरी है. लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है, वह यह है कि प्रधानमंत्री और बाक़ी कोयला मंत्रियों ने कोयले के ब्लॉक निजी खिलाड़ियों को मुफ्त में बांट दिए. जबकि इस सार्वजनिक संपदा की सार्वजनिक और पारदर्शी नीलामी होनी चाहिए थी. नीलामी से अधिकाधिक राजस्व मिलता, जिसे देश में अन्य हितकारी कार्यों में लगाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. जब इस मामले को संसद में उठाया गया तो सरकार ने संसद और लोगों को गुमराह करने का काम किया. सरकारी विधेयक लाने की बात कही गई, जिसके तहत यह नीलामी की जा सकेगी, लेकिन यह विधेयक चार साल तक लोकसभा में लंबित रखा गया, ताकि सरकार के जिन निजी खिलाड़ियों के साथ काले संबंध हैं, उन्हें इस दरम्यान कोयले के ब्लॉक जल्दी-जल्दी बांटकर ख़त्म कर दिए जाएं. इसमें कितनी रकम का लेन-देन हुआ होगा, यह ज़ाहिर सी बात है.

लेकिन अनियमितताएं यहीं ख़त्म नहीं हो जातीं. एक ऐसी बात सामने आई है, जो चौंका देने वाली है. सरकारी नियमों के अनुसार, कोयले के ब्लॉक आवंटित करने के लिए भी कुछ नियम हैं, जिनकी साफ़ अनदेखी कर दी गई. ब्लॉक आवंटन के लिए कुछ सरकारी शर्तें होती हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में अनदेखा नहीं किया जा सकता. ऐसी एक शर्त यह है कि जिन खदानों में कोयले का खनन सतह के नीचे होना है, उनमें आवंटन के 36 माह बाद (और यदि वन क्षेत्र में ऐसी खदान है तो यह अवधि छह महीने बढ़ा दी जाती है) खनन प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए. यदि खदान ओपन कास्ट किस्म की है तो यह अवधि 48 माह की होती है. (जिसमें वन क्षेत्र हो तो पहले की तरह ही छह महीने की छूट मिलती है.) अगर इस अवधि में काम शुरू नहीं होता है तो खदान मालिक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. समझने वाली बात यह है कि इस प्रावधान को इसलिए रखा गया है, ताकि खदान और कोयले का उत्खनन बिचौलियों के हाथ न लगे, जो सीधे-सीधे तो कोयले का काम नहीं करते, बल्कि खदान ख़रीद कर ऐसे व्यापारियों या उद्योगपतियों को बेच देते हैं, जिन्हें कोयले की ज़रूरत है. इस गोरखधंधे में बिचौलिए मुंहमांगे और अनाप-शनाप दामों पर खदानें बेच सकते हैं. लेकिन सरकार ने ऐसी कई खदानों का लाइसेंस रद्द नहीं किया, जो इस अवधि के भीतर उत्पादन शुरू नहीं कर पाईं. ऐसा इसलिए, क्योंकि आवंटन के समय बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे ही बिचौलियों को खदानें आवंटित की गई थीं, ताकि वे उन्हें आगे चलकर उद्योगपतियों को आसमान छूती क़ीमतों पर बेच सकें. अब यदि सरकार और बिचौलियों के बीच साठगांठ नहीं थी तो ऐसा क्यों किया गया? यह काम श्रीप्रकाश जायसवाल का है, लेकिन आज तक उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है. 2003 तक 40 ब्लॉक बांटे गए थे, जिनमें अब तक सिर्फ 24 ने उत्पादन शुरू किया है. तो बाक़ी 16 कंपनियों के लाइसेंस ख़ारिज क्यों नहीं किए गए? 2004 में 4 ब्लॉक बांटे गए थे, जिनमें आज तक उत्पादन शुरू नहीं हो पाया. 2005 में 22 ब्लॉक आवंटित किए गए, जिनमें आज तक केवल 2 ब्लॉकों में ही उत्पादन शुरू हो पाया है. इसी तरह 2006 में 52, 2007 में 51, 2008 में 22, 2009 में 16 और 2010 में एक ब्लॉक का आवंटन हुआ, लेकिन 18 जनवरी 2011 तक की रिपोर्ट के अनुसार, कोई भी ब्लॉक उत्पादन शुरू होने की अवस्था में नहीं है. पहले तो बिचौलियों को ब्लॉक मुफ्त दिए गए, जिसके लिए माइंस और मिनरल एक्ट में संशोधन को लोकसभा में चार साल तक रोके रखा गया. फिर जब इन बिचौलियों की खदानों में उत्पादन शुरू नहीं हुआ (क्योंकि ये उत्पादन के लिए आवंटित ही नहीं हुई थीं), तो भी इनके लाइसेंस रद्द नहीं किए गए. सरकार और बिचौलियों एवं फ़र्ज़ी कंपनियों के बीच क्या साठगांठ है, यह समझने के लिए रॉकेट साइंस पढ़ना ज़रूरी नहीं है. अगर ऐसा न होता तो आज 208 ब्लॉकों में से सिर्फ़ 26 में उत्पादन हो रहा हो, ऐसा न होता.

इस सरकार की कथनी और करनी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है. सरकार कहती है कि देश को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना आवश्यक है. देश में ऊर्जा की कमी है, इसलिए अधिक से अधिक कोयले का उत्पादन होना चाहिए. इसी उद्देश्य से कोयले का उत्पादन निजी क्षेत्र के लिए खोलना चाहिए, लेकिन इस सरकार ने विकास का नारा देकर देश की सबसे क़ीमती धरोहर बिचौलियों और अपने प्रिय उद्योगपतियों के नाम कर दी. ऐसा नहीं है कि सरकार के सामने सार्वजनिक नीलामी का मॉडल नहीं था और ऐसा भी नहीं कि सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं था. महाराष्ट्र के माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी इस प्रक्रिया के चलते कोल इंडिया से कुछ ब्लॉक मुफ्त ले लिए. ये ब्लॉक थे अगरझरी, वरोरा, मार्की, जामनी, अद्कुली और गारे पेलम आदि. बाद में कॉरपोरेशन ने उक्त ब्लॉक निजी खिलाड़ियों को बेच दिए, जिससे उसे 750 करोड़ रुपये का फ़ायदा हुआ. यह भी एक तरीक़ा था, जिससे सरकार इन ब्लॉकों को बेच सकती थी, लेकिन ब्लॉकों को तो मुफ्त ही बांट डाला गया. ऐसा भी नहीं है कि बिचौलियों के होने का सिर्फ कयास लगाया जा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र की एक कंपनी जिसका कोयले से दूर-दूर तक लेना-देना नहीं था, ने कोयले के एक आवंटित ब्लॉक को 500 करोड़ रुपये में बेचकर अंधा मुनाफ़ा कमाया. मतलब यह कि सरकार ने कोयले और खदानों को दलाल पथ बना दिया, जहां पर खदानें शेयर बन गईं, जिनकी ख़रीद-फरोख्त चलती रही और जनता की धरोहर का चीरहरण होता रहा.

प्रणब मुखर्जी ने आम आदमी का बजट पेश करने की बात कही, लेकिन उनका ब्रीफकेस खुला और निकला जनता विरोधी बजट. अगर इस जनता विरोधी बजट को भी देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र को एक लाख साठ हज़ार करोड़ रुपये आवंटित हुए. मूल ढांचे (इन्फ्रास्ट्रकचर) को दो लाख चौदह हज़ार करोड़, रक्षा मंत्रालय को एक लाख चौसठ हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किए गए. भारत का वित्तीय घाटा लगभग चार लाख बारह हज़ार करोड़ रुपये का है. टैक्स से होने वाली आमद नौ लाख बत्तीस हज़ार करोड़ रुपये है. 2011-12 के लिए कुल सरकारी ख़र्च बारह लाख सत्तावन हज़ार सात सौ उनतीस करोड़ रुपये है. अकेले यह कोयला घोटाला 26 लाख करोड़ का है. मतलब यह कि 2011-2012 में सरकार ने जितना ख़र्च देश के सभी क्षेत्रों के लिए नियत किया है, उसका लगभग दो गुना पैसा अकेले मुनाफाखोरों, दलालों और उद्योगपतियों को खैरात में दे दिया इस सरकार ने. मतलब यह कि आम जनता की तीन साल की कमाई पर लगा टैक्स अकेले इस घोटाले ने निगल लिया. मतलब यह कि इतने पैसों में हमारे देश की रक्षा व्यवस्था को आगामी 25 साल तक के लिए सुसज्जित किया जा सकता था. मतलब यह कि देश के मूल ढांचे को एक साल में ही चाक-चौबंद किया जा सकता था. सबसे बड़ी बात यह कि वैश्विक मंदी से उबरते समय हमारे देश का सारा क़र्ज़ (आंतरिक और बाह्य) चुकाया जा सकता था. विदेशी बैंकों में रखा काला धन आजकल देश का सिरदर्द बना हुआ है. बाहर देशों से अपना धन लाने से पहले इस कोयला घोटाले का धन वापस जनता के पास कैसे आएगा?

इस तरह हर साल मुफ्त बंटता रहा कोयला

Status Of Alloted Coal Blocks -Upto June 2010
Allotted by Ministry Of Coal, Government Of India

Year	Coal Blocks Allotteed(Nos)			Reserves (M Te)		
	Private	Government	Total	Private	Government	Total
1993	1	0	1	140.47	0.00	140.47
1994	1	0	1	22.5	0.00	22.5
1995	0	1	1	0	84.47	84.47
1996	4	2	6	259.34	410.71	670.05
1997			0	0	0.00	0.00
1998	4	0	4	494.77	0.00	494.77
1999	2	0	2	231.00	0.00	231.00
2000	1	0	1	156.00	0.00	156.00
2001	1	1	2	34.34	562.00	596.34
2002	1	0	1	92.30	0.00	92.30
2003	11	9	20	458.32	472.46	930.78
2004	1	5	6	7.00	2080.52	2087.52
2005	13	8	21	1376.14	1927.56	3303.70
2006	51	34	85	5469.86	12223.15	17693.01
2007	19	41	60	2871.77	8402.42	11274.19
2008	41	4	45	2820.46	609.99	3430.45
2009	32	2	34	6297.05	562.35	6859.40
2010	1	0	1	800.00	0.00	800.00
Total	184	107	291	21531.32	27335.63	48866.95
Cost		Rs	Millon	53828305	68339065	122167370.00
Estimated Total Valuation		Rs	Crores	5,382,830.50	6,833,906.50	12216737.00
Estimated Loss Of Government Government Revenue		Rs	Crores	2691415.25	3416953.25	6108368.5

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 3 अंक 7
दिल्ली, 25 अप्रैल-01 मई 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

विशेष संवाददाता
सरोज कुमार सिंह (बिहार)

प्रबंध संपादक (उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)
डॉ. सुनील कौशिक

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन व प्रसार +91 120 4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16+4+4+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

भारत का स्वतंत्रता आंदोलन देश के गांवों से ही निकल कर आया. गांधी का पूरा जीवन सर्वश्रेष्ठ आदर्शों के लिए संघर्ष की किताब है.

अन्ना हजारे न महात्मा गांधी हैं और न लोकनायक जय प्रकाश नारायण

अन्ना को अन्ना ही रहने दो

अन्ना हजारे के आंदोलन ने ऊंचाई देखी. जनता जीती, सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन अन्ना के आंदोलन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और कई भ्रांतियां पैदा हो रही हैं. कुछ लोग अन्ना की तुलना महात्मा गांधी और जय प्रकाश नारायण से करने लगे हैं. कई विश्लेषकों ने अन्ना के आंदोलन को जेपी आंदोलन बताया है. अन्ना हजारे क्या इस शताब्दी के गांधी हैं, क्या वह जेपी हैं या फिर अन्ना सिर्फ़ अन्ना हैं?

मनीष कुमार

अन्ना के आंदोलन के दौरान युवाओं को यह कहते पाया गया कि उन्होंने न तो जेपी को देखा और न ही गांधी को देखा, उनके लिए अन्ना हजारे ही गांधी और जय प्रकाश नारायण हैं. इसमें कोई शक़ नहीं है कि अन्ना हजारे ने शहरी युवाओं को जगाया है. आज के संदर्भ में यह एक अनोखी उपलब्धि है. जबसे देश में नव उदारवाद की नीतियां अपनाई गईं, तबसे पढ़े-लिखे युवा अपनी ही उलझन में उलझ गए हैं. आर्थिक नीति ने युवाओं को जीवन के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि वे देश और समाज से दूर होते जा रहे हैं. विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति से दूर चले गए हैं. शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाने तक सीमित हो गया है. ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव नहीं होते. राजनीतिक दलों की युवा शाखाएं तो हैं, लेकिन उन्हें राजनीति में बच्चा समझ कर मुख्य धारा से दूर रखा जाता है. यह एक प्रकार की साजिश है, जिसके तहत युवाओं को राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों से दूर रखा जाता है. देश की सरकार तो युवाओं को अफीम की गोली खिलाकर सुला देना चाहती है. युवाओं को भविष्य के लिए किस तरह तैयार करना है, सरकार के पास इस बारे में न तो कोई सोच है और न ही कोई योजना. अन्ना हजारे के आंदोलन ने यह सब बदल दिया. कई सालों बाद शहरी युवाओं ने युवा भारत का एक नया चेहरा पेश किया है. इसका समर्थन होना चाहिए. अब देखना यह है कि ये शहरी युवा कब तक जाग्रत अवस्था में रहते हैं. लोकपाल बिल तैयार हो जाएगा, संसद में पास भी हो जाएगा, लेकिन क्या भ्रष्टाचार देश से ख़त्म हो जाएगा? भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ यह लड़ाई लंबी है. हैरानी की बात यह है कि चार दिनों के आंदोलन को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि जैसे देश में कोई क्रांति हो गई.

कुछ लोग अन्ना हजारे की तुलना लोकनायक जय प्रकाश नारायण से करने लगे हैं. इन लोगों को लगता है कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर-मंतर में अन्ना हजारे ने लोगों को जमा किया, लोकपाल बिल के मुद्दे पर सरकार को झुकाया, उससे जेपी आंदोलन की याद ताज़ा हो गई. यह बात बिल्कुल सही है कि अन्ना उन शहरी युवाओं को सड़क पर उतारने में कामयाब हुए, जो अब तक सामाजिक और राजनीतिक विषयों को लेकर बेपरवाह थे. पिछले कुछ महीनों से लोग हर दिन एक नए घोटाले की ख़बर सुनकर चिंतित थे. जनता भ्रष्टाचार को लेकर नाराज़ थी. अन्ना हजारे को इस बात के लिए श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने इस आंदोलन को लोगों की नाराज़गी ज़ाहिर करने का एक ज़रिया बनाया. यह आंदोलन अगर बाबा रामदेव करते या फिर कोई और करता तो मीडिया के कारण उस आंदोलन को भी वैसा ही समर्थन मिलता, जैसा अन्ना हजारे को मिला. जहां तक बात अन्ना हजारे से जय प्रकाश नारायण की तुलना की है तो फ़र्क़ ज़मीन और आसमान का है. सबसे बड़ा अंतर विचारधारा और लक्ष्य का है. जय प्रकाश नारायण कोई साधारण नेता नहीं थे, वह एक राजनीतिक और सामाजिक विचारक थे. अन्ना विचारक नहीं, एक एक्टिविस्ट हैं. अन्ना हजारे का आंदोलन सिर्फ़ लोकपाल बिल में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी तक सीमित है. सरकार ने मांग पूरी कर दी तो आंदोलन भी ख़त्म हो गया. जबकि जय प्रकाश जी किसी एक मुद्दे को लेकर सरकार का विरोध नहीं कर रहे थे.

जय प्रकाश जी के आंदोलन का स्कोप बड़ा था. वह व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन कर रहे थे. उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था. अन्ना हजारे और जय प्रकाश नारायण में एक बड़ा अंतर यह है कि अन्ना ख़ुद इस आंदोलन के जनक थे. लोकपाल बिल की मांग पर वह ख़ुद अनशन पर बैठ गए. मीडिया ने जब इसे दिखाया तो समर्थन बढ़ने लगा, इंटरनेट के माध्यम से लोग जुड़ने लगे और आंदोलन बड़ा हो गया. जय प्रकाश जी ने स्वयं आंदोलन शुरू नहीं किया. छात्र आंदोलित थे, उन्हें लगा कि एक सर्वमान्य नेता की ज़रूरत है तो उन्होंने जेपी को आमंत्रित किया कि वह आएं और उनका नेतृत्व करें. उनके आते ही छात्र आंदोलन का चरित्र बदल गया और वह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया. जय प्रकाश नारायण ने इसलिए आंदोलन का नेतृत्व किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि सरकार ग़रीबों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ हो गई है. जय प्रकाश नारायण को शहरी युवाओं एवं छात्रों के साथ-साथ मज़दूरों, किसानों और ग्रामीणों का भी समर्थन मिला था. अन्ना हजारे के आंदोलन में सिर्फ़ शहरी युवाओं की हिस्सेदारी थी. उन्होंने जो मुद्दा उठाया, उसका सरोकार शहरी और पढ़ी-लिखी जनता से है. अन्ना पढ़े-लिखे शहरी युवाओं अथवा यूं कहें कि शिक्षित भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जय प्रकाश जी पढ़े-लिखे शहरी युवाओं के साथ-साथ मज़दूरों, किसानों और ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे थे. अन्ना के साथ शौकिया एक्टिविस्ट थे, वहीं जय प्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों में अनुभवी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपने-अपने संगठनों और विचारधाराओं को त्याग कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया. अन्ना ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बारे में एक बयान क्या दे दिया, आंदोलन में शामिल लोगों ने अन्ना के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए. अन्ना अपने समर्थकों के वैचारिक मतभेदों की दीवार गिराने में असफल रहे हैं. जय प्रकाश ने तो भूदान और सर्वोदय की बात की. देश के गांवों की रूपरेखा बदलने की ठानी थी. उन्होंने यह काम सिर्फ़ सार्वजनिक उन्माद के आधार पर नहीं किया था, बल्कि उनके पास एक विज़न था. उन्होंने गांधी और पश्चिम के आदर्शों को एक सूत्र में पिरो कर गांवों को आधुनिक तकनीक के साथ बदलने की कोशिश की. उन्होंने बिहार के नक्सलियों और चंबल के डाकुओं के बीच भी बहुत काम किया और उन्हीं की वजह से बड़ी संख्या में डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया. आज की तरह 1974 में भी महंगाई, बेरोज़गारी, खाद्य पदार्थों की भारी कमी और भ्रष्टाचार ने देश में उथल-पुथल मचा दी थी, लेकिन जेपी ने इन मुद्दों को अपना लक्ष्य नहीं बनाया. पटना में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह एक क्रांति है. हम यहां बस इसलिए नहीं आए हैं कि बस विधानसभा को स्थगित कर दिया जाए. आज हमें संपूर्ण क्रांति चाहिए.

जो लोग अन्ना हजारे की तुलना जय प्रकाश नारायण से करना चाहते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि विचारधारा, जनता का समर्थन, नेतृत्व, संगठन शक्ति और लक्ष्य किसी आंदोलन का आधार होता है. हक़ीक़त यह है कि इन पैमानों पर अन्ना हजारे और जय प्रकाश नारायण में कोई समानता ही नहीं है. नई पीढ़ी के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम नहीं देखा और न ही गांधी को देखा. जब अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया तो कई लोग यह कहने लगे कि अन्ना आज के युग के गांधी हैं. महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं. गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस थे. सुभाष चंद्र बोस को गांधी की वजह से कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा था. कांग्रेस से बाहर जाने के बाद ही उन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी. महात्मा गांधी की विचारधारा, राजनीतिक सोच, संगठन शक्ति, लक्ष्य और व्यक्तित्व के सामने देश के बड़े-बड़े इतिहासपुरुष और नेता बौने नज़र आते हैं. उनके आगे विरोधी भी नतमस्तक हो जाते थे. जवाहर लाल नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे महापुरुषों का उनसे कई विषयों पर मतभेद रहा, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया. अपने हर आंदोलन में गांधी ने देश के हर वर्ग को अपने साथ लिया. गांधी को सबसे अधिक भरोसा गांव की ग़रीब जनता पर था. गांधी गांव-गांव दौरा और पदयात्रा करते थे. वह गांव की जनता को समझाते थे कि अंग्रेज देश को लूट रहे हैं.

फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

जय प्रकाश जी के आंदोलन का स्कोप बड़ा था. वह व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन कर रहे थे. उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था. अन्ना हजारे और जय प्रकाश नारायण में एक बड़ा अंतर यह है कि अन्ना ख़ुद इस आंदोलन के जनक थे. लोकपाल बिल की मांग पर वह ख़ुद अनशन पर बैठ गए. मीडिया ने जब इसे दिखाया तो समर्थन बढ़ने लगा, इंटरनेट के माध्यम से लोग जुड़ने लगे और आंदोलन बड़ा हो गया. जय प्रकाश जी ने स्वयं आंदोलन शुरू नहीं किया.

भारत का स्वतंत्रता आंदोलन देश के गांवों से ही निकल कर आया. गांधी का पूरा जीवन सर्वश्रेष्ठ आदर्शों के लिए संघर्ष की किताब है. सबसे पहले गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक प्रवासी वक़ील के रूप में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया. 1915 में वापसी के बाद उन्होंने भारत में किसानों, कृषि मज़दूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एकजुट किया. 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद गांधी जी ने देश भर में ग़रीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों के विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता के निर्माण, आत्मनिर्भरता, छुआछूत के अंत के लिए बहुत से आंदोलन चलाए. इन सबके बीच विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाले स्वराज की प्राप्ति उनका प्रमुख लक्ष्य रहा. गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में दांडी मार्च और इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़कर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया. दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा. गांधी जी की विशेषता यह है कि वह सिर्फ़ एक आंदोलनकारी ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक विचारक थे. गांधी जी ने सबसे पहले समझा कि देश का अंग्रेजी तंत्र कैसा है, अंग्रेजी राज का आधार क्या है. गांधी जी ने समझा कि देश को बदलने का तरीक़ा किसी एक या दो मुद्दों पर अंग्रेजी सरकार को घेरना नहीं है. उन्होंने यह दिखाया कि सरकार किस तरीक़े से अपने आप में ही अवैध है, किस तरह सरकार भारतीय लोगों की न होकर ब्रिटेन के लोगों के फ़ायदे के लिए यहां राज कर रही है. यह समझने के बाद ही उन्होंने अनशन और असहयोग जैसे कारगर अस्त्र निकाले. गांधी जी यह मानते थे कि देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ सरकार की ही नहीं, बल्कि लोगों की भी समान ज़िम्मेदारी है. यही वजह है कि जातिगत हिंसा हो या धार्मिक हिंसा अथवा छुआछूत, इन सबसे निपटने के लिए उन्होंने जनांदोलन किया. वह हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि जब तक देश के लोगों की सोच और मानसिकता नहीं बदलेगी, क़ानून बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. यह बात समझनी होगी कि गांधी का जीवन संघर्ष की गाथा है. एक-दो आंदोलन करने से कोई गांधी नहीं होता. किसी मुद्दा विशेष पर आंदोलन करने से कोई गांधी नहीं होता. गांधी होने के लिए गांधी के आदर्शों के साथ-साथ गांधी जैसा विचारक बनना भी ज़रूरी है.

अन्ना हजारे ने देश के शहरी नौजवानों को आंदोलित करके अनोखा काम किया है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि आज देश में एक प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में लोगों का सहयोग लेना ज़रूरी होता है. अन्ना के आंदोलन में किसान नहीं थे, मज़दूर नहीं थे, ग़रीब नहीं थे. अन्ना के आंदोलन में अल्पसंख्यक भी नहीं थे. अन्ना ने बस कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं पर ही विश्वास किया है. सच्चाई यही है कि मीडिया और इंटरनेट ने इस आंदोलन का प्रचार-प्रसार करके शहरी युवाओं को सड़क पर ला खड़ा किया. गांधी जी और जय प्रकाश नारायण ने आम जनता को अपने आंदोलन में साथ लिया था. उनके साथ गांव और तहसील में संघर्ष कर रहे सामजिक कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, लेकिन अन्ना के आंदोलन में ऐसे लोगों की भारी कमी दिखाई पड़ी. जो सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना के साथ नज़र आए, वे किसी न किसी एनजीओ या फिर निज स्वार्थ के लिए आंदोलन करने वाले प्रोफेशनल थे. अन्ना के आंदोलन का एकमात्र एजेंडा लोकपाल बिल रहा, जो इस आंदोलन के लक्ष्य को बहुत ही सूक्ष्म बनाता था. अगर गांधी जी या जय प्रकाश ऐसे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते तो वे सरकार के साथ-साथ लोगों के व्यक्तित्व में भी बदलाव की बात करते. वे इस सवाल का जवाब ढूंढते कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ क़ानून होने के बावजूद देश गर्त में कैसे चला गया? गांधी जी और जेपी इस बात पर भी ज़ोर देते कि देश में क़ानून लागू करने वाले ही व्यवस्था को ख़राब करते हैं और अगर उनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा, उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी तो कल कोई भी लोकपाल बन जाए, वह भी अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है.

आम नेता और ऐतिहासिक नेता में एक फ़र्क़ होता है. गांधी और जय प्रकाश जैसे नेता का आंदोलन समग्र होता था. आंदोलन का वैचारिक आधार होता था और उन आंदोलनों में भविष्य के सवालों का जवाब भी होता था. यही वजह है कि गांधी और जय प्रकाश नारायण को लोग आंदोलन का नेतृत्व करने का आमंत्रण देते थे. राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में मोतिहारी आए और उन्होंने नील की खेती से त्रस्त किसानों को उनका अधिकार दिलाया. 1974 में बिहार में आंदोलन हुआ, लेकिन आंदोलन के लक्ष्य और प्रयोजन के विस्तार के लिए लोगों ने जेपी को आमंत्रित किया था. गांधी और जय प्रकाश जहां-जहां गए, जनसैलाब उनके साथ नज़र आया. अन्ना का विरोध बस देश के शहरी लोगों और विश्वविद्यालय के छात्रों तक ही सीमित रहा. देश के छात्रों में भी गांधी जी की ऐसी साख थी कि उन्होंने पढ़े-लिखे, उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाने का काम दिया और बख़ूबी कराया. लेकिन अन्ना के छात्र बस धरने पर बैठे टीवी पर भाषण दे रहे थे. उनमें से कितनों को अन्ना गांव जाने के लिए तैयार कर पाते, यह सोचनीय विषय है. अन्ना गांधी नहीं हैं, अन्ना जय प्रकाश नहीं हैं. अन्ना सिर्फ़ अन्ना हजारे हैं.

वैसे जितने कम समय में इस आंदोलन ने ऊंचाई हासिल की, उतने ही वक़्त में अन्ना हजारे का आंदोलन अब थमने भी लगा है. आंदोलन में दरार भी नज़र आने लगी है. जो लोग कल तक अन्ना हजारे का समर्थन कर रहे थे, अब अन्ना के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं. अन्ना हजारे ने मोदी के बारे में एक बयान क्या दिया, मेधा पाटेकर, अरुणा राय और मल्लिका साराभाई समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने अन्ना के विचारों और नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया. इस विरोध को नज़रअंदाज़ तो नहीं किया जा सकता. विचारधारा की शून्यता किसी भी आंदोलन को दिशाहीनता की स्थिति में पहुंचा देती है.

manish@chauthiduniya.com

भारतीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (शिक्षण संस्थाएं) को पिछली यूपीए सरकार ने 2004 में स्थापित किया था, जिसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुहैल एजाज़ सिद्दीकी को नियुक्त किया गया था.

अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

उच्चतम न्यायालय की ग्यारह सदस्य खंडपीठ ने टी एम ए पाई एवं पी ए ईनामदार की याचिकाओं पर संविधान की धारा 30 (1) के तहत निर्णय देते हुए अल्पसंख्यकों को पांच अधिकार दिए, जिसमें शिक्षण संस्थाओं में नियुक्ति, शुल्क निर्धारण, सोसाइटी का गठन, प्रवेश और अनुशासनहीन कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही आदि अधिकार शामिल हैं. इन सभी अधिकारों को पाने के लिए देश की प्रत्येक शिक्षण संस्था को संबंधित प्रदेश के हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ती है. आश्चर्यजनक बात यह है कि यदि संबंधित अदालत द्वारा किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था को इंटर कॉलेज संबंधी किसी मामले पर राहत दे दी जाती है तो उसे अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेज या जूनियर हाईस्कूल पर लागू नहीं माना जाता. परिणामस्वरूप एक ही प्रकार की राहत के लिए सभी शिक्षण संस्थाओं को उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है, जिससे उनका आर्थिक और मानसिक शोषण होता है. इसी प्रकार संविधान में प्राप्त शुल्क निर्धारण अधिकार का हाल इससे भी बदतर है. उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट विधायी अनुभाग–1, 735/सात–वि–1–02(क) 1–2006, 10 जुलाई 2006 उत्तर प्रदेश निजी व्यवसायिक शैक्षिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का नियतन अध्यादेश) में कहा गया है कि यह अध्यादेश अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त–ग़ैर सहायता प्राप्त निजी व्यवसायिक शैक्षिक संस्थाओं पर लागू होगा. इसी के साथ शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) इलाहाबाद द्वारा पत्रांक/डिग्री अर्थ–1/बीएड शुल्क/5612–6172/2009–10, 3 मार्च 2010 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें निजी क्षेत्र के संस्थानों में चल रहे बीएड पाठयक्रमों का शुल्क निर्धारण करना था. यह आदेश प्रदेश के समस्त स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों को संबोधित करते हुए जारी किया गया है, साथ ही लिख दिया गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर. हास्यास्पद स्थिति यह है कि सरकार खुद अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं का शुल्क निर्धारित नहीं करती और यदि संस्थाएं ख़ुद शुल्क तय कर लें तो संबंधित विश्वविद्यालय उसे मानते नहीं. इस पर संस्थाएं अदालत का सहारा लेकर शुल्क निर्धारण कराती हैं, जिससे समय और श्रम की बर्बादी होती है. फिर सरकार मुनाफ़ाखोरी और कुप्रबंधन का ठप्पा लगाकर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं का जमकर शोषण करती है. जबकि किसी भी संस्था या व्यक्ति को बिना दोष सिद्ध हुए दोषी नहीं ठहराया जा सकता. उच्चतम न्यायालय ने पी ए ईनामदार बनाम महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर निर्णय देते हुए स्पष्ट कहा है कि आप किसी नागरिक के अधिकारों पर इस शंका से रोक नहीं लगा सकते कि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा. यह कितना कड़वा सत्य है कि सब कुछ केंद्र और प्रदेश सरकार के सामने हो रहा है और हमारे प्रतिनिधि, अधिकारी एवं ख़ुद को अल्पसंख्यकों का मसीहा कहने वाले राजनीतिक दल मूकदर्शक बने बैठे हैं.

उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किए जाने हेतु मानकों के निर्धारण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियम/विनियम इस प्रकार के नहीं होने चाहिए कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार निष्प्रभावी हो जाएं. राज्य सरकार किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था का प्रबंधन अपने हाथ में नहीं लेगी, प्रबंध समिति के गठन में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और संस्था के प्रबंध तंत्र में अल्पसंख्यक समुदाय से बाहर के लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा. प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का आरक्षण मान्य नहीं होगा, यह संस्था का अधिकार है. इन संस्थाओं के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिलेंगे. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण का माध्यम संबंधित संस्था स्वयं तय करेगी, जिसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. इतना सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में सरकारी अफसरों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है. वे अल्पसंख्यक संस्थाओं का प्रबंधन अपने हाथों में लेकर अदालत के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विवाद की स्थिति में अल्पसंख्यक संस्था का प्रबंध तंत्र प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में अपनी समस्या का निपटारा करा सकता है, परंतु अधिकतर जनपदों में ज़िलाधिकारी और ज़िला विद्यालय निरीक्षक इन संस्थाओं पर क़ब्ज़ा कर लेते हैं, जिससे इनका अल्पसंख्यक चरित्र ख़तरे में पड़ जाता है.

भारतीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (शिक्षण संस्थाएं) को पिछली यूपीए सरकार ने 2004 में स्थापित किया था, जिसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुहैल एजाज़ सिद्दीकी को नियुक्त किया गया था. इस आयोग में नायाब अब्बासी गर्ल्स (पीजी) कॉलेज, अमरोहा (जेपी नगर) उत्तर प्रदेश ने दो याचिकाएं डालीं और दोनों ही ख़ारिज कर दी गईं. एक याचिका संविधान में मिले नियुक्ति के अधिकार से संबंधित थी, जिसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा घोषित शैक्षिक योग्यता के आधार पर किसी को भी प्रवक्ता, प्राचार्य अथवा लिपिकीय संवर्ग में नियुक्त कर सकती हैं, उन्हें विषय विशेषज्ञ नियुक्त करने की बाध्यता नहीं है, परंतु आयोग द्वारा एक बार भी इस याचिका की गंभीरता को नहीं समझा गया. एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली समेत सभी विश्वविद्यालयों ने यह नियम बना रखा है कि किसी विषय के प्रवक्ता के चयन हेतु पहले विश्वविद्यालय से विषय विशेषज्ञ नियुक्त कराएं, उसके बाद विश्वविद्यालय जाकर साक्षात्कार कराएं, तब उसका अनुमोदन प्राप्त होगा. क्या यह संविधान में मिले अधिकारों का खुला अपमान नहीं है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस याचिका पर जो निर्णय दिया, उसे प्रदेश के अधिकारियों ने मानने से इंकार कर दिया. इस पर उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा अनुभाग को एक दिसंबर, 2010 को एक कार्यालय ज्ञाप जारी करना पड़ा, जिसमें कहा गया कि दि नेशनल कमीशन फार माइनारिटी एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसके द्वारा निर्गत प्रमाणपत्रों–आदेशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है. ऐसी शिक्षण संस्थाओं को, जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया जा रहा है, उनके साथ अल्पसंख्यक संस्था की तरह व्यवहार किया जाए और आयोग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. इस आदेश की प्रति प्रदेश के प्रमुख सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग, शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा निदेशक (बेसिक), निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण और समस्त ज़िला विद्यालय निरीक्षकों एवं ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजी गई है. आदेश से एक बात साफ़ हो गई कि अफसरशाही के सामने आयोग का कोई महत्व नहीं है, इसीलिए सरकार को कार्यालय ज्ञाप जारी करने को विवश होना पड़ा. मज़ेदार बात यह है कि इस कार्यालय ज्ञाप में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को छोड़ दिया गया. यही नहीं, बीएड के 2008–09 सत्र में जब अधिक शुल्क लेने की सामान्य शिक़ायत हुई तो सरकार ने बीएड कॉलेजों को निशाना बना लिया था. इस पर

उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट आदेश दिया था कि प्रथम काउंसिलिंग के लिए जमा शुल्क वापस नहीं होगा और किसी अल्पसंख्यक संस्था का शुल्क संबंधित विश्वविद्यालय में जमा नहीं कराया जाएगा, परंतु इस आदेश के बाद भी अमरोहा (जेपी नगर) की तत्कालीन ज़िलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने 15 जून, 2009 को चार अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेजों एवं एक सामान्य डिग्री कॉलेज को नोटिस देकर फीस वापसी का आदेश जारी कर दिया. उन्हें बार–बार हाईकोर्ट के आदेश और संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का हवाला दिया गया, परंतु वह नहीं मानीं और उन्होंने संबंधित कॉलेजों में कैंप लगवा कर ज़बरन फीस वापसी कराई. जनपद के अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेजों ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की शरण ली, परंतु आयोग ने एक बार भी ज़िलाधिकारी को नोटिस देकर यह नहीं पूछा कि वह अदालत के आदेश के बावजूद हस्तक्षेप क्यों कर रही हैं. ऐसा नज़ारा पूरे उत्तर प्रदेश में देखा गया और फिर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की रक्षा के लिए डाली गई याचिका छह तारीख़ों के बाद निरस्त कर दी गई.

प्रदेश के पांच हज़ार मदरसों की आधुनिकीकरण योजना के लगभग बीस हज़ार शिक्षक पिछले ढाई साल से अपना वेतन मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला. इस संबंध में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आज तक कोई पत्र केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को नहीं लिखा गया कि उक्त बीस हज़ार शिक्षक बदहाल क्यों हैं. रंगनाथ मिश्र आयोग एवं सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों को लागू कराने के लिए आयोग ने आज तक कोई क़दम नहीं उठाया. पांच राज्यों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जा रहा है, परंतु इससे उनका भला होने वाला नहीं. ऑल इंडिया मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मुस्लिम रजा के नेतृत्व में हजारों शिक्षकों ने बीती 23 फरवरी को दिल्ली के जंतर–मंतर पर धरना दिया और ढाई वर्ष से रुके वेतन को दिलाने की मांग उठाई. अगले दिन यानी 24 फरवरी को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने धरनास्थल पर आकर आश्वासन दिया कि मार्च के अंत तक रुका हुआ वेतन दिला दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. तहफुजे मदारिस अरबिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सैय्यद जिल्ले मुजतबा ने भी दर्जनों ज्ञापन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (शिक्षण संस्थाएं) नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग को भेजे, परंतु कहीं से कोई राहत नहीं मिली.

डॉ. महताब अमरोहवी
feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किए जाने हेतु मानकों के निर्धारण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियम/विनियम इस प्रकार के नहीं होने चाहिए कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार निष्प्रभावी हो जाएं. राज्य सरकार किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था का प्रबंधन अपने हाथ में नहीं लेगी, प्रबंध समिति के गठन में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और संस्था के प्रबंध तंत्र में अल्पसंख्यक समुदाय से बाहर के लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा. प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का आरक्षण मान्य नहीं होगा, यह संस्था का अधिकार है.

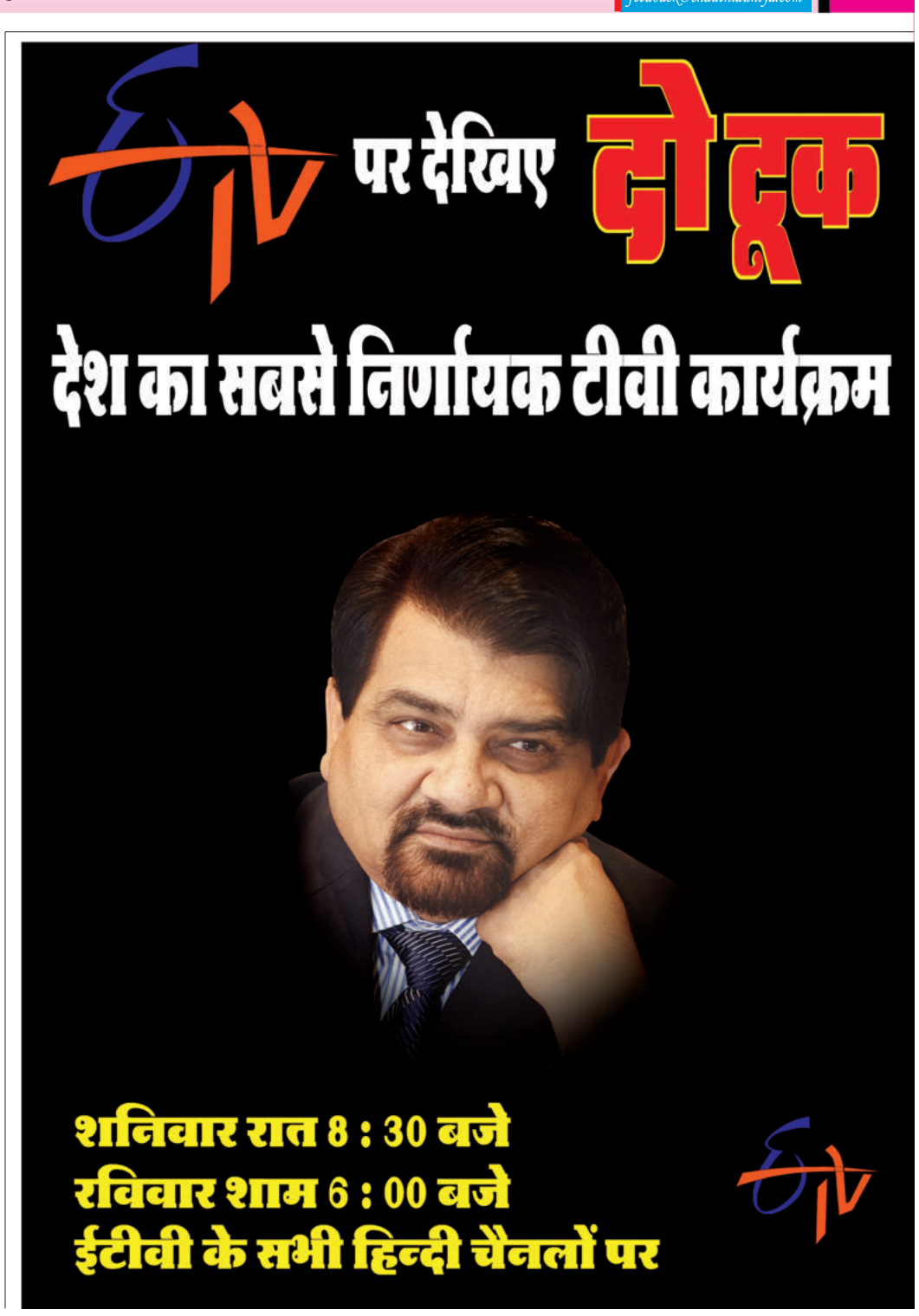

बंगाल के वोटरों को सोच-समझ कर फ़ैसले देने की आदत रही है. भूमि सुधार, खेती के मामले में विकास के अलावा वाममोर्चा के सत्ता में बने रहने का एक बड़ा कारण क्षेत्रवाद को खाद-पानी देना भी है.

पश्चिम बंगाल

अब तो फ़ैसले की घड़ी है

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

बिमल राय

विधानसभा चुनाव अब आख़िर मुक़ाम पर हैं. फ़ैसले की घड़ी क़रीब है. दो-तीन सालों के रुझानों और उम्मीद के आधार पर हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते रहे हैं, पर मामला सिर्फ़ 5-7 प्रतिशत वोटों के इधर-उधर होने का है. राष्ट्रीय और प्रांतीय नेताओं द्वारा धुआंधार प्रचार जारी है. तृणमूल के नए गढ़ यादवपुर से खड़े मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य खुली जीप से रैलियां निकाल रहे हैं तो ममता पदयात्राएं कर रही हैं. चार-चार किलोमीटर की पदयात्रा. बस्ती के घुरऊ एवं सोमारू जब अपनी दीदी के सामने आकर हाथ मिलाते हैं तो छतों से फूलों की बारिश होती है. बुद्धदेव की जीप तक छोटे लोगों के हाथ नहीं पहुंच पाते और वह चाहकर भी उनसे हाथ नहीं मिला पाते. एक के साथ पुलिस चलती है तो दूसरे को जनता के बीच रहने से डर नहीं लगता.

माकपा में व्यक्ति आधारित फोकस नहीं होता. उसकी नीतियां बोलती हैं, नेता नहीं. उसके पोस्टरों में नारे बोलते हैं, तरक़्क़ी की कहानियां बोलती हैं. तस्वीरें सर्वहारा की होती हैं, नेताओं या उम्मीदवारों की नहीं. जब तक ज्योति बसु राज करते रहे, इस नियम को उलटने-पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ी. जनसभाओं में ज़्यादातर लोग उन्हें देखने आते थे, पर अब माकपा की सभाओं के लिए ज़्यादातर लोग लाए जाते हैं. बसु जैसा प्रभामंडल बंगाल के किसी माकपा नेता के पास नहीं है. इसलिए बुद्धदेव एक खांटी भद्रलोक की तरह धूल-धक्कड़, उमस और पसीने की गंध वाले माहौल से दूर रहना पसंद करते रहे हैं, जबकि उन्हें सत्ता से बेदख़ल करने की कगार पर खड़ीं ममता के राजनीतिक जीवन का 70-80 फ़ीसदी हिस्सा गांवों और बस्तियों की गर्द भरी सड़कों-गलियों पर बीता है. हालात बदले हैं, इसलिए पहली बार मुख्यमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र की खाक छान रहे हैं.

इस राय को भी मानने वाले कम नहीं हैं कि अगर 35 साल में भी कोई सरकार नहीं बदलेगी तो कब बदलेगी. वामपंथियों के गढ़ केरल में भी हर पांच साल में सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहां के वोटरों की राजनीतिक जागरूकता की देश में मिसाल दी जाती है. यहां त्रिकोणीय मुक़ाबलों के बावजूद कभी त्रिशंकु विधानसभा की नौबत नहीं आई. यहां निर्दलियों के जीतने का प्रतिशत भी देश में शायद सबसे कम है. वोटर दो में से ही एक चुनते रहे हैं, तीसरे का समर्थन नहीं करते. इसीलिए बहुसंख्यक जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आने की योग्यता हासिल करने में विपक्ष को 35 साल लग गए. बंग विभाजन के बाद लगभग दो दशक तक बंगालियों ने कांग्रेस को ही चुना. बीच में 1967 में कांग्रेस से अलग होकर अजय मुखर्जी ने विप्लवी बांग्ला कांग्रेस बनाई और संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन हुआ, जिसमें ज्योति बसु उप मुख्यमंत्री बने. इसी दौरान बंगाल में नक्सली आंदोलन के तौर पर ख़ूनी राजनीति का प्रवेश हुआ. हिंसा और फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में सैकड़ों लोग मारे गए. 1972 में धांधली के आरोपों के बीच कांग्रेस सत्ता में लौटी. इस चुनाव में ज्योति बसु भी 40 हज़ार वोटों से हार गए थे. आख़िर में जनता लहर पर सवार होकर वामपंथी 1977 में आए और छा गए. उसके बाद के चुनावों में भी कांग्रेस को 30-40 प्रतिशत वोट मिलते रहे. ममता के कांग्रेस से अलग होने के बाद वोटों के बंटवारे से वाममोर्चा का काम थोड़ा आसान हो गया और वह चुनाव दर चुनाव जीत हासिल करता गया.

बंगाल के वोटरों को सोच-समझ कर फ़ैसले देने की आदत रही है. भूमि सुधार, खेती के मामले में विकास के अलावा वाममोर्चा के सत्ता में बने रहने का एक बड़ा कारण क्षेत्रवाद को खाद-पानी देना भी है. माकपा द्वारा ज़्यादातर समस्याओं के लिए केंद्र को ज़िम्मेदार ठहरा कर हमेशा तलवार ताने रहने, समर्थन के एवज में अपनी बात मनवाने, विचारधारा से समझौता न करने और राजनीति की मुख्य धारा से अलग अपनी लीक पर चलने जैसे हठी रुख़ से बंगाली मध्य वर्ग ख़ुश होता रहा. हालांकि माकपा की तलवार से उसके ही हाथ तब कट गए, जब उसे ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने का मौक़ा गंवाना पड़ा. माकपा को समझ में नहीं आया कि एक बंगाली के पीएम बनने से उसका उदार क्षेत्रवाद और ज़्यादा लोकप्रिय होता. यही टर्निंग प्वाइंट था, जब बंगालियों का माकपा से मोहभंग शुरू हो गया. बसु ने इसे ऐतिहासिक भूल कहकर संभलने का मौक़ा दिया, पर मार्क्सवादी सिद्धांतों वाली पोथी लेकर बैठे केंद्रीय नेताओं ने सबक लेने से इंकार कर दिया. ममता का इस क्षेत्रीय पहचान को हवा देने का घोषित एजेंडा नहीं है, पर वह मौक़ा मिलने पर भी राजनीतिक चतुराई दिखाने में नाकाम होती जा रही हैं. मिसाल के तौर पर चुनाव आयोग के उस विज्ञापन पर ममता ने आपत्ति जताई, जिसमें सौरभ गांगुली थे. उनका कहना था कि सौरभ कई माकपा नेताओं के क़रीबी रहे हैं. आख़िर में विवाद बढ़ता देख सौरभ ने ख़ुद अपने पैर पीछे हटा लिए. सौरभ अपने क्रिकेट जीवन में भले ही विवादास्पद रहे, पर बंगाल में उनकी लोकप्रियता को लेकर कोई संदेह नहीं है. यक़ीन न हो तो बीते 11 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और डेक्कन चार्जर्स के बीच हुए मैच के दौरान हज़ारों खाली पड़ी कुर्सियां इसकी गवाही दे सकती हैं. आईपीएल की किसी टीम ने सौरभ को नहीं ख़रीदा, इससे बंगालियों को गहरा सदमा पहुंचा है और वे एक तरह से नाइट राइडर्स को अपनी टीम मानने से इंकार कर चुके हैं. ऐसे संवेदनशील मौक़े पर ममता को अपने वोटरों पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए था. आख़िर सौरभ वोटरों से अपना क़ीमती वोट ज़रूर डालने की अपील करने वाले थे, न कि वाममोर्चा को जिताने की.

मज़बूत कैडर आधार वाले वाममोर्चा को पूरी तरह उखाड़ फेंकना इस बार भी संभव नहीं होगा. पिछले लोकसभा चुनावों के बाद से देश के राजनीतिक क्षितिज पर बहुत कुछ बदला है. अब बच्चा-बच्चा जान गया है कि भ से भालू नहीं, भ्रष्टाचार होता है. कुछ अनजान लोगों को अन्ना के अनशन ने पूरी तरह समझा दिया. वही कांग्रेस विपक्षी गठबंधन की एक घटक है. हालांकि ममता के गठबंधन का नेतृत्व करने के कारण बंगाल में इस फैक्टर का असर कम हो सकता है. उनके पास पूरे राज्य में फैला जनाधार भी है. एक समय था कि गांवों में उनका संगठन नहीं था, पर नंदीग्राम और सिंगूर में भूमि अधिग्रहण विवाद पैदा हुए तो वाममोर्चे का प्रशासकीय अनुभव फेल हो गया और इस बहाने ममता गांवों में पहुंच गईं. अपनी ग़लतियां सुधारने के लिए माकपा ने कुछ लुभावनी घोषणाओं के साथ माफी मांगने का सिलसिला शुरू किया, पर लगता है कि लोग उसे माफ करने के बदले ममता को एक मौक़ा देना चाहते हैं. माकपा नेता लोगों को समझा रहे हैं कि ममता उसी तरह राज्य चलाएंगी, जैसे रेल मंत्रालय चला रही हैं. विपक्ष के बंटने और आपस में लड़ने की वजह से लोगों के मन में शंका रही और वाममोर्चा हर पांच साल पर कामयाब होता रहा, पर अब सारे समीकरण सही जगह पर हैं. अपमान का घूंट पीकर भी कांग्रेस ने गठबंधन किया और घोटालों के इस राष्ट्रीय घटाटोप के बीच ख़ुश होने के लिए उसे बंगाल की जीत जैसा ही कुछ चाहिए. 17 जनवरी, 1996 को ममता ने बंगाल युवा कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से एक नारा दिया था–सीपीएम विरुद्धे नया सोपान, नतुन सकाल आनबे तूफ़ान. मंच से भाषण देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हाराव ने उन्हें बंगाल की वीरांगना की उपाधि दी थी. उस समय शायद इस वीरांगना को अंदाजा नहीं रहा होगा कि नई सुबह का इंतज़ार इतना लंबा होगा. यह समय की गति है कि जिस दल को छोड़कर उन्होंने माकपा के ख़िलाफ़ बिगुल बजाया, आज उसी की मदद से वह अपने अधूरे काम को अंजाम देने में लगी हैं.

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा दोनों खेमों को खटक रही

चुनावी सफलताओं की नज़र से देखें तो बंगाल की लाल मिट्टी कमल के लिए कभी उर्वर नहीं रही. जब-जब उसका तृणमूल से चुनावी तालमेल हुआ, सीटों के मामले में उसे प्रतीकात्मक कामयाबी हाथ लगी, पर पूरे राज्य में उसका जनाधार तैयार होने लगा. हालांकि विधानसभा में तो उसका खाता भी नहीं खुला है. तृणमूल बनने के कुछ महीनों बाद 1998 में हुए लोकसभा चुनावों में पहली बार भाजपा से उसका गठबंधन हुआ और तृणमूल को सात और भाजपा को एक सीट मिली. 16 सीटों पर तृणमूल और 11 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे. यहीं से भाजपा और तृणमूल दोनों का फैलाव शुरू हो गया. बाद में ममता को कभी पंजा तो कभी कमल पसंद आता रहा, पर भाजपा जब भी अकेली लड़ी, उसे 7 से 10 प्रतिशत तक वोट हासिल होते रहे. 2008 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में मिली कामयाबी से भाजपा का उत्साह बढ़ा. मालदा और वीरभूम में पार्टी ने दो ज़िला परिषदों, 184 पंचायत समितियों और 1271 ग्राम पंचायतों पर क़ब्ज़ा जमाया. बिना पार्टी प्रतीक के उसके प्रत्याशी 9 समितियों और 159 पंचायतों में जीते. 2003 के पंचायत चुनावों में पार्टी के पास केवल एक पंचायत समिति थी. 2009 के लोकसभा चुनावों में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थन से भाजपा ने दार्जिलिंग सीट जीती, पर वह कम से कम पांच सीटों पर वाममोर्चा के जीतने का कारण बनी. भाजपा को ख़ासकर सीमा से सटे इलाक़ों में अच्छी कामयाबी मिल रही है, जहां मूल बंगालियों से ज़्यादा संख्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की होती जा रही है. इस वजह से बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है, बेरोज़गारी के कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं. तस्करी और महिलाओं की ख़रीद-फरोख्त एक जमा-जमाया पेशा बन गया है. माकपा ने उन्हें राशनकार्ड देकर और मतदाता सूची में नाम दर्ज कर अपना वोट बैंक बढ़ाया, ममता भी उन्हें लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं. पिछले रेल बजट में ममता ने रेलवे लाइनों के किनारे बसे लोगों के लिए आवासन संस्थाओं की मदद से आशियाना बनाने का भी प्रावधान किया है. यह बांग्लादेशी घुसपैठियों के माकपाई वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है. रेलवे लाइन के किनारे बसे 90 फ़ीसदी लोग घुसपैठिए हैं. उन्हें घर देने से रेलवे को किस तरह फ़ायदा होगा, यह रेलवे के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? इस बार भाजपा सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और विधानसभा में खाता खोलने को लेकर आश्वस्त है. ख़ासकर उत्तर बंगाल में उसे तीन-चार सीटें जीतने का भरोसा है. इसके अलावा वह पूरे राज्य में वोट काटकर माकपा और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों के जीतने-हारने का कारण बन सकती है. इस वजह से दोनों ही खेमे उससे खार खाए हुए हैं. ममता अपनी सभाओं में भाजपा को बंगाल के एक और विभाजन के लिए प्रयासरत बता रही हैं तो माकपा अपना सांप्रदायिकता वाला राग अलाप रही है. भाजपा प्रत्याशियों के उत्पीड़न की भी ख़बरें आ रही हैं. मिसाल के तौर पर आसनसोल में एक हिंदी स्कूल के सामने हुई सड़क दुर्घटना से उत्तेजित छात्रों के पथराव के बाद आसनसोल उत्तर सीट से खड़े भाजपा प्रत्याशी मदन मोहन चौबे को पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी ज़बरदस्त पिटाई की. उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप है. चौबे को ग़ैर जमानती धाराओं में बंद करने से हिंदीभाषियों में ज़बरदस्त नाराज़गी है. हिंदीभाषी बहुल इस सीट पर चौबे के जीतने के आसार दिख रहे हैं और इससे ख़ासकर माकपा के लोग घबराए हुए हैं. डीएम ओंकार सिंह मीणा ने वारदात की मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया है. इस मामले पर आसनसोल कोर्ट परिसर में अनशन हुआ और मानवाधिकार आयोग तक भी आवाज़ पहुंची.

स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन (2008)

ज़िले	पंचायत समिति सीटें	ग्राम पंचायत सीटें
कूचबिहार	17	84
जलपाईगुड़ी	13	97
उत्तर दिनाजपुर	00	13
दक्षिण दिनाजपुर	03	41
मालदा	17	72
मुर्शिदाबाद	03	29
नदिया	33	225
उत्तर 24 परगना	25	143
दक्षिण 24 परगना	05	45
हावड़ा	08	89
हुगली	03	32
बर्दवान	12	121
वीरभूम	13	77
बांकुड़ा	08	66
पुरुलिया	03	26
पूर्व मिदनापुर	08	61
पश्चिमी मिदनापुर	11	46

मज़बूत कैडर आधार वाले वाममोर्चा को पूरी तरह उखाड़ फेंकना इस बार भी संभव नहीं होगा. पिछले लोकसभा चुनावों के बाद से देश के राजनीतिक क्षितिज पर बहुत कुछ बदला है. अब बच्चा-बच्चा जान गया है कि भ से भालू नहीं, भ्रष्टाचार होता है. कुछ अनजान लोगों को अन्ना के अनशन ने पूरी तरह समझा दिया. वही कांग्रेस विपक्षी गठबंधन की एक घटक है.

फोटो– *मंजय*

पश्चिम बंगाल में 34 सालों तक शासन में रहकर इतिहास रच चुकी वामपंथी पार्टियों को पहली बार अपने किले को बचाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है.

जनता बदलाव चाहती है

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

- 34 सालों में पश्चिम बंगाल में 42 हज़ार हत्याएं हुईं
- ये सारी हत्याएं राजनीतिक या अर्द्ध राजनीतिक थीं
- 34 सालों में 72 हज़ार औद्योगिक इकाइयां हुई बंद
- सिर्फ़ हावड़ा में 12 हज़ार कल-कारखाने हुए बंद

शशिशेखर

सत्ता की राजनीति में आरोप–प्रत्यारोप एक आम बात है, लेकिन जब समय चुनाव का हो तो इनकी अहमियत भी बढ़ जाती है. यही आरोप चुनावी मुद्दे तक बन जाते हैं. मसलन, पश्चिम बंगाल में चुनाव का शंखनाद हो चुका है और विपक्ष यानी तृणमूल कांग्रेस वामपंथी शासन की जमकर बखिया उधेड़ने में जुटी हुई है. तृणमूल कांग्रेस के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री सुल्तान अहमद चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि पिछले 34 सालों के वामपंथी शासन में पश्चिम बंगाल से विकास नाम की चीज ग़ायब हो गई, चाहे वह ग्रामीण विकास की बात हो, सामाजिक विकास की बात हो या फिर अल्पसंख्यक समाज के विकास की बात हो. अहमद कहते हैं कि पिछले 34 सालों में पश्चिम बंगाल में 42 हज़ार हत्याएं हुईं और ये सारी हत्याएं राजनीतिक या अर्द्ध राजनीतिक थीं.

बहरहाल, पश्चिम बंगाल में 34 सालों तक शासन में रहकर इतिहास रच चुकी वामपंथी पार्टियों को पहली बार अपने किले को बचाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है. नंदीग्राम और सिंगूर के बाद तृणमूल कांग्रेस पिछले 34 सालों का लेखा–जोखा लेकर जनता के बीच उतर रही है, लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं है. एक सच तृणमूल कांग्रेस के लिए भी कड़वा हो सकता है. यह सच यह सवाल पैदा करता है कि आख़िर तृणमूल कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल की जनता के लिए क्या एजेंडा है? अगर ममता बनर्जी सत्ता में आती हैं तो उनके पास विकास के लिए क्या एजेंडा है? इस मुद्दे पर सुल्तान अहमद कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो अगले सौ दिनों में शासन–प्रशासन की कार्यप्रणाली बदल देंगे और लोगों को अंतर दिखने लगेगा. रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफ़ारिशों पर तृणमूल कांग्रेस के रुख़ पर सवाल पूछे जाने पर अहमद कहते हैं कि हम इन सिफ़ारिशों को न सिर्फ़ पश्चिम बंगाल, बल्कि पूरे भारत में लागू कराने के पक्ष में हैं और हम जल्द ही इसके लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे. वह कहते हैं कि हमने इस मुद्दे को अपने घोषणापत्र में भी शामिल किया है. लेकिन केंद्र सरकार में एक मज़बूत सहयोगी के रूप में काम करने वाली तृणमूल कांग्रेस से क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि संसद में इस आयोग की रिपोर्ट को पेश हुए एक साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन अब तक उस पर चर्चा क्यों नहीं कराई गई. क्या इस सवाल का जवाब तृणमूल कांग्रेस को नहीं देना चाहिए?

> “पिछले 34 सालों के वामपंथी शासन में पश्चिम बंगाल से विकास नाम की चीज ग़ायब हो गई, चाहे वह ग्रामीण विकास की बात हो, सामाजिक विकास की बात हो या फिर अल्पसंख्यक समाज के विकास की बात. इन 34 सालों में पश्चिम बंगाल में 42 हज़ार हत्याएं हुईं और ये सारी हत्याएं राजनीतिक या अर्द्ध राजनीतिक थीं.”
>
> **सुल्तान अहमद,** *केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री*

दूसरा सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल के औद्योगीकरण का है. सुल्तान अहमद के मुताबिक़, वामपंथी पार्टियों के पिछले 34 सालों के शासन के दौरान राज्य में 72 हज़ार छोटी–बड़ी औद्योगिक इकाइयां बंद हो गईं. अकेले हावड़ा में 12 हज़ार कल–कारखाने बंद हो गए. मज़दूरों को न प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला और न वेतन. बेरोज़गारी दूर करने के नाम पर अहमद कहते हैं कि रेल मंत्री के तौर पर ममता बनर्जी रेलवे में लाखों रिक्तियों को भरने और बंगाल में रेल उद्योग स्थापित करने का काम कर रही हैं. लेकिन क्या सिर्फ़ सरकारी नौकरी बांटने भर से राज्य से बेरोज़गारी दूर हो जाएगी, यह सवाल तृणमूल के सामने तब तक बना रहेगा, जब तक वह पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए कोई ठोस और कारगर एजेंडा तैयार नहीं करती. इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि नक्सली तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, सुल्तान अहमद कहते हैं कि नक्सली भी आम आदमी हैं और वे अगर हमारे पक्ष में मतदान करना चाहते हैं तो हम उन्हें इससे रोक तो नहीं सकते.

> **रेल मंत्री के तौर पर ममता बनर्जी रेलवे में लाखों रिक्तियों को भरने और बंगाल में रेल उद्योग स्थापित करने का काम कर रही हैं. लेकिन क्या सिर्फ़ सरकारी नौकरी बांटने भर से राज्य से बेरोज़गारी दूर हो जाएगी, यह सवाल तृणमूल के सामने तब तक बना रहेगा, जब तक वह पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए कोई ठोस और कारगर एजेंडा तैयार नहीं करती. इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि नक्सली तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, सुल्तान अहमद कहते हैं कि नक्सली भी आम आदमी हैं और वे अगर हमारे पक्ष में मतदान करना चाहते हैं तो हम उन्हें इससे रोक तो नहीं सकते.**

एजेंडा तैयार नहीं करती. हालांकि ममता बनर्जी ने सत्ता मिलने के बाद अगले 200 दिनों का एजेंडा अभी से तय कर लिया है. इसमें कहा जा रहा है कि कोलकाता को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाया जाएगा, नए मेडिकल कॉलेज, मदरसे, मुस्लिम विश्वविद्यालय, हिंदी स्कूल और 300 नए आईआईटी खोले जाएंगे. दार्जिलिंग और जंगल महल के लिए विशेष विकास योजना बनाई जएगी. पर्यटन का विकास किया जाएगा. दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड और दीघा को गोवा बना दिया जाएगा. इसके अलावा लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए सिंगल विंडो भुगतान प्रणाली, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में रोज़गार पैदा करना, राज्य के कर ढांचे को तार्किक बनाना. सार्वजनिक क्षेत्र के बंद कारखानों को फिर चालू करना और नए कारखाने खोलना आदि काम किए जाएंगे. लेकिन क्या ममता बनर्जी के लिए यह सब कुछ कर पाना, वह भी महज़ 200 दिनों के भीतर संभव हो पाएगा? जिस तरीक़े से ममता और उनके समर्थकों ने नंदीग्राम और सिंगूर में विरोध प्रदर्शन किया, उससे क्या नए निवेशक पश्चिम बंगाल में निवेश करना चाहेंगे? सवाल यह भी है कि विकास के लिए निवेश और निवेश के लिए आधारभूत संरचना की ज़रूरत होगी, उसे पहले पूरा करने के लिए ममता बनर्जी को इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना पड़ेगा. क्या ये काम 200 दिनों के भीतर संभव हो पाएंगे? बिहार का उदाहरण सामने है. नीतीश कुमार को अपना पहला कार्यकाल सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में ही लग गया. ज़ाहिर है, सिर्फ़ घोषणाओं से काम नहीं चलने वाला. इसके अलावा पश्चिम बंगाल की एक और अहम समस्या है, नक्सलवाद. इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि नक्सली तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, सुल्तान अहमद कहते हैं कि नक्सली भी आम आदमी हैं और वे अगर हमारे पक्ष में मतदान करना चाहते हैं तो हम उन्हें इससे रोक तो नहीं सकते.

बहरहाल, तृणमूल कांग्रेस के जवाब और इस चुनाव के मद्देनज़र उसके रुख़ को देखकर यह साफ़ हो जाता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में लड़ाई आर–पार की है. यहां आरोप महज़ आरोप नहीं हैं, बल्कि चुनावी मुद्दे भी हैं. हालांकि इस सबके बीच जनता से जुड़े कुछ सवाल गौण दिख रहे हैं, लेकिन इस बार लड़ाई बदलाव की भी है. जैसा कि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने नारा भी दिया है कि बदला नहीं, हमें बदलाव चाहिए. इस नारे को मतदाताओं के बीच ले जाने के लिए तमाम हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. टेक्नोलॉजी क्षेत्र के दिग्गज सबीर भाटिया और आईआईएम के छात्र तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार को हाईटेक बनाने में कोई कोर–कसर बाक़ी नहीं रखना चाहते. ज़ाहिर है, तृणमूल कांग्रेस बदलाव के लिए जनता के साथ–साथ तकनीक पर भी भरोसा कर रही है. अगर जनता सचमुच बदलाव के मूड में है तो कुछ सवालों का जवाब पाने की जल्दबाज़ी उसे भी नहीं होगी.

shashishekhar@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... शीला और सुपर बग! ...धीर

केंद्रीय भूगर्भ जल सर्वेक्षण आयोग की रिपोर्ट को यदि सच मानें तो बुंदेलखंड में खेती के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है.

घटता पानी, बढ़ती प्यास

सुरेंद्र अग्निहोत्री

बेतवा, शहजाद, केन, धसान, मंदाकिनी, यमुना, जामनी, एवं सजनाम जैसी सदा नीरा नदियां होने के बावजूद पानी के लिए तरस रहे लोगों के दर्द को समझना बड़ा कठिन है. बुंदेलखंड में जल युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता. बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर हुई लूट ने हालात बदतर कर दिए हैं. 2003 में हुई वर्षा 1044.88 एमएम से घटते-घटते वर्ष 2009 तक 277.30 एमएम रह गई. दो हज़ार से अधिक चंदेलकालीन तालाबों में पानी नहीं है. ललितपुर जनपद में प्रदेश के सर्वाधिक कृत्रिम जलाशय होने के बावजूद यहां के चार ब्लॉक संकट की स्थिति में हैं. गर्मी ने अभी सिर्फ़ दस्तक दी है, फिर भी बुंदेलखंड में पानी के लिए त्राहि-त्राहि शुरू हो गई है. चित्रकूट के पाठा का पथरीला इलाक़ा हो या भरतकूप का खदानों वाला क्षेत्र या फिर मंदाकिनी के किनारे बसे तिरहार क्षेत्र के दर्जनों गांव, इस समय हर जगह की कहानी लगभग एक जैसी है. गांव तो गांव, शहर के हैंडपंप भी हांफ रहे हैं. एक हज़ार हैंडपंपों को रीबोर करने की स्वीकृति मिलने के बाद ज़िलाधिकारी इसे बड़ी राहत मान रहे हैं, वहीं जल निगम के अधिकारी अभी मंदाकिनी को बचाने की कार्ययोजना की शुरुआत नहीं कर सके हैं. चौदह हज़ार हैंडपंपों वाले इस ज़िले के अधिकांश हैंडपंप गंदा पानी दे रहे हैं. मानिकपुर के कई गांवों के लोगों ने तो जोहड़ों की शरण लेना शुरू कर दिया है.

नहरों की स्थिति

स्थान	संख्या	2006-07	2007-08
झांसी	160	81	19
जालौन	291	289	16
ललितपुर	119	95	00
बांदा	184	09	00
महोबा	97	36	00
हमीरपुर	100	28	00
चित्रकूट	88	22	00
म.प्र. के कुछ हिस्से	11	06	02
कुल	1050	566	37

जल निगम द्वारा आदर्श पेयजल योजना के अंतर्गत रामनगर, सिकरी, छीबों, पियरिया माफी, खटवारा, बिनौरा, अकबरपुर एवं लोढ़वारा में हैंडपंपों की हालत सरकारी काग़ज़ों में सही बताई जा रही है, लेकिन इन गांवों में शायद ही कहीं पर सही ढंग से पानी मिल रहा हो. कांशीराम शहरी आवासों में रहने वाले लगभग नौ सौ परिवार पानी की कमी से अक्सर जूझते हैं, पर अभी तक उनकी इस समस्या का निपटारा नहीं हो सका.

नोनार पेयजल योजना एवं बालापुर खालसा पेयजल योजना का हाल भी ख़राब है. सांसद आर के सिंह पटेल ने जब पथरा माफी, लोहदा एवं पिपरोदर की जलापूर्ति का हाल देखा तो वह अवाक रह गए. जलापूर्ति के लिए बनाई गईं टंकियां सफेद हाथी बनी खड़ी हैं. ग्रामीणों ने बताया कि चालीस में से कुल पांच हैंडपंप पानी दे रहे हैं. ग्राम लोहदा में पैंतालिस में से केवल पांच हैंडपंप पूरा पानी देते हैं, बाक़ी दो-चार बाल्टी ही पानी देते हैं. पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने जल निगम के

जल निगम द्वारा आदर्श पेयजल योजना के अंतर्गत रामनगर, सिकरी, छीबों, पियरिया माफी, खटवारा, बिनौरा, अकबरपुर एवं लोढ़वारा में हैंडपंपों की हालत सरकारी काग़ज़ों में सही बताई जा रही है, लेकिन इन गांवों में शायद ही कहीं पर सही ढंग से पानी मिल रहा हो.

अधीक्षण अभियंता समेत अनेक अधिकारियों को बंधक बना लिया, जिन्हें सांसद पटेल की पहल पर बड़ी मुश्किल से छुड़ाया जा सका. अधिशासी अभियंता जल संस्थान मनोज कुमार आर्या स्वीकारते हैं कि पिछले दिनों पानी उठाने का काम कुल 6 एमएलडी का हुआ, जिससे कई इलाक़ों को कम आपूर्ति की गई. ज़िलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को मंदाकिनी की सफाई और जल निगम को मशीन लगाकर युद्ध स्तर पर कचरा साफ कराने के आदेश दिए हैं. अगर जल्द ही मंदाकिनी को साफ न किया गया तो गर्मी में शहरवासियों को पानी की कमी झेलनी पड़ सकती है.

हमीरपुर के अपर ज़िलाधिकारी एच जी एस पुंडीर ने बताया कि जल संकट के मद्देनज़र यहां के हैंडपंपों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराया जाएगा और मौदहा बांध, लघु डाल नहर एवं नलकूपों से तालाबों को भर लिया जाएगा. 16,561 हैंडपंपों में से 797 हैंडपंप रिबोर की स्थिति में हैं. जल निगम हैंडपंपों की मरम्मत करा रहा है. ग्राम पंचायतों को भी ख़राब हैंडपंपों को ठीक करने का आदेश जारी हो चुका है. झांसी जनपद के सपरार बांध का जलस्तर लगातार घटने से मई माह से ही पेयजल आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो सकती है. सपरार बांध से मऊरानीपुर में पेयजल आपूर्ति की जाती है. मऊरानीपुर में बांध के पानी के अलावा ट्यूबवेल एवं कुएं आदि जल के स्रोत हैं, किंतु बड़ी आबादी बांध के पानी पर आश्रित है. बांध में इस समय लगभग 220 मिलियन घन फुट पानी बचा हुआ है. वहां से प्रतिदिन लगभग साढ़े तीन एमएलडी पानी की आपूर्ति की जा रही है. सपरार प्रखंड के अधिशासी अभियंता ए के सक्सेना

चित्रकूट धाम मंडल

कुल आबादी-34,06,449

पानी की स्थिति

स्थान	जरूरत	आपूर्ति
शहरी इलाक़े	83 एमएलडी	69 एमएलडी
ग्रामीण क्षेत्र	56 एमएलडी	48 एमएलडी

मुख्य जलस्रोत

बेतवा, यमुना, बागेन, केन, प्यस्वनी, मंदाकिनी, ओहनडेम, अर्जुन सागर, मदन सागर, बेलाताल, कबरई तालाब एवं ट्यूबवेल. इनमें अधिकांश सूख चुके हैं और कुछ सूखने की कगार पर हैं.

ख़र्च धनराशि

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 58 करोड़ रुपये आए, अभी तक एक पैसा ख़र्च नहीं. केंद्र से 4 करोड़ 63 लाख 92 हज़ार रुपये मिले, ख़र्च 4 करोड़ 62 लाख 78 हज़ार रुपये.

झांसी मंडल

कुल आबादी-47 लाख

पानी की स्थिति

स्थान	ज़रूरत	आपूर्ति
शहरी इलाक़े	203.26 एमएलडी	147.92 एमएलडी
ग्रामीण क्षेत्र	150 एमएलडी	110 एमएलडी

मुख्य जलस्रोत

माता टीला बांध, गोविंद सागर बांध, राजघाट बांध, सपरार बांध, हैंडपंप, कुएं, तालाब और नलकूप. सभी बांधों पर पानी घटा. तीस प्रतिशत से ज़्यादा हैंडपंप, तालाब और कुएं सूखे हैं.

ख़र्च धनराशि

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 11 करोड़ रुपये आए, जिसमें से 9.50 करोड़ ख़र्च हुए. केंद्र एवं राज्य से 98 करोड़ 40 लाख रुपये आए, ख़र्च हुए केवल 85 करोड़ 33 लाख रुपये.

का कहना है कि मऊरानीपुर में सुबह और शाम तीन-तीन घंटे जलापूर्ति की जाती है. प्रतिदिन खपत एवं भीषण गर्मी से वाष्पीकरण का औसत बढ़ने से बांध से अधिकतम 20 मई तक जलापूर्ति संभव है. उन्होंने बांध के घटते जलस्तर के मद्देनजर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता सुरेश चंद्र को पत्र लिखकर मऊरानीपुर की जलापूर्ति में कटौती करने के लिए कहा है. महोबा जनपद का वार्ड हवेली दरवाजा भीषण पेयजल संकट से जूझ रहा है. यहां के ऊंचाई वाले इलाक़ों में पूरे साल टैंकरों से जलापूर्ति होती है. गर्मी की शुरुआत होते ही पेयजल संकट गहरा गया है. स्थानीय निवासी विपिन तिवारी एवं आनंद द्विवेदी बताते हैं कि पानी के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है. आपूर्ति के लिए वार्ड में पाइप लाइन डालने की योजना लंबित है. जल निगम की लापरवाही से पाइप लाइन नहीं पड़ सकी. क़स्बा मुस्करा में ट्रांसफार्मर ख़राब होने से पेयजल के लिए हाहाकार मच गया. हैंडपंपों पर एक-एक बाल्टी पानी के लिए लंबी-लंबी लाइनें लग गईं. तीन दर्जन से अधिक गांव पूरी तरह से अंधेरे में डूबे हुए हैं. ललितपुर के मैदानी इलाक़ों के साथ-साथ पठारी इलाक़ों में भी पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है. मड़ावरा क्षेत्र की संजीवनी मानी जाने वाली नदियां सूखी पड़ी हैं.

मध्य प्रदेश के कुछ इलाक़ों में पानी बरस गया था, इस वजह से कुछ बांध भर गए थे. वहीं पठारी इलाक़ों की स्थिति पहले की तरह है. इन क्षेत्रों में जल संरक्षण के व्यापक इंतज़ाम किए गए थे, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण जल संकट बरक़रार है. पानी के भंडारण और जलस्तर बनाए रखने के लिए चेकडैम एवं बंधियों का निर्माण किया गया था, जो सूख चुके हैं. ऊंचाई पर मौजूद इस विकास खंड के कुर्रट गांव में पानी का भीषण संकट है. इस ग्राम पंचायत के मजरे कुर्रट, जैतूपुरा एवं लखंजर काफी उपेक्षित हैं. वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को धसान नदी पार करनी पड़ती है. वे सागर जनपद के गांव बराठा से रोजमर्रा की ज़रूरत का सामान ख़रीदते हैं. इस क्षेत्र के अन्य ग्रामों में भी पानी का संकट बना हुआ है. प्रदेश में 20 एकड़ भूमि में आवासीय कॉलोनी बनने पर एक एकड़ भूमि पर तालाब बनना अनिवार्य है, लेकिन नगर विकास और आवास विकास विभाग इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं. भूमिगत जल संग्रहण के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि का 25 प्रतिशत हिस्सा ज़िलाधिकारी ख़र्च करते हैं. उस राशि को जल संग्रहण की जगह ख़र्च किया जाना ज़रूरी है. भूगर्भ जल के गिरते स्तर को रोकने के लिए नगर विकास, आवास विकास, जल निगम, ग्राम्य विकास, वन विभाग एवं भूमि विकास विभाग भी तैयार नहीं हैं. भूगर्भ जल विभाग को बीते वर्ष 175 लाख रुपये पीजो मीटर स्थापना के लिए मिले हैं. बुंदेलखंड के पठारी जनपद बांदा, चित्रकूट, महोबा एवं ललितपुर के हालात बदतर होते जा रहे हैं. बांदा एवं चित्रकूट में जलस्तर बहुत तेज़ी से नीचे खिसक रहा है. कई विकास खंडों को तो डार्क एरिया घोषित कर दिया गया है.

केंद्रीय भूगर्भ जल सर्वेक्षण आयोग की रिपोर्ट को यदि सच मानें तो बुंदेलखंड में खेती के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है. 1950-60 के दशक में इस क्षेत्र में जीवांश की मात्रा .52 थी, जो आज .20 रह गई है. जीवांश की कमी से उत्पादन कम हो रहा है. मई-जून में तापमान 53 डिग्री तक हो जाने से खेतों में जीवांश ख़त्म हो जाता है. वनों की कटान के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है. केंद्रीय भूगर्भ जल सर्वेक्षण आयोग द्वारा के अनुसार, विकास खंड मऊ, मानिकपुर, कर्वी, पहाड़ी एवं रामनगर डार्क एरिया में आते हैं. नरैनी जसपुरा ग्रे एरिया (चेतावनी स्तर) पर हैं. इन क्षेत्रों में यदि रिचार्जिंग की व्यवस्था नहीं हुई तो धीरे-धीरे यहां भी जलस्तर मानक से नीचे खिसक जाएगा. बांदा मंडल के महुआ, कमासिन एवं बबेरू और झांसी मंडल के महरौनी, तालबेहट, बबीना, मऊरानीपुर एवं बड़ा गांव को व्हाइट एरिया माना गया है. ललितपुर जनपद के मडावरा एवं जखोरा ब्लॉक के अनेक ग्रामों का भी जलस्तर मानक से नीचे है. शासन द्वारा जलस्तर बनाए रखने के लिए कुछ चेकडैमो का निर्माण कराया गया था, लेकिन यथार्थ और सरकारी आंकड़ों में भारी अंतर है. स्वयंसेवी संस्था जन कल्याण समिति द्वारा पठारी क्षेत्रों में जलस्तर के संबंध में जुटाए गए आंकड़े भयावह तस्वीर प्रस्तुत करते हैं. मई और जून माह में बुंदेलखंड के 50 प्रतिशत हैंडपंप जलस्तर गिर जाने से बेकार हो जाते हैं. क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन आदित्य का कहना है कि राज्य सरकार के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है. प्रदेश सरकार के मंत्री दद्दू प्रसाद का गृह जनपद ही पानी के लिए तरस रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

फाटा फटेहाल है. आज़ादी के इतने सालों बाद भी वहां साक्षरता प्रतिशत सिर्फ़ 17.6 है. ख़ैबर पख्तूनख्वा में आज तक राज्य को स्वायत्त शासन नहीं दिया गया है.

अंग्रेजों ने असम में लाइन सिस्टम भी लागू किया, जिसके अंतर्गत विभिन्न धर्मावलंबियों को अलग-अलग इलाक़ों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया.

मेघनाद देसाई

जनता ही भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारेगी

जवाहर लाल नेहरू लोकतंत्र में विश्वास रखते थे और उनके पास एक लोकतांत्रिक देश में अनशन करने के लिए वक़्त नहीं था. उनका मानना था कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा अनशन करना ठीक नहीं है. 1953 में कांग्रेस कमेटी द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की अनुशंसा को जब सरकार ने ख़ारिज कर दिया था, तब पोट्टी श्रीरामुलु ने अनशन किया था. अनशन के दौरान श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई. नतीजतन, आंध्र प्रदेश की मांग माननी पड़ी और बाद में भाषाई आधार पर अन्य राज्य भी अस्तित्व में आए. 1971 के बाद इंदिरा गांधी ने लोकसभा में भारी बहुमत हासिल किया था, लेकिन महंगाई के ख़िलाफ़ जय प्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन और बाद में गुजरात एवं बिहार में भड़के जनांदोलन ने इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने के लिए मजबूर कर दिया. इसके बाद क्या हुआ, इतिहास के पन्नों में दर्ज है.

मैं इतिहास के पन्ने इसलिए उलट रहा हूं, क्योंकि अन्ना हजारे के अनशन से हमारी संसदीय संरचना पर कुछ सवाल उठे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं, जो अन्ना के अनशन से सहमत नहीं हैं. ऐसे लोगों का कहना है कि संसदीय लोकतंत्र में क़ानून बनाने का काम सांसदों का है, न कि सिविल सोसायटी के लोगों का. लेकिन ग़ौर करने वाली बात यह है कि सबसे अच्छा लोकतंत्र भी शून्यता की स्थिति में काम नहीं करता. यदि संसद अपना काम करने में असफल हो जाता है, जनता की मांगों को पूरा करने में असफल रहता है, तब जनता को यह अधिकार है कि वह अपनी राय प्रकट करे. इसके लिए एक ही रास्ता है कि लोग मार्च करें, प्रदर्शन करें, ताकि उनका विरोध दर्ज हो सके. भारत में विधायिका एक तरह से निष्क्रिय है और कार्यपालिका ने विधायिका के क्रियाकलापों पर नियंत्रण कर लिया है. वह विधायिका के एजेंडे को भी नियंत्रित करती है. लेकिन यदि प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि वह भ्रष्टाचार को रोक पाने में ख़ुद को इसलिए असमर्थ पाते हैं, क्योंकि यह गठबंधन का जमाना है और गठबंधन धर्म उन्हें कोई कड़ा क़दम उठाने से रोकता है, तो ऐसी स्थिति में जनता संसद से यह अपेक्षा नहीं कर सकती है कि वह अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से निभाएगी.

ज़ाहिर है, अन्ना हजारे और उनके अनुयायी आदर्शवादी हैं. वे कुछ असंभव मांग कर देते हैं. यूपीए-2 के लिए अन्ना हजारे का अनशन कुछ-कुछ पोट्टी श्रीरामुलु के अनशन जैसा है. यह दलील कि क़ानून बनाना सरकार का काम है और जनता को धैर्य रखना चाहिए, अब काम नहीं करेगी. मुख्य समस्या यह है कि अब लोगों का अपने चुने हुए प्रतिनिधियों में ही विश्वास घटने लगा है. यह जवाब कि मंत्रियों का समूह क़ानून बना देगा, कोई स्थायी समिति इस पर संसद में चर्चा करेगी, अब संतोषजनक नहीं लगता. पिछले साल नवंबर से लगातार सामने आ रहे घोटाले और संसद की ठप्प होती कार्यवाही ने पूरी राजनीतिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बहरहाल, हम लोग भारतीय लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में कुछ नए परिवर्तन के गवाह बन रहे हैं. यह आंदोलन एक वैकल्पिक ड्राफ्ट का प्रस्ताव दे रहा है. अगर इस तरह की आशा होती कि लोकसभा लोकपाल प्रस्ताव में संशोधन के सुझाव देगी, जिस पर बाद में बहस होगी और फिर उसे पास किया जाएगा (जैसा ब्रिटिश संसद में होता है), तब तो इस आंदोलन की मांग पर उपजे गुस्से को समझा जा सकता था, लेकिन भारतीय संसद इस तरह से काम नहीं करती. संसद के भीतर थोड़े-बहुत काम के अलावा सिर्फ़ शोरशराबा ही होता है.

भारत के लिए किसी विधेयक के मसौदे पर जनांदोलन खड़ा होना एक विचित्र घटना है. ज़ाहिर है, एक अकेले विधेयक से सारी समस्याओं का निपटारा नहीं हो जाएगा. अब तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार के पास सिर्फ़ आरटीआई ही था, लेकिन अब लोकपाल आने के बाद भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक और सशक्त हथियार मिल जाएगा. नई पीढ़ी ने राजनीतिक कार्यों से मिलने वाली एक नई तरह की ख़ुशी को ढूंढा है. इससे पहले मैंने इस तरह के आंदोलन अमेरिका में जन अधिकार अभियान, 1968 में फ्रांस, यूके और यूएस के छात्र आंदोलन के रूप में देखे हैं. बदलाव वैसी व्यवस्था पर दबाव डाल सकता है, जो मरणासन्न हो गई हो, जैसे कि भारतीय संसदीय व्यवस्था. ज़ाहिर है, एक स्मार्ट व्यवस्था ख़ुद में बदलाव लाकर फिर से जनता का विश्वास जीतेगी.

feedback@chauthiduniya.com

पाकिस्तान के अस्तित्व पर ख़तरा

लिस्बन में पिछले नवंबर में हुई नाटो देशों के मुखियाओं की बैठक में यह फ़ैसला लिया गया कि बाहरी देशों की सेनाएं अफ़ग़ानिस्तान से 2014 के अंत तक हटा ली जाएंगी और देश की सुरक्षा का ज़िम्मा वहीं के सुरक्षातंत्र के हाथों में सौंप दिया जाएगा. हम बाद में इसका विश्लेषण करेंगे. अभी तक हम यह नहीं सोच पाए हैं कि इस फ़ैसले का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा. इस बदलाव का क्या असर पड़ेगा? क्या होगा, जब अफ़ग़ानिस्तान नेशनल आर्मी को पख्तून क्षेत्र की सुरक्षा सौंप दी जाएगी, जबकि इस सेना में पहले से ही नस्लीय और जातीय कारणों से उथल-पुथल चल रही है. ब्लैकविल प्लान के अनुसार, पख्तून के चारों ओर उग्रवादी विरोधी दीवार खड़ी करने की बात हुई है. क्या इसकी वजह से कहीं पाकिस्तान का भविष्य ख़तरे में नहीं आ जाएगा? क्या पूरे दक्षिण एशिया में असुरक्षा नहीं फ़ैल जाएगी? फाटा में क्या होना चाहिए, क्या वहां पर सुधार नहीं होने चाहिए, ताकि आने वाले समय में बाहरी तत्व घुसपैठ न कर पाएं? ओसामा के विश्वसनीय सलाहकार अब्दुल्लाह अजाम ने हमेशा से फाटा को सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से देखा है, इसीलिए उन्होंने अपने फतवे में कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में तीन हज़ार किलोमीटर की सीमा बिल्कुल खुली है और यहां ऐसा कबीलाई प्रदेश है, जो किसी की राजनीतिक सत्ता के अधीन नहीं है. इसलिए यह क्षेत्र मुजाहिदीन के छुपने के लिए उपयुक्त है.

यह एक सच है कि उग्रवादियों और आतंकवादियों की गणित में फाटा आने वाले समय में एक सुरक्षित बेस की तरह देखा जाता है. फाटा में अगर सुधार लाए जाएं तो इस स्थिति से बचा जा सकता है, लेकिन क्या हम आज इस हालत में हैं कि वहां पर राजनीतिक सुधार लाए जा सकें? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इन सुधारों को अट्ठारहवें संशोधन में ही सम्मिलित किया गया होता? पाकिस्तान असल में खंडित मानसिकता का शिकार एक मरीज़ है. वह हमेशा सच्चाई को नकारने में लगा रहता है और भुलावे में जीना पसंद करता है. पाकिस्तान का गठन, बाकी कारणों को हटा दिया जाए तो, इसलिए किया गया था, ताकि अंग्रेजों को उत्तरी-दक्षिण एशिया में एक सेक्यूरिटी स्टेट मिल जाए, जिससे सोवियत रूस को घेरा जा सके और ब्रिटेन द्वारा ईरान और पर्शियन गल्फ के साथ तेल का कारोबार सुचारू रूप से चलता रहे. यही कारण है कि पाकिस्तान कभी भी जनता केंद्रित राष्ट्र नहीं बन पाया. पाकिस्तान की जनता हमेशा हाशिए पर रखी गई और उसकी तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया गया. बस कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां जनता ने विकास किया है, जैसे पंजाब और सिंध. फाटा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हमेशा से उपेक्षित रहा है, क्योंकि इन सबको बस सीमावर्ती सुरक्षा क्षेत्र समझा गया.

विदेशी सेनाओं की वापसी इस बात पर निर्भर करती है कि अफगानिस्तान अपनी सेनाओं को कितनी जल्दी तैयार कर पाता है. ताजा स्थिति यह है कि सेना में भगोड़ों और नदारद सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो सेना को चाक-चौबंद करने में कितना समय लगेगा, यह कहा नहीं जा सकता.

फाटा फटेहाल है. आज़ादी के इतने सालों बाद भी वहां साक्षरता प्रतिशत सिर्फ़ 17.6 है. खैबर पख्तूनख्वा में आज तक राज्य को स्वायत्त शासन नहीं दिया गया है. राज्य अपने लिए कोई क़ानून नहीं बना सकता, क्योंकि यह क्षेत्र भी फाटा की तरह अनुच्छेद 246 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के अधीन आता है. तो क्या यह सिर्फ़ एक संयोग है कि राष्ट्र के विरुद्ध जो आंदोलन होते हैं, वे उन्हीं क्षेत्रों में होते हैं, जो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आते हैं? बाक़ी दूसरे विषयों की तरह ही हमने सुधार लाने में बहुत देर लगा दी है और इस कारण भविष्य के लिए भी परेशानियां बढ़ गई हैं. क्या होगा जब 2014 में अफ़ग़ानिस्तान से विदेशी सेनाएं हटा ली जाएंगी? हालांकि यह वापसी कभी भी संपूर्ण नहीं होगी और एक आतंकवाद रोधी सेना हमेशा ही रहेगी.

विदेशी सेनाओं की वापसी इस बात पर निर्भर करती है कि अफगानिस्तान अपनी सेनाओं को कितनी जल्दी तैयार कर पाता है. ताज़ा स्थिति यह है कि सेना में भगोड़ों और नदारद सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो सेना को चाक-चौबंद करने में कितना समय लगेगा, यह कहा नहीं जा सकता. दूसरी ओर सेना में पख्तूनों को कम संख्या में लिया जा रहा है. याद रखने की बात है कि यह पख्तून दक्षिण और पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान से आते हैं, जो कि देश में अशांति का कारण है. इस वजह से उग्रवाद रोधी तंत्र बना पाना कठिन है. ब्लैकविल प्लान के मुताबिक़, तालिबान को दक्षिण और पूर्वी प्रांतों में ही रोकने के लिए अफ़ग़ानिस्तान को दो भागों में बांट देना चाहिए. एक होगा पख्तून क्षेत्र, जिसे मैगिनोट लाइन की तरह प्रयोग में लाया जाएगा, ताकि तालिबानी उत्तर की ओर न जा पाएं, लेकिन यह प्लान पाकिस्तान के पख्तून क्षेत्र की कोई बात नहीं करता है. ब्लैकविल को लगता है कि ऐसा करने से तालिबानीकरण की बीमारी को बाकी जगहों पर फैलने से रोका जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र को स्पेशल फ़ोर्स और ड्रोन हमलों से क़ाबू में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पाकिस्तान का पख्तून इलाक़ा अफ़ग़ान तालिबान के नियंत्रण में आ जाएगा और पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लग जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि इस विभाजन से पृथक पख्तून राज्य जैसा कुछ बन जाए. सबसे बड़ी बात यह है कि अशांत और असंतुलित पाकिस्तान कोई अच्छी ख़बर नहीं है.

ख़ालिद अज़ीज़
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेशावर के चेयरमैन हैं)

पाठकों की दुनिया

मजबूरी या आस्था?

लोग देश की अदालतों से न्याय की उम्मीद करते हैं, लेकिन अदालतों में कितना भ्रष्टाचार है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता. फिर भी आम आदमी न्याय की आस लिए वर्षों अदालतों की चौखटें चूमता रहता है. क्या यह उसकी मजबूरी है या भ्रष्ट लोकतंत्र में आस्था?

-मोहम्मद रफीक चौहान, एडवोकेट, ई-मेल से.

भावनाओं से खिलवाड़

21-27 मार्च के अंक में सही कहा गया है कि सच्चर कमेटी एवं रंगनाथ मिश्र कमीशन की सिफारिशें लागू होने से मुसलमानों को लाभ पहुंचता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मुस्लिम कांग्रेसी नेता कद के बड़े ज़रूर हैं, लेकिन वे मुसलमानों के हित में नहीं सोचते, सिर्फ़ उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं. नेता जब तक ईमानदार नहीं होगा, तब तक मुसलमानों का भला होने से रहा.

-आबिद मजीद इराकी, जहानाबाद, बिहार.

रामदेव का योगदान

यदि जन लोकपाल क़ानून बन जाता है तो उसके बाद अन्ना हज़ारे साहब इस बात के लिए आंदोलन करें कि जो जन प्रतिनिधि ईमानदारी और वफ़ादारी के साथ काम न करे तो उसे वापस बुलाने का अधिकार जनता को मिले. जन लोकपाल बिल आंदोलन की सफलता का श्रेय किसी एक शख्स को नहीं जाता, बल्कि इस अभियान में 90 प्रतिशत वे लोग शामिल हैं, जो पहले से बाबा रामदेव के भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हैं. इसलिए रामदेव के योगदान को भी याद रखना होगा.

-हरि ओम अग्रवाल, ई-मेल से.

सर्वश्रेष्ठ पत्र

युवाओं को जागना होगा

चौथी दुनिया का 4 अप्रैल-10 अप्रैल अंक पढ़ा. संपादकीय पढ़कर लगा कि अभी भी ऐसे अख़बार हैं, जो महज़ सत्ता के भोंपू नहीं हैं. मैं युवा हूं, पर युवाओं पर संपादक के प्रहार को सहर्ष स्वीकारता हूं. उनका यह कथन कि आज के युवा शायद अफ़ीम खाकर सो रहे हैं, एकदम ठीक है. देश के युवा एवं छात्र संगठन आज क्यों मौन हैं, जबकि वे गाहे-बगाहे क्रांति का बिगुल बजाने का दम भरते रहते हैं. आज छात्र संगठन अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं निभा रहे. वे सिर्फ़ अपने राजनीतिक आकाओं के हुक्म का पालन करते हैं. नौजवानों को आगे आना ही पड़ेगा. जिस तरह भीष्म पितामह को अधर्म का साथ देने का ज़िम्मेदार माना जाता है, क्योंकि उनका मौन अन्याय के साथ था, उसी तरह आज देश की स्थिति ख़राब होते हुए भी यदि युवाओं ने कुछ न किया तो देश के विनाश में उनका नाम भी काले अध्याय में जोड़ा जाएगा. युवाओं को आगे आना ही होगा, तभी यह देश बच पाएगा.

-अरुण सरोहा, हिंदी पत्रकारिता विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय.

नक़ली नोट, रिज़र्व बैंक और सरकार

मुख्य आलेख नकली नोट, रिज़र्व बैंक और सरकार पढ़ा. नकली नोटों के विषय में आपने जो रिपोर्ट प्रकाशित की, उसके लिए हार्दिक बधाई. कम से कम अब तो भारत सरकार को रामदेव द्वारा दी जा रही सलाह (करेंसी रिकॉल) पर फ़ौरन अमल करके राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर जनता को यह संदेश देना चाहिए कि वह अपने राजधर्म का पूर्ण निर्वाह कर रही है.

-राजा शर्मा, ई-मेल से.

अब जनता आगे आए

दौलत और सत्ता की हवस ने इंसान के अंदर की इंसानियत को ऐसी हालत में पहुंचा दिया है, जहां उसे इतना भी होश नहीं कि दौलत के गहने और सत्ता की पोशाक धारण करके जिस दरख्त की डाली को वह काट रहा है, वह उसी पर बैठा है और जिस ऊंचाई पर बैठा है, वह इसी दरख्त की देन है. अफ़सोस तो यह है कि देश के अधिकांश राजनेता इसी मानसिकता वाले हैं. अब आम जनता को ही पुरजोर आवाज़ से इंकलाब कहना होगा, भ्रष्टाचार के ख़ात्मे के लिए.

-अब्दुल रशीद, पत्रकार, सिंगरौली, मध्य प्रदेश.

राजकमल प्रकाशन समूह
राजकमल प्रकाशन राधाकृष्ण लोकभारती प्रकाशन
1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002 फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
राजकमल प्रकाशन समूह
की ओर से
लेखन विधा को सम्मान
'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपये की किताबें

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें
हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को पुरस्कृत किया जाएगा
पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
HELP LINE – 09311196029
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11, नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

लोकतंत्र के लिए लड़ाई ख़ुद लड़नी चाहिए

हम लोग या हिंदुस्तान के लोग भूल गए हैं कि पश्चिम एशिया में, लीबिया में लड़ाई चल रही है. यमन में जनता सड़कों पर है. सीरिया में लोग बशर अराफात का विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ जहां से यह कहानी शुरू हुई थी यानी मिस्र, वहां भी तहरीर चौक पर लोग डटे हुए हैं और उनका कहना है कि सेना को सत्ता छोड़नी चाहिए और चुनाव कराने चाहिए. पर इस सारी चीज़ में सबसे ज़्यादा नुक़सान किसका हुआ. सबसे ज़्यादा नुकसान लीबिया के लोगों का हुआ और लीबिया को लेकर ही हमें ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है. लीबिया के ऊपर अचानक हमला अमेरिका ने किया और उन दिनों ओबामा साहब, हिलेरी क्लिंटन और रॉबर्ट गेट्स, जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, लगातार टीवी पर आकर, आंखों में गुस्सा भरके, बाहें उठाकर ग़द्दाफ़ी को तबाह करने की धमकियां दे रहे थे और उनका कहना था कि ग़द्दाफ़ी के पास कोई समर्थन नहीं है. अमेरिका को लगता था कि उसके विमान बम बरसाएंगे, हमले करेंगे और ग़द्दाफ़ी या तो स्वयं सत्ता छोड़ देंगे या ग़द्दाफ़ी के लोग इस डर से कि अमेरिका सामने आ गया है और इराक़, अफ़ग़ानिस्तान को सामने रखते हुए उन पर दबाव डालेंगे कि वह सत्ता छोड़ दें, पर ऐसा हुआ नहीं. अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति के चुनाव हैं. ओबामा साहब दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं.

ओबामा साहब को लोगों ने कहा कि आपने जो क़दम उठाया है, वह ग़लत क़दम है. दरअसल, अमेरिका में ओबामा के ऊपर दो तरह के दबाव पड़े. एक तो यह कि यह ग़लत क़दम है, दूसरा उनसे कहा गया कि आप वहां पर अपनी सेना को इस लड़ाई में इनवॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक ज़मीन के ऊपर ग़द्दाफ़ी का शासन ख़त्म नहीं होता, तब तक आसमान से बम बरसाने से कुछ नहीं होगा. अमेरिका से ज़्यादा होशियार और स्मार्ट ग़द्दाफ़ी नज़र आए. उन्होंने अपनी सेना जहां-जहां लोगों के पास तैनात थी, वहां से हटा दी. उनकी वायुसेना की कमर तो पहले अमेरिकी बमवर्षकों, फिर नाटो की बमबारी ने तोड़ दी, लेकिन उनकी अपनी फौज उनके प्रति वफ़ादार बनी रही. लीबिया में 50 हज़ार की सेना है, जिसमें दस हज़ार वे लोग हैं जो लीबिया के लिए या कहें कि ग़द्दाफ़ी के लिए हर क्षण अपनी जान हथेली पर लिए घूमते रहते हैं. बुश ने जो लड़ाई इराक़ में लड़ी थी, उसको लोग भूले नहीं थे. और सीनियर बुश का एक किस्सा लोगों को याद है कि जब इराक़ ने कुवैत के ऊपर हमला किया था, तब सीनियर बुश ने कुवैत को छुड़ाने के लिए अपनी सेना भेज दी. कुवैत की आज़ादी के साथ ही दक्षिणी इराक़ में लोगों का विद्रोह सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ भड़क गया और लोगों को लगा कि अब अमेरिका साथ है तो हम क्यों न सद्दाम को सत्ता से बेदख़ल कर दें. पर सीनियर बुश ने कुवैत को आज़ाद कराने के साथ ही साथ उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया. नतीजा यह हुआ कि सद्दाम हुसैन ने दक्षिणी इराक़ के लोगों का बेरहमी से दमन किया. उसी तरह इस बार ओबामा साहब ने किया. जो विद्रोह ग़द्दाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ और जिस तरह से लोग, अनट्रेंड लोग, सिर्फ़ जोश से भरे हुए लोग ग़द्दाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हुए, दरअसल वे विभिन्न कबीलों के थे, जो क़द्दाफ़ कबीलों के ख़िलाफ़ खड़े रहे हैं, वे लोग आगे आए और उन्होंने पारंपरिक वाहनों के ऊपर हथियार लगाए. ऐसे हथियार, जो उन्हें आसानी से उपलब्ध हो गए, उससे उन्होंने लड़ाई लड़ने की कोशिश की. उन लोगों को लगा कि अमेरिकी बमवर्षक ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वे आसानी के साथ त्रिपोली पर क़ब्ज़ा कर लेंगे. पर त्रिपोली तो दूर, वे मेश्रातो और बेनगाजी पर भी क़ब्ज़ा नहीं कर पाए. वहां थोड़े दिनों के लिए क़ब्ज़ा हुआ, लेकिन बाद में ग़द्दाफ़ी की फौजों ने दोनों जगहों से विद्रोहियों को पीछे खदेड़ दिया.

इस बीच अमेरिका ने तय किया कि वह लीबिया से अपने हाथ खींच लेगा और उसने इस सारी लड़ाई को नाटो के ऊपर छोड़ दिया. दरअसल, नाटो का मतलब इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा फ्रांस का था. फ्रांस चाहता था कि वह दुनिया के भीतर अपनी ऐसी साख बनाए, जो साख आज तक उसकी थी नहीं. ब्रिटेन ने उसका साथ दिया. दोनों के दबाव में अमेरिका ने वहां बमबारी शुरू की, लेकिन जब अमेरिका ने देखा कि दोनों उसका साथ पूरी तौर पर नहीं दे रहे हैं और इस लड़ाई की वजह से ओबामा को अगले साल होने वाले चुनाव में फ़ायदे की जगह नुक़सान होगा तो वह पीछे हट गया. मैं यहां यह भी बता दूं कि अमेरिकियों के ऊपर 40 मिलियन डॉलर हर महीने का एक्स्ट्रा टैक्स लीबिया की लड़ाई की वजह से लगने की संभावना पैदा हो गई थी और इसका अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के ऊपर बहुत बुरा असर होता. हिलेरी क्लिंटन गईं और उन्होंने इस लड़ाई को नाटो को लड़ने के लिए दे दिया. ब्रिटेन और फ्रांस के लिए यह सुनहरा मौक़ा था कि वे वहां जाएं, गद्दाफी को हटाएं और वहां तेल की संपत्ति पर अपना क़ब्ज़ा कर लें. अमेरिका ने अपना हित बता दिया कि उसको लीबिया के तेल में कोई दिलचस्पी नहीं है. फ्रांस और ब्रिटेन को थी. मज़े की बात यह है कि एक तरफ बात चल रही थी और उसी समय लीबिया के विदेश मंत्री ग्रीस के ज़रिए धीरे से ब्रिटेन पहुंच गए. ब्रिटेन पहुंचते ही ऐसा लगा कि एक बड़ा क्रैक हुआ, लेकिन ग़द्दाफ़ी के ख़िलाफ़ वह क्रैक हुआ नहीं, बस मिसफायर होकर रह गया. नाटो की सेना ने हमले धीमे कर दिए और यह बहाना लिया कि वहां मौसम इतना ख़राब है कि हम हमले नहीं कर सकते.

ओबामा साहब को लोगों ने कहा कि आपने जो क़दम उठाया है, वह गलत कदम है. दरअसल, अमेरिका में ओबामा के ऊपर दो तरह के दबाव पड़े. एक तो यह कि यह ग़लत क़दम है, दूसरा उनसे कहा गया कि आप वहां पर अपनी सेना को इस लड़ाई में इनवॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक ज़मीन के ऊपर ग़द्दाफ़ी का शासन ख़त्म नहीं होता, तब तक आसमान से बम बरसाने से कुछ नहीं होगा. अमेरिका से ज़्यादा होशियार और स्मार्ट ग़द्दाफ़ी नज़र आए. उन्होंने अपनी सेना जहां-जहां लोगों के पास तैनात थी, वहां से हटा दी.

दरअसल, लीबिया में नाटो और अमेरिकन सेनाओं को पता चल गया कि सच्चाई उसके कहीं विपरीत है, जैसी उनके पास जानकारी थी. अगर कहें तो कह सकते हैं कि कोई ग्राउंड इन्फॉरमेशन इन फोर्सेज के पास थी ही नहीं. अब यहां पर सीआईए घुसा. सीआईए ने कमान संभाली इन्फॉरमेशन की, ट्रेनिंग देने की, ख़ासकर विद्रोहियों को, क्योंकि वे बिल्कुल अनट्रेंड थे. उनको हथियार चलाने ही नहीं आते थे. पांच बड़े जहाज भरकर अमेरिका से हथियार भेजे गए, लेकिन वे विद्रोहियों के किसी काम ही नहीं आए. उनको हथियारों की ट्रेनिंग देना सीआईए ने शुरू किया. और सीआईए ने सोचा कि वह इनमें कुछ ऐसे लोग तलाश लेगा, ग़द्दाफ़ी के आसपास के रिश्तेदारों में, जो उनकी हत्या कर सकें. इस सारी चीज में एक चीज कहीं ग़ायब हो गई और वह थी आज़ादी की बात.

ब्रिटेन और फ्रांस ने ग़द्दाफ़ी के साथ सुलह की कोशिशें तेज़ कर दीं. अमेरिका ने एक रोड मैप बनाया कि वह लीबिया को डिवाइड कर दे, बेनगाजी को राजधानी बनाकर विद्रोहियों के हाथ में सौंप दे. उधर सीरिया में, चूंकि वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद शिया हैं, वहां सुन्नियों ने उनके ख़िलाफ़ हंगामा शुरू किया. कांट्राडिक्शन यह है कि बशर अल असद और उनके रिश्तेदार, उनके बेटे, उनके भतीजे काउंटर टेररिज्म की लड़ाई में अमेरिका का साथ दे रहे हैं. यमन, जॉर्डन इन सब में लोग तो विरोध में हैं. यहां के शासक उनका सामना भी कर रहे हैं. और सबसे बुरी बात जो इस सारे दौर में हुई कि सऊदी अरब ने अपनी सेना बहरीन में भेज दी. सेना को बहरीन में भेज करके उसने वहां क़रीब 300 लोगों का कत्लेआम कर दिया, जो विरोध कर रहे थे. इस मसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में, अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन हुए, लेकिन उन प्रदर्शनों को न टेलीविज़न पर दिखाया गया और न अख़बारों में ख़बरें आईं.

अमेरिका में अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं. बाकी जगहों की ख़बरें आ रही हैं, लेकिन बहरीन को लेकर कोई ख़बर नहीं आ रही है. यह सारी स्थिति बताती है कि अगर आप अपनी आज़ादी के लिए अमेरिका के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं तो वह भरोसा पूरी तरह नहीं करना चाहिए. यद्यपि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र को अमेरिका अपना आविष्कार मानता है और दूसरे शब्दों में वह कहता है कि लोकतंत्र हमारा बच्चा है और वह चाहता है कि सारी दुनिया में लोकतंत्र रहे. लेकिन लोकतंत्र उसी तरह से रहे, जिसका फ़ायदा अमेरिका को हो. जिसका फ़ायदा अमेरिका को न हो, वहां लोकतंत्र रहे या न रहे, उससे अमेरिका को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता. सूडान में तीन लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, अमेरिका के माथे पर शिकन नहीं आई. सोमालिया में क़त्लेआम हो रहे हैं, अमेरिका के माथे पर कोई शिकन नहीं है. आएवरी कोस्ट में भी तीन लाख से ज़्यादा लोग मारे गए. संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के ख़िलाफ़ वहां पर राष्ट्रपति सत्ता में बने रहे पिछले कुछ महीने से, लेकिन अमेरिका के माथे पर कोई शिकन नहीं आई, क्योंकि अमेरिका का वहां कोई इंटरेस्ट नहीं था. वहां लोकतंत्र मरता रहा, लेकिन अमेरिका को चिंता नहीं हुई. लीबिया में, यमन में, सीरिया में, मिस्र में जनता का उभार आया. उस जनता के उभार को जितना समर्थन देना चाहिए था, उतना समर्थन अमेरिका ने नहीं दिया. लेकिन इन देशों के लोगों को लगा कि उन्हें अमेरिका से समर्थन मिलेगा और वे सड़क पर खड़े हो गए. बाक़ी जगहों पर लोग अभी पशोपेश में हैं कि वे क्या करें. लेकिन लीबिया में तो एक बड़े हिस्से के सामने अपनी जान गंवाने का और जान गंवाने के लिए तैयार रहने की धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है. ग़द्दाफ़ी ने कहा है कि बेनगाजी के लोगों को क़त्लेआम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बग़ावत की है. बेनगाजी के लिए लड़ने वाले लोग, जिनका बहाना सबसे पहले अमेरिका ने हमला करने के लिए लिया, उन्हें अमेरिका ने खुला छोड़ दिया. यह अफ़सोस की बात है कि हिंदुस्तान, ब्राज़ील, चीन और सबसे बड़ा अफ़्रीकी महासंघ, इन सब लोगों ने इस लड़ाई का विरोध किया और वह लड़ाई अभी भी वहां चल रही है. उससे भी बड़ा अफ़सोस कि हिंदुस्तान के अख़बारों में अब लीबिया या पश्चिमी एशिया की ख़बरें न के बराबर आ रही हैं. सारी दुनिया में लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाने वालों को अपनी जान देनी पड़ती है, इसका सबूत बहरीन, लीबिया, यमन, सीरिया हैं. इससे बड़ा सबूत क्या होगा? इसलिए अगर लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठानी है तो अपने दम पर उठानी चाहिए, किसी बाहर की शक्ति के भरोसे अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसे निराशा का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

राम पुनियानी

असम धरतीपुत्रों को बांटने की साज़िश

हाल में असम में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा और ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी जैसे पार्टी नेताओं ने जिस मुद्दे को जमकर उछाला, वह था बांग्लाभाषियों, विशेषकर मुसलमानों की असम में कथित घुसपैठ. सांप्रदायिक पार्टियां और संगठन यह झूठा प्रचार कर रहे हैं कि अधिकांश बांग्लाभाषी मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं. इस मिथक का सहारा लेकर उक्त पार्टियां एवं संगठन अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ घृणा फैलाने और हिंदुओं की भावनाएं भड़काने का अपना पुराना खेल खेल रहे हैं.

बंगाली मुसलमानों का मुद्दा समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाता रहा है. बंगाली मुसलमानों को, चाहे वे बांग्लादेश के निवासी हों या पश्चिम बंगाल के, देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा बताया जाता है. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, स्वामी असीमानंद एवं अभिनव भारत आदि द्वारा किए गए आतंकी हमलों के लिए इन्हें दोषी ठहराया जाता रहा है. इन हमलों का दोष बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के सिर मढ़ा जाता रहा और यह आरोप भी लगता रहा है कि भारत में रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमान इन संगठनों की मदद करते हैं. असम में बांग्लाभाषी मुसलमानों का मुद्दा उछाल कर उसके ज़रिए समाज का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का अभियान लंबे समय से चल रहा है. असम में बड़ी संख्या में मुसलमानों, विशेषकर बांग्लाभाषी मुसलमानों को डी (डाउटफुल अर्थात संदेहास्पद) मतदाता क़रार देकर उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया है. इन ग़रीब, असहाय लोगों पर यह ज़िम्मेदारी लाद दी गई है कि वे यह साबित करें कि वे भारत के वैध नागरिक हैं. भाजपा का यह आरोप है कि कांग्रेस बांग्लादेशी मुसलमानों को उन क्षेत्रों में बसा रही है, जहां से उसे कम वोट मिलते हैं. असम के नेल्ली में 1983 में मुसलमानों का क़त्लेआम हुआ था, जिसमें 5000 से ज़्यादा निर्दोष मुसलमान मारे गए थे. असम की एक जनजाति को भड़का कर यह क़त्लेआम कराया गया था. यह आरोप लगाया गया था कि बांग्लादेशी मुसलमानों ने वोट डालकर चुनाव परिणामों को प्रभावित किया. इस मुद्दे को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जो आरएसएस से नियंत्रित है, ने चुनावों में भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बांग्लाभाषी मुसलमानों का मसला काफी जटिल है और इसका इतिहास बहुत पुराना है. 1826 में असम पर क़ब्ज़ा करने के बाद तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय किया कि आसपास के अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के निवासियों को बहुत कम आबादी वाले असम में बसाया जाए. इसके लिए जनरोपण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत अविभाजित बंगाल के निवासियों को असम में बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा, ताकि बंगाल में कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सके. इस कार्यक्रम के तहत जो बांग्लाभाषी असम में बसाए गए, उनमें मुसलमानों की बड़ी संख्या थी. इन प्रवासियों ने असम में कृषि का विकास किया. वे बहुत मेहनती थे और असम के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया.

भारत के विभाजन के बाद असम, जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान का पड़ोसी बन गया था, से काफ़ी संख्या में हिंदू पलायन करके सीमा से दूर स्थित राज्यों में बस गए. पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा चलाए गए दमन चक्र से पीड़ित कई लोगों ने वहां से भागकर असम में शरण ली. इनमें अधिकांश हिंदू थे.

भारत के विभाजन के बाद असम, जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान का पड़ोसी बन गया था, से काफी संख्या में हिंदू पलायन करके सीमा से दूर स्थित राज्यों में बस गए. पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा चलाए गए दमन चक्र से पीड़ित कई लोगों ने वहां से भागकर असम में शरण ली. इनमें अधिकांश हिंदू थे. दूसरी ओर असम में सांप्रदायिक राजनीति के उदय से आतंकित होकर लगभग 6 लाख असमिया मुसलमानों ने बांग्लादेश को अपना नया घर बना लिया. बांग्लादेश के कुछ निवासी मुख्यत: रोज़ी की तलाश में भारत के अन्य शहरों में बस गए. मुंबई और दिल्ली में बांग्लादेशी मुसलमान प्रवासियों का हौव्वा खड़ा किया जाता रहा है. जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की सदस्यता वाली अनेक जन जांच समितियों ने मुंबई में बांग्लादेशी मुसलमानों के ख़तरे की तह में जाने की कोशिश की है. इनमें से एक जन जांच समिति, जिसमें शमा दलवई और इरफान इंजीनियर शामिल थे, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मुंबई में बांग्लादेशी मुसलमानों की आबादी 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं है. दावा यह किया जाता है कि मुंबई में तीन लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए निवास कर रहे हैं. मुंबई में रह रहे बांग्लादेशियों में से अधिकांश जरी का अत्यंत श्रमसाध्य काम करते हैं. उनकी महिलाएं बहुत कम वेतन पर घरों में काम करती हैं. वे बहुत बदहाली में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं. उनका लगभग पूरा समय दो जून की रोटी जुटाने में ख़र्च हो जाता है. उनके घर मुंबई के उपनगरों के बाहरी क्षेत्रों में स्थित गटरों और नालियों के नज़दीक बनाई गई कच्ची झोपड़ियां हैं. यही स्थिति अन्य महानगरों, विशेषकर दिल्ली में है. यहां भी सांप्रदायिक तत्वों ने इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ उठाने की भरपूर कोशिश की है.

बेहतर जीवन की तलाश में अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना, चाहे क़ानूनी हो या ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से, पूरी दुनिया में बहुत आम है. ग़रीब वर्ग तो यह करता ही है, अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग भी यही करता है. भारत में असंख्य नेपाली और तिब्बती प्रवासी रहते हैं. बड़ी संख्या में भारतीय युवक-युवतियां अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर एवं श्रीलंका आदि में बस गए हैं या काम कर रहे हैं. इन प्रवासियों का एक ही उद्देश्य है, ग़रीबी एवं बदहाली से मुक्ति या फिर अपने आर्थिक-सामाजिक स्तर का उन्नयन. इसी शुद्ध सामाजिक-आर्थिक परिघटना को सांप्रदायिक तत्व अपने हित साधन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. भारत के अन्य इलाक़ों की तरह असम में भी अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति पर अमल किया. उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बैर भाव उत्पन्न किया. उन्नीसवीं सदी में चलाए गए जनरोपण कार्यक्रम से असम के स्थानीय निवासियों का नाख़ुश होना स्वाभाविक था. अंग्रेजों के हिंदुओं एवं मुसलमानों को एक-दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काने से समस्या और बढ़ी.

अंग्रेजों ने असम में लाइन सिस्टम भी लागू किया, जिसके अंतर्गत विभिन्न धर्मावलंबियों को अलग-अलग इलाक़ों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया. इससे यह समस्या और गंभीर हो गई. एक प्राकृतिक घटनाक्रम भी असम में तनाव को बढ़ा रहा है. विशाल ब्रह्मपुत्र नदी की धारा की दिशा बदलती रहती है और इस कारण उसके तट पर रहने वालों को अपना घर-बार छोड़कर अन्यत्र शरण लेनी पड़ती है. इन विस्थापितों में से अधिकांश ग़रीब होते हैं और उन पर बांग्लादेशी घुसपैठिए का लेबिल चस्पा कर दिया जाता है. असम की सांप्रदायिक स्थिति पर तुरंत ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है. डी मतदाता के मुद्दे के कारण भी वहां व्यापक जनाक्रोश है. असम एक अत्यंत ग़रीब राज्य है और उसे विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत है. ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक परिघटनाओं से जनित जनाक्रोश का कुछ तत्व राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं. असम के सभी निवासियों के बीच प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयास होने चाहिए. सांप्रदायिक तत्वों के दुष्प्रचार का डटकर मुक़ाबला करके ही हम राज्य में व्याप्त सामाजिक अलगाव और विभाजन के भाव को दूर कर सकते हैं. यही असम की प्रगति की राह को प्रशस्त करेगा और वहां हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अंकुश लगाएगा.

(लेखक आईआईटी मुंबई के पूर्व प्राध्यापक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

हम किसी विदेशी व्यक्ति से बात करते समय भी उसके जैसा बोलने का प्रयत्न करने लगते हैं.

सूचना का अधिकार — जानने का अधिकार जीने का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

आरटीआई : भ्रांतियां और निवारण

फाइल नोटिंग सार्वजनिक अधिकारियों को ईमानदार सलाह देने से रोकेगा?

यह ग़लत है. इसके विपरीत हर अधिकारी को अब यह पता होगा कि जो कुछ भी वह लिखता है, वह जन समीक्षा का विषय हो सकता है. यह उस पर जनहित में उत्तम लिखने का दबाव बनाएगा. कुछ ईमानदार नौकरशाहों ने अलग से स्वीकारा है कि आरटीआई ने उनके राजनीतिक एवं अन्य प्रभावों को दरकिनार करने में बहुत सहायता की है. अब अधिकारी सीधे तौर पर कहते हैं कि यदि उन्होंने कुछ ग़लत किया तो उनका उस समय पर्दाफाश हो जाएगा, यदि किसी ने उसी सूचना के बारे में पूछ लिया. इसलिए अधिकारियों ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया है कि वरिष्ठ अधिकारी लिखित में निर्देश दें.

सरकारी रिकॉर्ड्स सही रूप में व्यवस्थित नहीं हैं

आरटीआई की वजह से सरकारी व्यवस्था पर अब रिकॉर्ड्स सही आकार और स्वरूप में रखने का दबाव बनेगा, अन्यथा अधिकारी को आरटीआई क़ानून के तहत दंड भुगतना होगा.

लंबी-चौड़ी सूचना मांगने वाले आवेदन को ख़ारिज किया जाना चाहिए?

बिल्कुल नहीं. यदि कोई एक लाख पृष्ठों की जानकारी चाहता है तो वह ऐसा तभी करेगा, जब सचमुच इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके लिए उसे 2 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. यह अपने आप में हतोत्साहित करने वाली बात है. इसलिए इस कारण अर्जियां रद्द नहीं होनी चाहिए कि लोग केवल ख़ुद से संबंधित सूचना ही मांगें, न कि सरकारी कामकाज से जुड़ी सूचना. आरटीआई अधिनियम का अनुच्छेद 6 (2) स्पष्ट कहता है कि प्रार्थी से यह नहीं पूछा जा सकता कि वह क्यों कोई जानकारी मांग रहा है. इसलिए दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति कोई भी सूचना मांग सकता है, चाहे वह तमिलनाडु की हो.

सूचना प्राप्ति के पश्चात मुझे क्या करना चाहिए?

इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता. यह इस बात पर निर्भर होगा कि आपने किस प्रकार की सूचना की मांग की है और आपका मक़सद क्या है. बहुत से मामलों में केवल सूचना मांगने भर से ही आपका मक़सद हल हो जाता है. उदाहरण के लिए अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी मांगने भर से ही आपका पासपोर्ट अथवा राशनकार्ड आपको मिल जाता है. बहुत से मामलों में सड़कों की मरम्मत पर पिछले कुछ महीनों में ख़र्च हुए पैसों का हिसाब मांगते ही सड़क की मरम्मत हो गई. इसलिए सूचना की मांग करना और सरकार से प्रश्न पूछना स्वयं एक महत्वपूर्ण क़दम है, लेकिन अगर आपने सूचना के अधिकार का उपयोग करके भ्रष्टाचार और घपलों को उजागर किया है तो आप सतर्कता विभाग एवं सीबीआई में सबूत के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं अथवा एफआईआर दर्ज करा सकते हैं.

सूचना मांगने और इसके माध्यम से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वालों को परेशान किए जाने की भी आशंका है?

हां. कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें सूचना मांगने वालों को शारीरिक रूप से नुक़सान पहुंचाने का प्रयास किया गया.

ऐसा तब किया जाता है, जब सूचना मांगने से बड़े स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा होने वाला हो. लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हर आवेदक को ऐसी धमकी का सामना करना पड़ेगा. सामान्यत: अपनी शिकायत की स्थिति जानने या फिर किसी दैनिक मामले के बारे में जानने के लिए आवेदन करने पर ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है. ऐसा उन मामलों में हो सकता है, जिनकी सूचना मांगने से नौकरशाहों और ठेकेदारों के बीच साठगांठ का पर्दाफाश हो सकता है या फिर किसी माफ़िया के गठजोड़ के बारे में पता चल सकता है.

सूचना के लिए आवेदनों का ढेर लग जाने से सामान्य सरकारी कामकाज प्रभावित नहीं होगा?

आवेदन जमा करने की कार्यवाही में बहुत समय, ऊर्जा और कई तरह के संसाधन ख़र्च होते हैं. जब तक किसी को वाकई सूचना की ज़रूरत न हो, तब तक वह आवेदन नहीं करता. आइए, कुछ आंकड़ों पर गौर करें. दिल्ली में 60 से ज़्यादा महीनों में 120 विभागों में 14,000 आवेदन किए गए. इसका मतलब हर महीने हर विभाग में औसत 2 से भी कम आवेदन. क्या ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार के पास आवेदनों के ढेर लग गए होंगे.

लोगों को बेतुके आवेदन करने से कैसे रोका जा सकता है?

कोई भी आवेदन बेतुका नहीं होता. किसी के लिए पानी का कनेक्शन उसके लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकता है, पर अधिकारी इसे बेतुका मान सकते हैं. नौकरशाही में मौजूद स्वार्थी तत्वों की ओर से बेतुके आवेदन का प्रश्न उठाया गया है. सूचना का अधिकार अधिनियम किसी भी आवेदन को निरर्थक मानकर अस्वीकृत करने का अधिकार नहीं देता. नौकरशाहों का एक वर्ग चाहता है कि लोक सूचना अधिकारी को यह अधिकार दिया जाए कि यदि वह आवेदन को बेतुका समझे तो उसे अस्वीकार कर दे. यदि ऐसा होता है तो हर लोक सूचना अधिकारी हर आवेदन को बेतुका बताकर अस्वीकार कर देगा. यह अधिनियम के लिए बहुत ख़राब स्थिति होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

नकलची हार्मोन

इस बात से तो सभी वाक़िफ़ होंगे कि दुनिया नकलचियों से भरी पड़ी है. कोई किसी का सामान चुराता है तो कोई किसी का आइडिया. इसके अलावा क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति से बात करते समय या उसके तुरंत बाद आप अनजाने में उसके जैसा ही बोलने का प्रयत्न करने लगे हों? ऐसा सब लोगों के साथ होता है और इसके लिए हमारे जीन को ज़िम्मेदार माना जा सकता है. इंसानों के दिमाग़ के अंदर दूसरों से मित्रता स्थापित करने का नैसर्गिक गुण विद्यमान होता है. हम जाने-अनजाने लोगों से बात करते समय उसकी वाक प्रणाली की नकल करने लगते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता. एटेंशन, पर्सेपशन एंड साइकोफिजिक्स जर्नल में छपी रिपोर्ट के अनुसार, हमारे अंदर नकल करने की नैसर्गिक क्षमता मौजूद है, जो हमें दूसरों के साथ मित्रता स्थापित करने में मदद करती है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के अनुसार, हमारा अवचेतन मन सामने वाले व्यक्ति के हाव-भाव, उसके बोलने एवं खड़े रहने के तरीक़ों, बोलने की गति और उसमें लगने वाले समय आदि की भी नकल करने लगता है. शोधकर्ताओं के अनुसार, हम किसी विदेशी व्यक्ति से बात करते समय भी उसके जैसा बोलने का प्रयत्न करने लगते हैं. ऐसा हमारे अवचेतन मन की वजह से होता है और हमें इसका एहसास नहीं हो पाता, परंतु इससे अमूमन क्षोभजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है. यही वजह है कि किसी विदेशी स्थल पर लंबे काल तक रहने से हम वहां के मूल लोगों की तरह बोलने लगने हैं. न केवल हमें वहां की भाषा समझ में आने लगती है, बल्कि उन लोगों की तरह शब्दों के उतार-चढ़ाव पर भी हमारी पकड़ बन जाती है.

वीडियो गेम और हिंसा

बच्चों की अब तक जिन हिंसक मामलों में भागीदारी पाई गई है, उनके कारणों को लेकर हमेशा शोध होता रहा है. सवाल यह भी उठता रहा है कि क्या कंप्यूटर पर हिंसक खेल खेलने का असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है? हाल में किए गए एक सर्वे से इस बात की पुष्टि होती है कि हिंसक खेल हमारे व्यवहार पर असर डालते हैं. इस सर्वे से और भी कई चौंकाने वाले नतीजे प्राप्त हुए हैं. ओहियो स्टेट और मिशिगन यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए सर्वे के नतीजों के अनुसार, हिंसक खेलों का असर खेल खेलने के 24 घंटे बाद भी रहता है. इस सर्वे के लिए शोधकर्ताओं ने कुछ स्वयंसेवकों की सहायता ली और उन्हें 20 मिनट तक हिंसक खेल जैसे कि मोर्टल कोम्बेट खेलने को कहा या फिर गिटार हीरो जैसा अहिंसक खेल. इसके बाद हिंसक खेल खेलने वाले आधे खिलाड़ियों को कहा गया कि उन्हें कल भी यही खेल खेलना है और उन्हें मन ही मन आज से अच्छा खेल दिखाने की तैयारी करनी है. दूसरे दिन शोधकर्ताओं की टीम ने सभी स्वयंसेवकों की आक्रामकता की परीक्षा ली. इस समीक्षा से पता चला कि जिन पुरुष खिलाड़ियों ने हिंसक खेल खेला था, परंतु जिन्हें अगले दिन के लिए रणनीति बनाने को नहीं कहा गया था, उनकी आक्रामकता सामान्य से अधिक नहीं थी. लेकिन जिन खिलाड़ियों को अगले दिन अच्छी तैयारी के साथ आने को कहा गया था, उनकी आक्रामकता काफी बढ़ गई थी. दूसरी तरफ़ अहिंसक खेल खेलने वाले लोगों की आक्रामकता सामान्य से कम ही रही. इससे साबित होता है कि जो लोग लगभग हर दिन हिंसक खेल खेलते हैं और बाक़ी समय अपने खेल को सुधारने के बारे में सोचते रहते हैं, उनमें आक्रामकता भी अधिक होती है और वे लोग जाने-अनजाने लोगों से उलझते रहते हैं. दूसरी बात यह भी है कि इस सर्वे के लिए मात्र 20 मिनट तक ही खेल खेलने को कहा गया, जबकि कंप्यूटर गेम के नशे से ग्रस्त लोग इससे कहीं अधिक समय तक खेल खेलते रहते हैं और इसका असर उनके दिमाग़ पर छाया रहता है. इसलिए अगर आपके बच्चे हिंसक खेलों के शौक़ीन हैं तो सावधान रहिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
नौकरी कर रहे लोगों को इच्छित पद एवं अधिकार मिलने के आसार बनेंगे. परिवार के साथ वक़्त बिताएंगे. सौदे में कठिनाई होगी. हो सकता है कि यात्रा निरस्त करनी पड़े. पुराने दोस्त के आगमन से परिवार में व्यस्तता बढ़ेगी.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
कार्यस्थल पर सबके सहयोग से सफलता हासिल कर लेंगे. युवाओं को अध्ययन के मुद्दे पर तनाव बना रहेगा. निर्माण कार्य की आवश्यकता महसूस होगी. कोई शुभ समाचार आपके उत्साह को बढ़ाएगा, जिससे काम बनेगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
साझेदारी में चल रहा गतिरोध दूर हो सकता है. अनावश्यक शंकाओं से बचें. ग़लत तरीक़े से धन अर्जित न करें. यात्रा आवश्यक होगी. आयात-निर्यात से अच्छा लाभ होगा. पुराने मित्र मिलेंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
आपके द्वारा किए गए कार्यों का विरोध होगा. बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. अचानक कोई नई परेशानी खड़ी हो सकती है. परिवार की समस्याओं के संबंध में कोई ग़लत निर्णय लेना कठिन होगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
प्रियजनों से भेंट होगी. व्यय की पूर्ति होगी. कामकाज के तरीक़ों में बदलाव करके अच्छा लाभ कमाएंगे. सुख-दुःख को समान समझ कर सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें. सब अपने आप ठीक होगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
कार्य के सिलसिले में भाग-दौड़ करनी पड़ सकती है. व्यापार से जुड़े जातकों की विभिन्न क्षेत्रों में साख बढ़ेगी. परिवार के सहयोग से काम में आसानी होगी. घरेलू मामले बातचीत से सुलझाएंगे.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
शुभ समाचार का आना लगातार जारी रहेगा, इसलिए वही कार्य करें, जिसके बनने की उम्मीद हो. संतान के प्रति थोड़ा चिंतित होंगे, पर समझदारी से काम लें. आकर्षक फ़ायदे की उम्मीद पर किया गया निवेश नुक़सान का सौदा हो सकता है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
आप अव्यवस्थाओं का विरोध करेंगे और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेंगे. पड़ोसियों के कारण कुछ परेशानी हो सकती है. बेहतर होगा कि उनसे बनाकर रखें, तभी सहायता मिलेगी. नए सौदे लाभदायक साबित हो सकते हैं.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
आपकी सकारात्मक सोच से कार्यस्थल पर काम में मजा आएगा. पहले एवं तीसरे दिन पारिवारिक अशांति रहेगी, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय उससे पहले ही ले लें. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
पारिवारिक व्यवस्था बनाने में व्यस्त रहेंगे. सोचे हुए कार्य सफल होंगे और मित्रों द्वारा किए जा रहे विरोध में कमी आएगी. अधिकारी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे. आपको अपने संपर्क का लाभ मिलेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है. आपके कार्य की प्रशंसा होगी. मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. समाज के कार्यों में व्यस्त रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
आप पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का दबाव बनेगा. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. अपने सामान के प्रति सचेत रहें. नया काम करना नुक़सानदेह हो सकता है. संतान के संबंध में सुखद समाचार प्राप्त होगा.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

दुनिया भर के कई नेताओं, जिनमें फ़्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भी शामिल हैं, ने बैग्बो से पद छोड़ने की अपील की थी, जिसकी उन्होंने अनसुनी कर दी.

आइवरी कोस्ट

सत्ता की लड़ाई में पिसी जनता

झगड़े का एक मुख्य कारण यह भी था कि आइवरी कोस्ट के केंद्रीय बैंक ने राष्ट्रपति पद के दो दावेदारों में से एक, बैग्बो का सरकारी धन पर से नियंत्रण ख़त्म कर दिया. केंद्रीय बैंक के इस क़दम को बैग्बो को पद से हटाने के लिए वित्तीय और राजनीतिक दबाव के रूप में देखा गया.

राजीव रंजन तिवारी

आइवरी कोस्ट के निर्वाचित राष्ट्रपति अलासान वाएतरा के समर्थक भारी हथियारों के साथ अबिजान में घूम रहे हैं. साथ ही आइवरी कोस्ट में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टरों ने भी निवर्तमान राष्ट्रपति लोरांग बैग्बो की सेनाओं पर गोलीबारी शुरू कर दी है. आइवरी कोस्ट में पिछले साल 28 नवंबर को हुए चुनावों में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों, अलासान वाएतरा और लोरांग बैग्बो ने अपनी-अपनी जीत का ऐलान किया था. बाद में देश के चुनाव आयोग ने अलासान वाएतरा को विजयी घोषित किया था. संयुक्त राष्ट्र भी वाएतरा को ही राष्ट्रपति के रूप में स्वीकारता है. चूंकि दोनों ही अपने को जीता हुआ मानकर चल रहे थे, इसलिए निवर्तमान राष्ट्रपति बैग्बो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे और दूसरी ओर निर्वाचित राष्ट्रपति वाएतरा कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर गुज़रने से गुरेज नहीं कर रहे थे.

बताते हैं कि दोनों गुटों के बीच छिड़ी हिंसक जंग में अब तक कम से कम एक हज़ार लोग मारे गए. अलासान वाएतरा की समर्थक सेना लगातार राष्ट्रपति निवास की ओर बढ़ने की कोशिश में लगी हुई थीं, जहां बैग्बो अपने सैनिकों के साथ घुसे हुए थे. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने आइवरी कोस्ट में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रपति से उनके समर्थकों द्वारा कथित तौर पर सैकड़ों लोगों को मारने की जांच करने का आग्रह किया है. बान की मून कहते हैं कि वह आइवरी कोस्ट के दुएकुए क़स्बे से मिली ख़बरों से चिंतित हैं. अलासान वाएतरा ने कहा कि दुएकुए, जहां अकेले 800 लोग मारे गए, ख़ून की होली खेली गई है, उसमें उनके समर्थकों का हाथ नहीं है. ग़ौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों ने सैकड़ों लाशें बरामद की हैं. दुएकुए में संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं एक चर्च के अहाते में शरण लिए हज़ारों आम लोगों की रक्षा करती रहीं. अलासान वाएतरा समर्थक सेना के अधिकारियों ने कहा है कि शहर में हुई लड़ाई में क़रीब 160 लोग मारे गए. उधर आइवरी कोस्ट के प्रमुख शहर अबिजान में भी दोनों गुटों के बीच घमासान लड़ाई हुई. वाएतरा समर्थकों ने बैग्बो की सेना को सभी प्रमुख स्थानों से खदेड़ दिया. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक़, बैग्बो के नियंत्रण वाले राष्ट्रपति महल के क़रीब भी गोलीबारी हुई. झगड़े का एक मुख्य कारण यह भी था कि आइवरी कोस्ट के केंद्रीय बैंक ने राष्ट्रपति पद के दो दावेदारों में से एक, बैग्बो का सरकारी धन पर से नियंत्रण ख़त्म कर दिया. केंद्रीय बैंक के इस क़दम को बैग्बो को पद से हटाने के लिए वित्तीय और राजनीतिक दबाव के रूप में देखा गया. बैंक के इस क़दम का सीधा अर्थ यह था कि उसने वाएतरा को राष्ट्रपति मान लिया. आइवरी कोस्ट में हुए चुनाव पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि देश के स्वतंत्र चुनाव आयोग ने अलासान वाएतरा को विजयी घोषित किया था, जिसका समर्थन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी किया गया था, लेकिन आईवरी कोस्ट की संवैधानिक परिषद ने लोरांग बैग्बो को यह कहते हुए विजयी घोषित किया कि विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में चुनावों में भारी धांधली हुई. इसके बाद बैग्बो ने पद से हटने से मना कर दिया था. तभी से दोनों पक्षों में गतिरोध बना. अलासान वाएतरा और लोरांग बैग्बो के बीच इस खींचतान में कई हिंसक वारदातें भी हुईं. आइवरी कोस्ट में लगभग दस हज़ार संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिक तैनात हैं. यहां के 14 हज़ार लोगों को पड़ोसी देश लाइबेरिया में शरण लेनी पड़ी. इससे यहां राजनीतिक अनिश्चितता और तनाव का माहौल बन गया था. संयुक्त राष्ट्र ने अधिक से अधिक लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराईं.

बैग्बो ने संयुक्त राष्ट्र से कहा था कि वह अपने सभी 10 हज़ार शांति रक्षक सैनिकों को देश से हटा ले, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा करने से इंकार कर दिया. अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेडक्रॉस (आईसीआरसी) के मुताबिक़, वाएतरा के वफ़ादारों द्वारा क़स्बे पर नियंत्रण के बाद हिंसा शुरू हुई होगी.

दुनिया भर के कई नेताओं, जिनमें फ़्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भी शामिल हैं, ने बैग्बो से पद छोड़ने की अपील की थी, जिसकी उन्होंने अनसुनी कर दी. देश छोड़कर भागने वालों में ज़्यादातर लोग वाएतरा समर्थक थे, जिन्हें आशंका थी कि पद पर जमे रहने वाले राष्ट्रपति के वफ़ादार सैनिक उन्हें प्रताड़ित कर सकते हैं. मामले को कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने की कोशिशें की गईं. संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थियों से संबंधित संस्था यूएनएचसीआर के मुताबिक़, आइवरी कोस्ट छोड़कर भागने वाले ज़्यादातर लोग देश के पश्चिमी हिस्से के गांवों से निकले थे. विवाद के चलते विश्व बैंक ने आइवरी कोस्ट को दी जाने वाली सहायता पहले ही रोक दी थी, जबकि वेस्ट अफ़्रीकन सेंट्रल बैंक ने आइवरी कोस्ट के सरकारी खाते का नियंत्रण अलासान वाएतरा को देने की घोषणा कर दी थी. वाएतरा संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों की सुरक्षा में राजधानी अबिजान के एक होटल में अपने समर्थकों के साथ कई दिनों से रह रहे थे.

बैग्बो ने संयुक्त राष्ट्र से कहा था कि वह अपने सभी 10 हज़ार शांति रक्षक सैनिकों को देश से हटा ले, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा करने से इंकार कर दिया. अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेडक्रॉस (आईसीआरसी) के मुताबिक़, वाएतरा के वफ़ादारों द्वारा क़स्बे पर नियंत्रण के बाद हिंसा शुरू हुई होगी. इस ख़ूनी जंग में जितने लोगों को बर्बरतापूर्वक मारा गया है, उसे देखकर सदमा लग सकता है. इसमें कोई संदेह नहीं कि कई शहरों में बड़ी संख्या में हत्याएं हुईं. संस्था इससे जुड़े सबूतों को जुटाने में लगी है. जब अलासान वाएतरा समर्थक सैनिक टुकड़ियां राष्ट्रपति आवास पहुंचीं, तब संयुक्त राष्ट्र और फ़्रांस की सेनाओं ने भी उनका साथ दिया. संयुक्त राष्ट्र और फ़्रांस के अनुसार, उन्होंने यह क़दम इसलिए उठाया, क्योंकि बैग्बो की सेनाओं ने भारी हथियारों से लोगों पर आक्रमण किया, जिसे रोकना आवश्यक था. बाद में रिपोर्ट आई कि फ़्रांस की सेना की स्पेशल टुकड़ी ने बैग्बो को बंदी बना लिया और वाएतरा को सौंप दिया. इस पर अंतरराष्ट्रीय विरोध हुआ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले सेनाएं एक्टिव एक्शन में भाग नहीं ले सकतीं. वे सिर्फ़ आम जनता की रक्षा के लिए तैनात होती हैं. तुरंत ही फ़्रांस ने इस बात को नकारा और बयान जारी किया कि बैग्बो को वाएतरा समर्थक सेना ने ही पकड़ा था, जबकि उसकी सेना बाहर खड़ी थी. अब असलियत चाहे जो भी हो, लेकिन लड़ाई बंद हो गई है और शांति स्थापना के प्रयास जारी हैं.

feedback@chauthiduniya.com

अशांति की पृष्ठभूमि

दरअसल आइवरी कोस्ट का इतिहास रहा है कि यहां आज तक जो भी प्रसिद्ध नेता हुए, वे आगे चलकर तानाशाह बन गए. सबसे पहले यह हाल हुआ था फेलिक्स का, जिन्होंने लगभग तीस साल तक राज किया. ये वही थे, जिन्होंने आइवरी कोस्ट के कोको व्यापार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया और यह देश कोको उत्पादन में सबसे अग्रणी बन गया. उन्होंने शांति व्यवस्था भी चाक चौबंद की, लेकिन आगे चलकर बैग्बो ने उनकी सत्ता को तब चुनौती दी, जब वह तानाशाह बन गए और लोकतंत्र का गला घोंटने लगे. बैग्बो लोकतंत्र और पारदर्शिता चाहते थे और जनता ने उनका सहयोग किया. इस कारण उन्हें दो बार जेल में भी डाला गया. सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि दूसरी बार उन्हें जेल में डालने वाले प्रधानमंत्री वाएतरा ही थे, जो भले ही आज प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन तब उदारवादियों के विरोधी थे. आज पासा पलट गया है और दोनों नेता जिस काम के लिए जाने जाते थे, ठीक उसका उलटा कर रहे हैं. बैग्बो तानाशाह बन गए और वाएतरा अब प्रजातंत्र के हिमायती हैं. आज जनता वाएतरा के साथ है. लड़ाई का सबसे बड़ा कारण तो राजनीतिक सत्ता है, लेकिन इस लड़ाई में आंचलिक और सांप्रदायिक नारों की आड़ में देश को बांट दिया गया है. बैग्बो ने सत्ता में आने के बाद देश को क्षेत्रीय और धार्मिक कारणों पर बांटने की वही चाल चली, जो उनसे पहले फेलिक्स ने चली थी. आइवरी कोस्ट का उत्तरी भाग मुस्लिम बाहुल्य है. ऐसा इसलिए, क्योंकि उत्तर में सबसे अधिक कोको के बाग़ हैं, जहां बाहरी देशों के लोग मज़दूरी करने आए और यहीं बस गए. सबसे अधिक संख्या में बुर्किना फासो से आए लोग हैं. वहीं दक्षिण में ईसाइयों की संख्या अधिक है. वे यहां के मूल निवासी हैं. उत्तर बनाम दक्षिण, इस्लाम बनाम ईसाइयत की लड़ाई में बैग्बो ने देश को उलझा दिया. वाएतरा भी बुर्किना फासो के मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें कई बार चुनाव नहीं लड़ने दिया गया. बैग्बो जब सत्ता में आए और उत्तर के मुसलमानों के साथ पक्षपात होने लगा तो वहां के सैनिकों ने 2002 में विद्रोह कर दिया, जिस कारण देश में गृह युद्ध की स्थिति बन गई. संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं ने वहां जाकर युद्ध विराम लगाया और बैग्बो ने सत्ता से उतर जाना क़ुबूल किया, लेकिन 2005 के बाद बैग्बो चुनाव किसी न किसी बात की आड़ लेकर टालते रहे. आख़िरकार 2010 में चुनाव हुए और बैग्बो हार गए, लेकिन फिर भी सत्ता से उतरने को तैयार नहीं हुए. इसी कारण आइवरी कोस्ट रणभूमि बन गया. संयुक्त राष्ट्र और फ़्रांस के शांति सैनिकों ने वाएतरा के सैनिकों के साथ मिलकर बैग्बो को अपने क़ब्ज़े में ले लिया है, लेकिन तब, जबकि देश में लगभग 1000 लोगों की मौत हो चुकी है. वैसे वाएतरा के सामने अभी पहाड़ से भी बड़ा काम बाक़ी है. याद रखने की बात यह है कि देश पहले फ़्रांस का उपनिवेश था और फ़्रांस का इस लड़ाई में खुलकर वाएतरा का साथ देना उनके लिए हानिकारक हो सकता है. ऐसा इसलिए भी, क्योंकि बैग्बो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि देश में अराजकता और राजनीतिक अशांति का एक कारण फ़्रांस की दखलंदाज़ी भी है और वाएतरा फ़्रांस के ट्टू हैं. अगर देशवासियों को ऐसा लगा तो वाएतरा का भी वही हश्र होगा, जो आज बैग्बो का हुआ है. आशा करते हैं कि आइवरी कोस्ट में पहले जैसी शांति व्यवस्था क़ायम होगी और देश एक बार फिर से अफ़्रीकन देशों में अपनी अग्रणी जगह बना लेगा.

सिद्धार्थ राय
feedback@chauthiduniya.com

गुरु प्रेम और साईं बाबा

पठन समाप्त होने पर काका साहेब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है. नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है. अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा. ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है.

यह तो सर्वविदित ही है कि बाबा ने काकासाहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के दो ग्रन्थ श्री मदभागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी. काकासाहेब इन ग्रन्थों का नियमपूर्वक पठन बाबा के समय से करते आये है और बाबा केसमाधि लेने केउपरान्त अभी भी वे उसी प्रकार अध्ययन करते रहे. एक समय चौपाटी (बम्बई) में काकासाहेब प्रातःकाल एकनाथी भागवत का पाठ कर रहे थे. माधवराव देशपाडे (शामा) और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे तथा ये दोनों ध्यानपूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे. उस समय 11वें स्कन्ध केद्वितीय अध्याय का वाचन चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश केसिद्ध यानी कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोर्त्र, द्रुमिल, चमस और कर भाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझायी थी. राजा जनक ने इन नव-नाथों से बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान किया था. पठन समाप्त होने पर काकसाहेब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परन्तु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है. नाथ तो सिद्ध थे, परन्तु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है. अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा. ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिये तो कोई आशा ही नहीं है. माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी न लगी. वह कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है, जिसके फलस्वरुप ही हमें साई सदृश अमूल्य हीरा हाथ लग गया है, तब फिर इस प्रकार का राग अलापना बड़ी निंदनीय बात है. यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है. माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परन्तु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेहपूर्वक भक्ति नहीं कर रहे है. क्या बाबा ने अधिकारपूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्रीहरि या गुरु केनाम जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है. तब फिर भय और चिंता को स्थान ही कहां रह जाता है. परन्तु फिर भी माधवराव के वचनों से काकासाहेब का समाधान न हुआ. वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिन्तित ही बने रहे. यह विचार उनके मस्तिष्क में बार-बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों केसमान भक्ति की प्राप्ति सम्भव हो सकेगी.

एक महाशय, जिनका नाम आनन्दराव पाखाडे था, माधवराव को ढूंढ़ते-ढूंढ़ते वहां आ पहुंचे. उस समय भागवत का पठन हो रहा था. श्री पाखाडे भी माधवराव केसमीप ही जाकर बैठ गये और उनसे धीरे-धीरे कुछ वार्ता भी करने लगे. वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे. इनकी कानाफूसी केकारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा. अतएव काकासाहेब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है. माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो सन्देह प्रकट किया था, यह चर्चा भी उसी का समाधान है. कल बाबा ने श्री पाखाडे को जो स्वप्न दिया है, उसे इनसे ही सुनो. इसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है. सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र उत्कंठा थी और सबसे अधिक काकासाहेब को. सभी केकहने पर श्री पाखाडे अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है. मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूं. पानी मेरी कमर तक है और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईबाबा के श्री-दर्शन हुए. वे एक रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री-चरण जल केभीतर थे. यह दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरुप देखकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ. इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा. मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा केसमीप ही खड़े है और उन्होंने मुझसे भावुकतापूर्ण शब्दों में कहा कि आनन्दराव, बाबा के श्री-चरणों पर गिरो. मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही करना चाहता हूं. परन्तु उनके श्री-चरण तो जल केभीतर है. अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं. मैं तो निस्सहाय हूं. इन शब्दों को सुनकर शामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपाकर अपने चरण बाहर निकालिये. बाबा ने तुरन्त चरण बाहर निकाले और मैं उनसे तुरन्त लिपट गया. बाबा ने मुझे यह कहते हुये आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंदपूर्वक जाओ. घबराने या चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं. अब तुम्हारा कल्याण होगा. उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि एक जरी केकिनारों की धोती मेरे शामा को दे देना, उससे तुम्हें बहुत लाभ होगा.

बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने केलिये ही श्री पाखाडे धोती लाए और काकासाहेब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिये, परन्तु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, तब तक मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं. कुछ तर्क-वितर्क के पश्चात काका ने दैवी आदेशसूचक पर्चियां निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया. काकासाहेब का यह नियम था कि जब उन्हें कोई सन्देह हो जाता तो वे कागज की दो पर्चियों पर स्वीकार-अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते थे और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था, उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे. इसका भी निपटारा करने केलिये उन्होंने उपयुक्त विधि केअनुसार ही दो पर्चियां लिखकर बाबा के चित्र केसमक्ष रखकर एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा. बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई तो वह स्वीकारसूचक पर्ची ही निकली और तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी. इस प्रकार आनन्दराव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काकासाहेब का भी सन्देह दूर हो गया.

इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य सन्तों केवचनों का उचित आदर करना चाहिये, परन्तु साथ ही साथ यह भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी मां अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिये, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिन्ता है. बाबा केनिम्नलिखित वचनों को हृदयपटल पर अंकित कर लो. इस विश्व में असंख्य सन्त हैं, परन्तु अपना पिता (गुरु) ही सच्चा पिता (सच्चा गुरु) है. दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों न कहते हां, परन्तु अपना गुरु-उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिये. संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर, उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमस्कार करो. तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है, जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का. बाबा की हर कथा में कुछ न कुछ संदेश छिपा रहाता है.

ओम साई राम

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मां होने के कारण नारी का स्थान भगवान से भी ऊंचा है.
प्रेमचंद

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

घर पहुंचते ही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की पोल खुल गई. वहां तक बिजली के तार-खंभे तो हैं, लेकिन बिजली नहीं है.

अनंत विजय

इ़ज़्ज़त की ज़मींदारी

शादी के ग्यारह साल बाद ससुराल जाने का मौक़ा मिला. लंबा अंतराल इस वजह से कि ससुराल के सब लोग बिहार के ऐतिहासिक शहर गया में बस गए थे. शादी भी वहीं से हुई और जब भी जाना हुआ गया ही गया. पत्नी के पैतृक गांव यानी अपनी असली ससुराल जाने का अवसर, जैसा कि ऊपर बता चुका हूं, शादी के ग्यारह साल बाद मिला. इतने लंबे अंतराल के बाद वहां पिछले साल दिवंगत हुए अपने श्वसुर की बरसी में गया था. हमें जाना था गया से तक़रीबन साठ–सत्तर किलोमीटर दूर औरंगाबाद ज़िले के रायपुर बंधवा गांव में. हम लोग गया से चलकर दो घंटे में वहां पहुंचे. बिहार की सड़कें पिछले सालों में बेहद अच्छी हो गई हैं और रास्ते में पड़ने वाले आज़ादी के पूर्व बने सारे पुलों के समांतर नए पुल बन रहे थे. जब मैं रास्ते में था तो सोच रहा था कि लगभग एक दशक पूर्व अपनी शादी में मुझे जमालपुर से गया के लगभग सौ–एक सौ दस किलोमीटर का सफर तय करने में ग्यारह घंटे लगे थे. तब बिहार में लालू राज था और सड़कें लगभग ग़ायब हो चुकी थीं. ख़ैर, यह अवातंर प्रसंग है. मैं बात कर रहा था अपने बंधवा सफर की. औरंगाबाद ज़िले के बंधवा तक जाने का रास्ता पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाक़े गोह एवं हसपुरा से होकर जाता था, लेकिन टाटा मैजिक से हमने दो घंटे का सफर बेख़ौफ़ होकर तय किया. रास्ते में सब कुछ सामान्य लग रहा था. रास्ते में मिलने वाले क़स्बानुमा बाज़ार में ख़ूब भीड़भाड़ और चहल–पहल थी, किसी भी तरह के डर का वातावरण नहीं दिख रहा था. कहीं कोई पुलिसवाला भी नहीं दिखा, अर्द्धसैनिक बल के जवान तो दूर की बात. हम लोग दोपहर बाद बंधवा पहुंचे. वहां का घर पुराने जमाने का बना था, मिट्टी की मोटी–मोटी दीवारें और ख़ूब ऊंचाई पर छत.

गांव में घुसते ही एक बोर्ड दिखाई दिया–यह गांव राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ऊर्जाकृत ग्राम है. लेकिन घर पहुंचते ही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की पोल खुल गई. वहां तक बिजली के तार–खंभे तो हैं, लेकिन बिजली नहीं है. कई घरों में सोलर एनर्जी से काम चल रहा था. मेरे लिए बिना बिजली के रहने का यह नया अनुभव नहीं था, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद बग़ैर बिजली के चार–पांच दिन गुजारे. यह एक संयोग ही बना कि जब पहली बार भारत ने क्रिकेट का वर्ल्डकप जीता था, तब भी मैंने रेडियो पर ही भारत की जीत की दास्तां सुनी थी और इस बार भी क्रिकेट के महायुद्ध में जब भारत श्रीलंका को पराजित कर रहा था तो मैं रेडियो से ही चिपक कर बैठा था. लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि एक ओर जहां मैं टीवी और बिजली से दूर था, वहीं मेरा मोबाइल मुझे बाहर की दुनिया से जोड़े हुए था और मुझे अपडेट रख रहा था. उन पांच दिनों में मैंने मोबाइल इंटरनेट का जमकर इस्तेमाल किया. फेसबुक और ट्वीटर से वर्ल्डकप फाइनल के दौरान लोगों के जोश और उत्साह का अंदाज़ मिल रहा था.

रायपुर बंधवा के अपने बंगले पर जब हम लोग शाम को बैठे तो लोगों के आने–जाने का सिलसिला शुरू हो गया. चूंकि मैं घर का दामाद था, इसलिए मुझे ख़ास तौर पर इ़ज़्ज़त बख्शी जा रही थी. गांव में मेरे दिवंगत श्वसुर प्रोफेसर प्रियव्रत नारायण सिंह की काफी इ़ज़्ज़त थी. गांव से बाहर रहने के बावजूद उनका दिल गांव में ही बसता था. हर साल दो–तीन बार गांव ज़रूर जाते थे. शाम को जब मैं और मेरी पत्नी के बड़े भाई राजेश जी गांव में घूमने निकले तो इस इ़ज़्ज़त का एहसास और गहरा हो गया. रास्ते में हर छोटा–बड़ा आदमी राजेश जी को सलाम मालिक कह रहा था. जमींदारी तो 1953 में ही चली गई थी, लेकिन इ़ज़्ज़त की जमींदारी अब भी क़ायम थी. कई लोग जो हमसे मिलने आ रहे थे, वे राजेश जी और उनके चाचा के सामने कुर्सी या बेंच पर बैठने के बजाय ज़मीन पर बैठ रहे थे. मुझे यह सामंती लग रहा था, लेकिन जब उनसे बात हुई तो पता चला कि यह उनके सम्मान देने का एक तरीक़ा है, उन पर कोई इसके लिए दबाव नहीं बनाता है. यह सदियों से चली आ रही एक परंपरा है, जिसे निभाया जा रहा है. यहां मेरे दिमाग़ में एक बात बार–बार उठ रही थी कि सुदूर गांव में हर कोई एक–दूसरे को विश करने के लिए सलाम का इस्तेमाल कर रहा था. बोलचाल में उर्दू के लफ़्ज़ों का जमकर इस्तेमाल हो रहा था. उर्दू को मुसलमानों की भाषा कहने वालों को उन इलाक़ों में जाकर देखना चाहिए कि जहां कोई मुस्लिम आबादी नहीं है, वहां भी बग़ैर किसी औपचारिक शिक्षा के, सिर्फ़ परंपरा के सहारे लोग उर्दू का इस्तेमाल कर रहे थे. भाषा के बीच दरार पैदा करने वाले लोगों को एसी कमरों से बाहर निकल कर उन लोगों के बीच जाने की ज़रूरत है.

इन पांच दिनों तक वहां रहने के दौरान कई अनुभव हुए. एक दिन अचानक दोपहर में घर के बरामदे में बैठा था तो दर्जनों बच्चे थाली पीटते हुए सामने से गुजरे. पूछने पर पता चला कि ये बच्चे मिड डे मील स्कीम के तहत खाना खाने स्कूल जा रहे हैं. और दरियाफ्त की तो आगे पता चला कि बच्चों का नामांकन तो स्कूल में कर दिया गया है, लेकिन उनकी पढ़ाई और स्कूल में उनकी उपस्थिति ज़्यादातर रजिस्टर में ही दर्ज होती है. बच्चे स्कूल में पढ़ने के बजाय दोपहर का खाना खाने आते हैं. दस बजे के क़रीब स्कूल में खाना बनना शुरू हो जाता है और बारह–एक बजे तक बच्चों को खाना खिलाकर स्कूल के मास्टर लोग फारिग हो जाते हैं. उसी तरह आंगनवाड़ी केंद्र का काम भी चल रहा था. लेकिन गांव के ही लोगों ने बताया कि मिड डे मील में जमकर घपला होता है, रजिस्टर में फ़र्ज़ी छात्रों के नाम भी दर्ज होते हैं और ज़िले के आला शिक्षा अधिकारियों की मिलीभगत से यह फ़र्ज़ीवाड़ा धड़ल्ले से चलता है. बातों–बातों में पता चला कि वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जिसमें तैनात डॉक्टर घंटे–डेढ़ घंटे के लिए केंद्र में आते हैं. गांव के लोग इस बात से ही ख़ुश दिखे कि कम से कम घंटे भर के लिए तो डॉक्टर गांव में होता है. नीतीश राज के पहले तो स्वास्थ्य केंद्र का ताला ही महीनों में खुलता था. यह भी पता नहीं चलता था कि किसी डॉक्टर की तैनाती वहां है या नहीं. लेकिन बड़ा सवाल अब भी है कि क्या नीतीश कुमार शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुधार कर पाएंगे, क्या केंद्र पर तैनात डॉक्टर पूरे समय तक मौजूद रहेंगे, क्या होटल में तब्दील हो रहे स्कूलों को वह विद्या का मंदिर बना पाएंगे? प्रदेश की जनता ने नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत के साथ जिताकर दोबारा सत्ता तो सौंप दी, लेकिन अब जनता की प्रचंड अपेक्षा भी है, जिस पर नीतीश कुमार को खरा उतरना होगा. अगर वह ऐसा कर पाते हैं तो इतिहास पुरुष हो जाएंगे और अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो इतिहास पुरुष बनने के बजाय इतिहास में खो जाने का ख़तरा भी उत्पन्न हो जाएगा.

गांव में घुसते ही एक बोर्ड दिखाई दिया-यह गांव राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ऊर्जाकृत ग्राम है. लेकिन घर पहुंचते ही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की पोल खुल गई. वहां तक बिजली के तार-खंभे तो हैं, लेकिन बिजली नहीं है. कई घरों में सोलर एनर्जी से काम चल रहा था. मेरे लिए बिना बिजली के रहने का यह नया अनुभव नहीं था, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद बग़ैर बिजली के चार-पांच दिन गुजारे.

बंधवा में चार–पांच दिन रहने के बाद हम लोग दोपहर बाद फिर से गया के लिए रवाना हो गए. देवकुंड और अमझरशरीफ से होते हुए हम लोग हसपुरा के रास्ते जा रहे थे. शाम घिरने लगी थी, लेकिन डर कहीं नहीं था, खुली गाड़ी में अंधेरे में सफर जारी था. मुझे याद है, जब शादी के बाद मैं अपनी ससुराल आया–जाया करता था तो शाम ढलने के बाद मेरे श्वसुर जी पास के बाज़ार में भी नहीं जाने देते थे. एक अजीब तरह का डर और अपराधियों का ख़ौफ़ लोगों के मन में इतने अंदर तक था कि हर कोई शाम ढलने के पहले घर लौट आता था, लेकिन सिर्फ़ पांच साल में एक व्यक्ति ने पूरी फिजां ही बदल दी. अंत में मैं एक मजेदार वाकया सुनाता हूं, जो वहीं किसी ने मुझे सुनाया. हसपुरा से एक लड़का गोह जाने के लिए बस में चढ़ा और उसने किराए के तौर पर पंद्रह रुपये निकाल कर दिए. कंडक्टर ने कहा कि किराए के बीस रुपये बनते हैं. दोनों में बकझक होने लगी. रंगदार टाइप के उस लड़के ने कंडक्टर पर धौंस जमाते हुए कहा कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं तो पंद्रह रुपये ही दूंगा. इस पर कंडक्टर ने जवाब दिया कि तुम भूल गए हो कि लालू यादव का राज ख़त्म हुए छह साल हो गए हैं और अगर तुम तत्काल किराए के बाक़ी पैसे नहीं दोगे तो बस से उतार दूंगा और अगर रंगदारी करोगे तो थाने में बंद करा दूंगा. तो समाज के आम आदमियों में क़ानून के प्रति जो यह विश्वास क़ायम हुआ है, वह बहुत कुछ कह जाता है.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

एयरसेल चाहती है कि उसके 3-जी सिम कार्ड के ज़रिए लैपटॉप में आसानी से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा सके.

नोकिया का नया मोबाइल

अगर आप मोबाइल फोन के शौक़ीन हैं और आपको चाहिए एक ऐसा फोन, जिसमें ढेरों फीचर्स हों तो आपके लिए जानी-मानी मोबाइल कंपनी नोकिया लाई है अपना नया हैंडसेट, जो देखने में काफी आकर्षक है और उसमें ढेरों फीचर्स हैं. नोकिया इस साल बाज़ार में 40 तरह के नए हैंडसेट उतारने जा रही है, जिनमें कम से कम एक दर्जन स्मार्ट फोन शामिल हैं. ये फोन जानी-मानी कंपनी ब्लैकबेरी को मात देने के लिए बाज़ार में उतारे जाएंगे. कंपनी को उम्मीद है कि नोकिया के ये नए मोबाइल ब्लैकबेरी से ज़्यादा पसंद किए जाएंगे. नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट से टाइअप किया है. इन मोबाइलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नोकिया ने ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है. इस फोन से आप पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं. नोकिया ने मनी ट्रांसफर सर्विस में यूनियन बैंक के साथ गठजोड़ किया है. इसके अलावा मोबाइल से मोबाइल कैश ट्रांसफर भी किया जा सकता है. इस सुविधा से छोटे शहरों और गांवों में रहने वालों को बहुत फ़ायदा होगा. नोकिया शोरूम एक तरह से वित्तीय सेवा केंद्र बन जाएंगे. वहां ग्राहक पैसे भी निकाल सकेंगे और 50,000 रुपये तक जमा कर सकेंगे.

नोकिया सी-7 - नोकिया का यह नया स्मार्ट फोन उसके अन्य फोनों की तुलना में महंगा है. दिल्ली में इसकी क़ीमत 29,999 रुपये है. यह ख़ास तौर से प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है और इसमें उनके लिए काफी कुछ है. नोकिया इंडिया के एमडी और वाइस प्रेसीडेंट डी शिवकुमार ने कहा कि नोकिया ए-7 ऑल इन वन बिज़नेस स्मार्ट फोन है और इसमें बेहतर मोबाइल ऑफिस सुविधाओं के साथ मनोरंजन की भी व्यवस्था है. उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि यह प्रोफेशनल्स को पसंद आएगा.

नोकिया एक्स-2 - यह एक क्वर्टी फोन है और नोकिया के पुराने सेट ई-72 की तरह दिखता है, लेकिन दोनों का फ़र्क़ साफ दिखाई देता है. इसकी बॉडी प्लास्टिक की है. इसमें चार रो वाला आकर्षक कीपैड है और इस्तेमाल करने में भी आरामदेह है. मैसेज करने में सुविधाजनक है. इसका कैमरा 3 मेगा पिक्सल का है. ई-मेल करने वालों के लिए इसमें नोकिया ई-मेल सर्विस है, जो कहीं से भी मेल भेजने में समर्थ है. इससे जी-मेल वग़ैरह सेटअप करने में आसानी होती है, लेकिन इसकी वेब ब्राउजिंग उतनी अच्छी नहीं है. इस फोन की ख़ासियत है इसकी बैटरी. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी एक बार चार्ज हो जाने के बाद साढ़े चार घंटे तक चलेगी. भारत में इसकी क़ीमत 5515 रुपये है, जबकि अमेरिका में यह महज़ 80 डॉलर का है.

आपके लिए ख़ास टीवी

सोनी ने बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इन मॉडलों की प्रतिस्पर्धी क़ीमतें तय की हैं, लेकिन सोनी ब्रैविया इंटरनेट कनेक्टेड टीवी के मॉडलों के मुक़ाबले इनके दाम अधिक हैं. सोनी गूगल टीवी एलसीडी-एलईडी टीवी अथवा ब्लू रे डिस्क प्लेयर युक्त है, जिसमें अतिरिक्त रूप से अंतर्निर्मित कंप्यूटर भी है.

अगर आप अपने फुरसत के पलों को ख़ास बनाना और घर बैठे थिएटर का मज़ा लेना चाहते हैं तो जानी-मानी कंपनी सोनी ने आपके लिए गूगल टीवी-1080पी नाम से डिस्प्लेयुक्त इंटरनेट टीवी के कई मॉडल बाज़ार में उतारे हैं. कंपनी ने आकार के लिहाज़ से इन मॉडलों के दाम तय किए हैं. 24 इंच वाले मॉडल का दाम 599 डॉलर है. इसी तरह 46 इंच वाले मॉडल की क़ीमत 1399 डॉलर तय की गई है. सोनी ने बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इन मॉडलों की प्रतिस्पर्धी क़ीमतें तय की हैं, लेकिन सोनी ब्रैविया इंटरनेट कनेक्टेड टीवी के मॉडलों के मुक़ाबले इनके दाम अधिक हैं. सोनी गूगल टीवी एलसीडी-एलईडी टीवी अथवा ब्लू रे डिस्क प्लेयर युक्त है, जिसमें अतिरिक्त रूप से अंतर्निर्मित कंप्यूटर भी है. इसमें गूगल टीवी नामक सॉफ्टवेयर मौजूद है, जो मोबाइल फोनों के लिए जारी मुफ्त एन्ड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. इसमें इंटेल का एटम प्रोसेसर लगा है. यह पारंपरिक टीवी के साथ-साथ वेब ब्राउजिंग की संपूर्ण सुविधा अतिरिक्त रूप से देता है. कुछ मामलों में आपको संपूर्ण कंप्यूटिंग की सुविधा भी मिल सकती है.

सोनी गूगल टीवी दो किस्म के हैं. आपके पास पहले से ही एचडीएमआई इनपुट युक्त एचडीटीवी नहीं है तो आप सोनी गूगल टीवी के एलसीडी अथवा एलईडी मॉडलों में से कोई एक चुन सकते हैं, जिनकी क़ीमत 24 इंच के मॉडल से 30 हज़ार रुपये से शुरू है. अगर आपके पास पहले से एचडीटीवी है, जिसमें एचडीएमआई इनपुट की सुविधा है तो आपके लिए गूगल टीवी युक्त सोनी ब्लू रे प्लेयर काम का है, जो 20 हज़ार रुपये में आता है. इसका रिमोट विशिष्ट किस्म का, बड़े आकार का, प्लेस्टेशन जैसा होता है, जो अंग्रेजी के क्वर्टी कीबोर्ड युक्त होता है. गूगल टीवी देखने के लिए आपका गूगल खाता होना आवश्यक है. गूगल खाता मुफ्त में बनाया जा सकता है और यदि आप जी-मेल का प्रयोग करते हैं तो इस खाते के ज़रिए भी गूगल टीवी का प्रयोग किया जा सकता है. गूगल टीवी युक्त सोनी इंटरनेट टीवी देखने के लिए आपको एक अदद ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी. सोनी गूगल टीवी को अन्य पारंपरिक वीडियो स्रोत जैसे कि वीडियो प्लेयर, डीटीएच सेटटॉप बॉक्स इत्यादि से भी जोड़ा जा सकता है. सामान्य इंटरनेट वीडियो के लिए 2.5 एमबीपीएस और हाई डेफिनिशन वीडियो के लिए 10 एमबीपीएस का डेडिकेटेड इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

▶▶ नई दिल्ली में एलजी के नए रेफ्रिजरेटर को पेश करती हुई एक मॉडल. फोटो-*सुनील मल्होत्रा*

अब लैपटॉप में सिम कार्ड

एयरसेल जल्द ही लैपटॉप में सिम कार्ड की सुविधा देने पाली है. एयरसेल कुछ लैपटॉप और टेबलेट कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों से इस सिलसिले में बातचीत कर रही है.

आप मोबाइल फोन में सिम कार्ड तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन आपको यह सुनकर ख़ुशी होगी कि जल्द ही आप अपने लैपटॉप में भी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे. जानी-मानी कंपनी एयरसेल जल्द ही लैपटॉप में सिम कार्ड की सुविधा देने पाली है. एयरसेल कुछ लैपटॉप और टेबलेट कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियों से इस सिलसिले में बातचीत कर रही है. एयरसेल इन कंपनियों से इस बात का आग्रह कर रही है कि वे लैपटॉप और टेबलेट में सिम कार्ड लगाने की सुविधा उपलब्ध कराएं. दरअसल एयरसेल चाहती है कि उसके 3-जी सिम कार्ड के ज़रिए लैपटॉप में आसानी से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा सके. एयरसेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गुरदीप सिंह के अनुसार, इस सिलसिले में हम कुछ कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम जल्दी ही यह सर्विस शुरू कर देंगे. कंपनी को भारत में कुल 13 सर्किलों में 3-जी सेवा के लिए लाइसेंस मिला है. ज़्यादातर शहरों में एयरसेल की 3-जी सर्विस शुरू हो चुकी है. कंपनी के नेशनल ऑपरेशन हेड विपुल सौरभ ने कहा है कि एयरसेल एकमात्र ऐसी कंपनी है, जो दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति ला रही है. सौरभ ने कहा कि एयरसेल ने राजस्व में अप्रत्याशित रूप से ज़बरदस्त वृद्धि हासिल की है. वर्ष 2010 में कंपनी का राजस्व 2009 की तुलना में 44 फ़ीसदी बढ़ा. एयरसेल विश्व की पांच सबसे बेहतर ढंग से संचालित दूरसंचार कंपनियों में एक है. उन्होंने कहा कि बाज़ार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को हमारे 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से आंका जा सकता है. अगले तीन वर्षों में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश और करने की हमारी योजना है.

साढ़े आठ लाख की मोटरसाइकिल

भारतीय युवाओं में मोटरसाइकिलों के प्रति क्रेज को देखते हुए अमेरिका की जानी-मानी कंपनी हार्ले डेविडसन ने अपना एक शानदार मॉडल पेश किया है. कंपनी ने दिल्ली में बाइक्स का अपना ज़बरदस्त मॉडल फोर्टी एट उतारा है. दिल्ली में इस ख़ूबसूरत मोटरसाइकिल की एक्स शोरूम क़ीमत साढ़े आठ लाख रुपये है. यह बाइक हार्ले डेविडसन के सभी शोरूमों में मिलेगी. इस बाइक में परंपरागत विशेषताओं के साथ ही आधुनिक ज़रूरतों का भी ख़ास ध्यान रखा गया है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन और सस्पेशन वग़ैरह है. इस बाइक की ख़ास बात यह है कि इस पर केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है. दुनिया भर के युवाओं में अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन की बाइक्स के प्रति अलग ही पैशन देखने को मिलता है. भारत बाइक्स के लिए एक बड़ा बाज़ार है, इसे देखते हुए कंपनी अब इन मोटरसाइकिलों को भारत में ही तैयार करेगी. कंपनी हरियाणा में प्रस्तावित संयंत्र से 2011 में दो नई मोटरसाइकिलें पेश करेगी, जिनकी क़ीमत 6.5 लाख रुपये तक होगी. कंपनी की तरफ़ से कहा गया है कि इसके दो मॉडल, सुपर लो और आयरन-883 होंगे. पहले मॉडल की क़ीमत 5.5 लाख, जबकि दूसरे मॉडल की क़ीमत 6.5 लाख रुपये होगी.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

श्रीलंका की मीडिया की मानें तो इससे विस्फोटक स्थिति बनेगी और क्रिकेट बोर्ड के बीसीसीआई से संबंध काफी तनावपूर्ण हो जाएंगे.

मुनाफ़े की लड़ाई में उलझा क्रिकेट

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

राजेश एस कुमार

हमारे देश में होने वाले ज़्यादातर विवादों में एक बात आम होती है, वह यह कि हमें विवाद की जो वजह बताई जाती है, दरअसल वह वजह होती ही नहीं है. विवादों की कोख में जाकर देखें तो मालूम पड़ता है कि कहानी तो कुछ और ही है. ऐसा ही कुछ आईपीएल में श्रीलंका के खिलाड़ियों की वापसी को लेकर पैदा हुए विवाद में देखा जा रहा है. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के चौथे संस्करण में हिस्सा ले रहे श्रीलंकाई क्रिकेटरों को श्रीलंका के खेल मंत्रालय ने जल्दी स्वदेश लौटने का निर्देश दिया है. इस निर्देश के पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि इससे मई में होने वाले इंग्लैंड दौरे के लिए टीम अपनी तैयारी कर सकेगी. लेकिन मामला उतना सीधा नहीं, जितना बताया जा रहा है. दरअसल यहां पर दो पक्षों के बयानों पर ग़ौर करना जरूरी है. एक तरफ श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड कहता है कि उसे बीसीसीआई से हमेशा आवश्यक सहयोग मिला है, इसलिए उसे अपने खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने से कोई एतराज नहीं है. वहीं श्रीलंका के खेल मंत्री महिंदानंद अलुथगामगे के मुताबिक, जब श्रीलंका क्रिकेट के अनुबंधित खिलाड़ी किसी अन्य प्रतियोगिता में जाते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता राष्ट्रीय टीम है और इसे भविष्य में कड़ाई से लागू किया जाएगा.

अब जरा याद कीजिए 2009 का आईपीएल सीजन. उस सीजन में भी श्रीलंका की टीम का इंग्लैंड दौरा था, तब श्रीलंका ने उस दौरे को रद्द करते हुए आईपीएल को प्राथमिकता दी थी. लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया, जो वह खिलाड़ियों पर देश वापसी का दबाव बना रहा है. दरअसल यहां पर मामला पैसा, मुनाफा और हिस्सेदारी से जुड़ा है. वर्ल्डकप और आईपीएल के बाद देश में क्रिकेट से जो पैसा बना है, उससे सभी वाकिफ हैं. जाहिर है, इस मुनाफे में कई लोगों का हिस्सा होता है. लगता है, इस बार श्रीलंका के खेल मंत्रालय को उतना मुनाफा नहीं मिला है, जितनी उसे उम्मीद थी, नहीं तो ऐसा उसे 2009 के दौरान भी करना चाहिए था. तब क्या देश को प्राथमिकता देना जरूरी नहीं था?

इस विवाद की तह तक जाएंगे तो कई और परतें भी दिखाई देंगी. आपको याद होगा कि खेल मंत्री महिंदानंद अलुथगामगे ने भारत की इस बात पर आलोचना की थी कि मुंबई में हुए विश्वकप के फाइनल मैच में श्रीलंकाई नेताओं के साथ रूखा व्यवहार किया गया. इसी आलोचना के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बारे में निर्णय लिया गया. आईपीएल से पहले देश नीति के तहत मंत्रालय ने कहा कि खेल मंत्री जल्द ही सर्कुलर जारी करेंगे, जो सभी श्रीलंकाई खिलाड़ियों के लिए अन्य प्रतिबद्धताओं से पहले राष्ट्रीय कर्तव्य को अनिवार्य बनाएगा. दूसरी तरफ वह इस फरमान के संदर्भ में सफाई देते हुए कहता है कि यह निर्णय हमारे देश के क्रिकेट के प्रदर्शन को सुधारने के लिए बेहद जरूरी है. ताज्जुब की बात है कि इससे पहले 2009 में श्रीलंका सरकार ने अपने खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने का रास्ता साफ करने के लिए इंग्लैंड दौरा ही रद्द कर दिया था. दूसरी ओर आईपीएल के एक फ्रेंचाइजी का कहना है कि उनके श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने उन्हें कम से कम 10 मई तक रुकने का आश्वासन दिया है. इसके अलावा कुछ ने तो यहां तक कहा है कि उनके श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने उन्हें 20 मई तक रुकने का आश्वासन दिया है. इसके अलावा बीसीसीआई श्रीलंकाई खेल मंत्रालय के साथ वार्ता करके इस निर्णय का कारण और निवारण खोजने में लगी है. महिंदानंद अलुथगामगे कहते हैं कि राष्ट्रीय चयन समिति की सिफ़ारिश पर मैंने बोर्ड के सचिव को यह निर्देश दिया है कि वह खिलाड़ियों को सूचित कर दें कि इंग्लैंड दौरे की तैयारी के लिए वे पांच मई तक स्वदेश लौट आएं. जबकि आईपीएल 28 मई को ख़त्म हो रहा है. श्रीलंका के जो खिलाड़ी आईपीएल–4 की विविध टीमों के साथ अनुबंधित हैं, वे श्रीलंका सरकार के तुरंत घर लौटने के फरमान से बेहद परेशान हैं. उन्होंने निर्णय लिया है कि वे इस हुक्म का पालन नहीं करेंगे. श्रीलंका के 9 खिलाड़ी इस फरमान को मानने के लिए बाध्य हो रहे हैं. सभी खिलाड़ी अपनी आईपीएल टीमों के लिए एक नगीने की तरह हैं, जिनके वापस चले जाने से उनकी टीमों के प्रदर्शन पर गंभीर असर पड़ना तय है.

इतना तो तय है कि खेल मंत्रालय का अपने क्रिकेटरों को वापस बुलाने का निर्णय काफी विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकता है. श्रीलंकाई बोर्ड के विश्व क्रिकेट के सबसे शक्तिशाली बोर्ड बीसीसीआई के साथ रिश्तों के लिए यह चिंता की बात है. जानकारों की मानें तो ताजा घटना से श्रीलंका और बीसीसीआई के बीच तनाव वाली स्थिति पैदा होना लगभग तय है, क्योंकि वह (बीसीसीआई) कहीं न कहीं आईसीसी और विश्व क्रिकेट में दबदबा रखता है. आईपीएल की दो टीमों में श्रीलंकाई खिलाड़ी कप्तान हैं और इसके अलावा सूरज रणदीव, नुवान कुलशेखरा, मुथैया मुरलीधरन, तिशारा परेरा, लसित मलिंगा, दिलहारा फर्नांडो, तिलकरत्ने दिलशान और नुवान प्रदीप खेल रहे हैं. इसके अलावा यह भी तय है कि इन खिलाड़ियों के अपने देश लौटने से टीमों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. टीमों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वे बीच टूर्नामेंट में इन क्रिकेटरों के चले जाने के बाद इनकी जगह किन खिलाड़ियों को शामिल करें. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के ऐलान के बाद पहले से ही दर्शकों की कम होती दिलचस्पी का सामना कर रहे इस टूर्नामेंट पर संकट के बादल घिरते नज़र आ रहे हैं. आईपीएल की अधिकतर टीमें ऐसी हैं, जो अपने हिस्से के आधे लीग मैच खेल चुकी हैं और टूर्नामेंट के अहम दौर में पहुंचने वाली हैं. श्रीलंकाई क्रिकेटरों के वापस लौटने से आईपीएल की अधिकतर टीमों को इनकी भरपाई करने में दिक्कत आ रही है. खासकर उन टीमों को, जिनमें लसिथ मलिंगा, कुमार संगकारा, महेला जयवर्द्धने और तिलकरत्ने दिलशान जैसे श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं, को भारी नुकसान हो सकता है. कोच्चि टस्कर्स की टीम की अगुवाई जयवर्धने कर रहे हैं तो डेक्कन चार्जर्स की कमान संगकारा के हाथों में है. ऐसे में दोनों टीमों के लिए नए कप्तान ढूंढने की चुनौती टीम प्रबंधन को परेशान कर सकती है. मुंबई इंडियंस को मलिंगा की गैर मौजूदगी खलेगी. इस तेज गेंदबाज के न रहने से मुंबई इंडियंस की टीम के चैंपियन बनने की उम्मीदों को धक्का लगेगा. हालांकि मुंबई की टीम इस समय बेहद संतुलित दिख रही है, लेकिन पिछले सीजन और पिछले दो मैचों में मलिंगा ने अपनी कहर बरपाती गेंदों से विपक्षी टीमों को जोरदार झटका दिया है. मलिंगा के वापस जाने से कप्तान सचिन तेंदुलकर को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा. मुनाफ पटेल के अलावा उनके पास कोई जाना–माना गेंदबाज नहीं है. ऐसे में गेंदबाजी सचिन की टीम की कमजोरी बन जाएगी और विपक्षी टीमें इसका भरपूर फायदा उठा सकती हैं. श्रीलंका के स्टार खिलाड़ी दिलशान रॉयल चैलेंजर्स के अहम बल्लेबाज हैं, जिनकी कमी टीम को खल सकती है. इस समय बैंगलोर की टीम ठीकठाक दिख रही है और बल्लेबाजी भी मजबूत है, लेकिन दिलशान में मैच जिताने की जो क्वालिटी है, उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है. आक्रामक बल्लेबाजी, कलाइयों का बेहतर इस्तेमाल और सही टाइमिंग की वजह से दिलशान क्रिकेट के फटाफट स्वरूप के लिए बेहद फिट हैं और मैच जिताऊ खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. वह न केवल बल्लेबाजी, बल्कि बैकवर्ड प्वाइंट पर बिजली सी फुर्ती वाली फील्डिंग और बेहतरीन ऑफ स्पिन गेंदबाजी की बदौलत टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. श्रीलंकाई बोर्ड के ताजा फरमान से आईपीएल की कोच्चि टस्कर्स और डेक्कन चार्जर्स को तो जरूर तगड़ा झटका लगेगा. चार्जर्स अब तक अपने दोनों मुकाबले हार चुकी है और टीम में कोई भी बड़ा नाम ऐसा नहीं है, जो बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद कर सके. कैमरून व्हाइट इस समय बांग्लादेश के दौरे पर गई ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ हैं, जो जल्द ही चार्जर्स का हिस्सा बनकर टीम की डूबती नैया बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं. आईपीएल में पहली बार हिस्सा ले रही कोच्चि की टीम टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम मानी जा रही है. जयवर्धने के वापस जाने से इस टीम को स्टार खिलाड़ी और कप्तान गंवाना पड़ जाएगा. जाने–माने स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ही इकलौते ऐसे खिलाड़ी बचे हैं, जो आईपीएल–4 का अपना यह सत्र पूरा कर पाएंगे.

अब देखना यह है कि बीसीसीआई इस मामले में किस तरह की प्रतिक्रिया देता है. श्रीलंका की मीडिया की मानें तो इससे विस्फोटक स्थिति बनेगी और क्रिकेट बोर्ड के बीसीसीआई से संबंध काफी तनावपूर्ण हो जाएंगे. आर्थिक रूप से मजबूत बीसीसीआई काफी प्रभावशाली है और आईसीसी के निर्णयों को अक्सर प्रभावित करता है. लेकिन इन सबको देखते हुए इतना तो तय हो गया है कि मुनाफे और वर्चस्व की लड़ाई में क्रिकेट और क्रिकेटर दोनों उलझे हुए हैं.

rajeshy@chauthiduniya.com

आईपीएल की अधिकतर टीमें ऐसी हैं, जो अपने हिस्से के आधे लीग मैच खेल चुकी हैं और टूर्नामेंट के अहम दौर में पहुंचने वाली हैं. श्रीलंकाई क्रिकेटरों के वापस लौटने से आईपीएल की अधिकतर टीमों को इनकी भरपाई करने में दिक़्क़त आ रही है.

महिंदानंद अलुथगामगे

Now, mixing business with pleasure makes perfect business sense.

FORTUNE Inn Grazia BY WELCOMGROUP Noida

Welcome to Fortune Inn Grazia, Noida - an elegant, upscale, full-service business hotel. It is strategically located in the heart of the city and in close proximity to Sector 18, the commercial and shopping hub of Noida. The hotel offers everything from contemporary accommodation and exciting dining options to, of course, comprehensive facilities for business and leisure. All to meet the growing needs of the new-age business traveller.

Block-I, Plot No. 1A, Sector-27, Noida - 201301, Uttar Pradesh, India. Tel: 0120-3988444, Fax: 0120-3380144, E-mail: grazia@fortunehotels.in, Website: www.fortunehotels.in

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 25 अप्रैल-01 मई 2011

बॉलीवुड में अभी तक ऑफ बीट रोल्स से तारीफ़ बटोरने वाली चित्रांगदा पहली बार फुल कमर्शियल प्रोजेक्ट में नज़र आएंगी.

छोटे पर्दे की मुश्किलें

फिल्मों में काम न मिलने की वजह से बॉलीवुड अभिनेत्रियां छोटे पर्दे पर अधिक नज़र आने लगी हैं. ऐसा ही कुछ प्रीति जिंटा ने किया. उन्होंने छोटे पर्दे की ओर क़दम बढ़ा लिए हैं. बहुत जल्द वह गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड के भारतीय संस्करण शो में होस्ट करती नज़र आ रही है. प्रीति की फिल्म रिलीज़ हुए काफी लंबा अर्सा बीत चुका है. उन्होंने आईपीएल और नेस वाडिया के चक्कर में अपने एक्टिंग करियर को ताख पर रख दिया. उन्हें लगा कि वह फिल्में बाद में साइन करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बॉलीवुड में अब नई-नई अभिनेत्रियों का आगमन हो चुका है. प्रीति के साथ काम करने वाले शाहरुख़, आमिर और सलमान भी नई एवं युवा अभिनेत्रियों में रुचि लेने लगे. प्रीति ने ख़ूब कोशिश की कि बाद में उन्हें फिल्म मिल जाएं, लेकिन यह संभव नहीं हो सका. प्रीति ने छोटे पर्दे का दामन यह सोचकर थामा, क्योंकि उन्हें बड़े पर्दे पर कोई पूछ नहीं रहा था. उन्होंने सोचा कि छोटे पर्दे पर काम करेंगी तो वह लोगों की निगाहों में बनी रहेंगी. लोगों को लगेगा कि उनके पास काम है. स्टेडियम में जब वह खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाती नज़र आती हैं तो दर्शक उन्हें बेरोज़गार समझ लेते हैं. अब प्रीति को महसूस होने लगा है कि टीवी पर काम करना बहुत कठिन है. उनका कहना है कि फिल्मों में काम बहुत धीमे तरीक़े से होता है, बहुत आराम रहता है, लेकिन टीवी की दुनिया की बात बहुत अलग है. यहां बिना रुके लगातार काम करना पड़ता है, समय का ध्यान रखना पड़ता है. प्रीति को टीवी कलाकारों का दर्द समझ में आ गया है और उनके प्रति सहानुभूति होने लगी है. लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत.

फिल्म प्रीव्यू

चलो दिल्ली

अभिनेत्री लारा दत्ता से शादी रचाने वाले भारतीय टेनिस स्टार महेश भूपति बॉलीवुड में बतौर प्रोड्यूसर अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं. उनकी फिल्म चलो दिल्ली में लारा दत्ता और कॉमेडियन विनय पाठक मुख्य भूमिका में होंगे. फिल्म को महेश भूपति के बिग डैडी प्रोडक्शंस और लारा दत्ता के भीगी बसंती प्रोडक्शन ने इरोज इंटरनेशनल के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. दस विदानिया जैसी संवेदनशील फिल्म से पहचान बना चुके निर्देशक शशांत शाह की मानें तो यह फिल्म अलग-अलग दुनिया से ताल्लुकात रखने वाले दो लोगों की कहानी है, जिसके ज़रिए असली भारत और उसके भांति-भांति के लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है. संगीत गौरव दासगुप्ता, आनंदराज आनंद और सचिन गुप्ता ने दिया है. आगामी 29 अप्रैल को रिलीज हो रही चलो दिल्ली एकदम नई स्टार कास्ट वाली फिल्म है. यह आम ज़िंदगी से जुड़ी कहानी पर आधारित है, जो दर्शकों को गुदगुदाएगी. इसमें कई ऐसे कलाकार भी दिखेंगे, जो अब तक थिएटर करते रहे हैं. इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड के एमडी सुनील लूला का कहना है कि चलो दिल्ली एक ऐसा सफर है, जिसमें दो किरदार असल और रंग-बिरंगे भारत के दर्शन कराएंगे. इसमें कई मजेदार लोग भी होंगे.

बिग डैडी प्रोडक्शंस के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश भूपति का कहना है कि इरोज इंटरनेशनल की दुनिया भर में मौजूदगी के चलते उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस फिल्म को विश्वव्यापी मंच पर पेश कर सकेंगे. फिल्म की स्क्रिप्ट पर हमें पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि दर्शक भी इसे पसंद करेंगे. फिल्म की शूटिंग जयपुर, दिल्ली और मुंबई में हुई और यह पोस्ट प्रोडक्शन दौर में है. फिल्म के बजट के बारे में इरोज इंटरनेशनल के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर राम मीरचंदानी बताते हैं, चलो दिल्ली 5 करोड़ रुपये के बजट में बनी है, क्योंकि हम एक सफल फिल्म चाहते थे. चलो दिल्ली एक मस्ती भरा सफर है, जिसमें एक बेमेल जोड़ी है और सफर रोमांच, पागलपन और हंसी की बौछार से सराबोर है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

रिया के नखरे

अभिनेत्रियों के पास चाहे फिल्में हों या नहीं या वह बिल्कुल फ्लॉप रही हों, तब भी नखरे दुनिया भर के होते हैं. जो उन्हें अच्छा लगेगा, वही करेंगी. ऐसा ही कुछ बांग्ला ब्यूटी रिया सेन ने किया. उनके पास इस समय फिल्मों का अकाल है, लेकिन नखरे कमाल के हैं. इन दिनों वह सुरेश भगत की फिल्म ए स्ट्रेंज लव स्टोरी में काम कर रही हैं, लेकिन सुरेश को रिया के साथ काम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. रिया ने उनसे तीन लाख रुपये की ड्रेस की डिमांड की तो उन्होंने मना कर दिया. इस पर रिया नाराज़ होकर शूटिंग बीच में ही छोड़कर चली गईं. इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल पूरी होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई. रिया ने सुरेश के ख़िलाफ़ सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में शिकायत भी की, लेकिन एसोसिएशन ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टीवी प्रोग्राम ने कहा कि रिया ने उसके साथ बदतमीजी की है. यहां तक कि उसे डुप्लीकेट के सहारे अपनी फिल्म पूरी करनी पड़ी और अब वह डबिंग आर्टिस्ट की तलाश में है, जो रिया के संवाद डब कर सके. हो सकता है, रिया ने ऐसा इसलिए किया हो कि अगर फिल्म फ्लॉप हो भी जाए तो दोष उन्हें न दिया जाए. वह कह सकती हैं कि काम उन्होंने पूरा नहीं किया है. इस घटना से सुरेश बहुत नाराज़ हैं. कहीं रिया को अपना नखरा महंगा न पड़ जाए. क्या होता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

विद्या की शानदार शुरुआत

फिल्म परिणीता से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाली विद्या बालन के लिए यह साल काफी लकी साबित हो रहा है. उन्हें काफी फिल्में मिल रही हैं. फिल्म नो वन किल्ड जेसिका से उन्हें काफी सराहना भी मिली. ग़ौरतलब है कि वह जल्द ही एक और वुमेन ओरिएंटेड फिल्म में आने की तैयारी कर रही हैं. वह मिलन लूथरिया की फिल्म डर्टी पिक्चर में एक नए अवतार में नज़र आने वाली हैं. ज़्यादातर साड़ी पहनने वाली विद्या जल्द ही बोल्ड कॉस्ट्यूम्स में नज़र आने वाली हैं. वह इस चेंज ड्रेसिंग सेंस को लेकर काफी उत्साहित हैं. फिल्म में विद्या से काफी बोल्डनेस की उम्मीद की जा रही है. विद्या एक्सपेरिमेंटल मोड में हैं, रेग्युलर फिल्मों के अलावा वह बड़े बैनरों के साथ काम करके भी नाम कमा रही हैं. उम्मीद है कि सुजॉय घोष की आनेवाली फिल्म कहानी में भी विद्या बालन एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. इस फिल्म की शूटिंग के सेट पर विद्या ने यह भी साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ़ ऐक्टिंग में पारंगत हुई हैं, बल्कि फिल्म मेकिंग के गुर भी सीख चुकी हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें फिल्म के सेट पर फिल्म मेकिंग के टिप्स देते सुना गया. सुजॉय भी विद्या की इस मेहनतकश अदा पर ख़ूब फिदा हुए, एक तो दिल लुभा लेने वाली ऐक्टिंग स्टार उसके साथ फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन में भी हाथ साफ. इस फिल्म में विद्या प्रेगनेंट महिला का किरदार अदा कर रही हैं, फिल्म में उनके साथ कुछ नए कलाकार भी हैं जिन्हें कुछ मुश्किल सींस को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन विद्या ने बहुत ही धैर्य रखकर उन कलाकारों का साथ हर बार रीटेक होने पर दिया. हाल ही में वह थैंक यू में अक्षय की पत्नी कैमियो के रोल में दिखीं. यही नहीं, दम मारो दम में वह अभिषेक की पत्नी के रोल में नज़र आईं. विद्या ने फिल्म पा में भी अभिषेक के अपोजिट रोल निभाया था, और खुशी की बात यह है कि फिल्म पा दोनों सितारों के करियर की बढ़िया और हिट फिल्मों में शामिल हो गई है. अब देखना यह है कि इन दोनों फ़िल्मों से विद्या का करियर ग्राफ उन्हें कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है.

नए रोल में चित्रांगदा

चित्रांगदा सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2003 में फिल्म हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी से शुरू की. उन्होंने इस लीक से हटकर बनी फिल्म से काफी तारीफ़ बटोरी और बॉलीवुड में नाम भी कमाया. लेकिन अब बॉलीवुड का नेचर बदलता जारहा है, यहां भी साइंस फिक्शंस पर आधारित फिल्में अपनी पकड़ जमाती जा रही है. अच्छी बात तो यह है कि जहां फिल्म मेकर्स लॉजिकल कॉन्सेप्टस लेकर आ रहे हैं, वहीं एक्सटर्स भी एक्सपेरिमेंट्स को लेकर ओपन हो रहे हैं. ख़बर मिली है कि चित्रांगदा अपनी आने वाली फिल्म में कुछ ऐसा ही करने वाली हैं. यहां बात हो रही है रौशन कैम्प की धूम मचाने वाली साइंस फिक्शन फिल्म कृष के सीक्वल की, जिसमें चित्रांगदा फीमेल म्यूटैंट का रोल करती नज़र आएंगी. ग़ौरतलब है कि जींस के डीएनए के स्ट्रक्चर में बदल जाने से इंसान को म्यूटैंट कहा जाता है. बॉलीवुड में अभी तक ऑफ बीट रोल्स से तारीफ़ पाने वाली चित्रांगदा पहली बार फुल कमर्शियल प्रोजेक्ट में नज़र आएंगी. कृष-3 में दो अभिनेत्रियां होंगी. प्रियंका अपने कृष वाले रोल को करती दिखाई देंगी, वहीं चित्रांगदा इसमें म्यूटैंट के साथ नज़र आएंगी. उन्हें कृष-3 में उनकी हालिया रिलीज़ फिल्म ये साली ज़िंदगी देखने के बाद साइन किया गया था. इसकेअलावा वह रोहित धवन की फिल्म देसी ब्वॉयज में भी नज़र आएंगी. उम्मीद है कि चित्रांगदा को अपने साइंटिफिक रोल में भी सीरियस डांसिंग का मौक़ा ख़ूब मिलेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

महाराष्ट्र

दिल्ली, 25 अप्रैल-01 मई 2011

www.chauthiduniya.com

1 मई महाराष्ट्र दिवस पर विशेष

सिर्फ़ ताक़त बढ़ाने की सियासत

वैसे तो महाराष्ट्र को देश के विकसित राज्यों में शुमार किया जाता है, लेकिन इस राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन काफ़ी ज्यादा है. चाहे औद्योगीकरण का मामला हो, शिक्षा का हो या फिर खेतों में सिंचाई की सुविधा का, विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, पश्चिम-मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और मुंबई क्षेत्रों में बंटे महाराष्ट्र में ज़बरदस्त अंतर नज़र आता है. आख़िर इसके पीछे वजह क्या है?

प्रवीण महाजन

अभी 10 मार्च की ही बात है. महाराष्ट्र में चीनी कारखानों को अनुमति देने के मसले पर कैबिनेट की बैठक में भारी मतभेद के कारण फ़ैसला खटाई में पड़ गया. इस दौरान कांग्रेस के मंत्रियों ने मौजूदा क़ानून कायम रखकर कारखानों को खुलकर परमीशन देने की वकालत की तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्रियों ने दो कारखानों के बीच 15 किलोमीटर का फ़ासला बढ़ाकर 25 किलोमीटर करने और अब और ज़्यादा कारखानों को परमीशन न देने का क़ानून लागू करने की मांग की. फ़िलहाल राज्य में क़रीब 134 शक्कर कारखाने हैं और इनमें अधिकतर पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हैं. विदर्भ एवं कोंकण में नगण्य हैं. भारी मतभेद का मतलब क्षेत्रीय वर्चस्व से संबधित है. औद्योगिक इकाईयों को अपने जनाधार वाले क्षेत्रों में लगाने की होड़ पहले से ही रही है. इनमें पश्चिम महाराष्ट्र हमेशा बाजी मारता रहा है. पिछले दो दशकों में देश में सबसे ज़्यादा औद्योगिक निवेश प्रस्ताव महाराष्ट्र को मिले हैं. राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 में दावा किया गया है कि अगस्त 1991 से अगस्त 2010 के बीच औद्योगिक निवेश प्रस्ताव पाने में महाराष्ट्र अन्य राज्यों से आगे रहा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उद्योगों के गंतव्य के रूप में राज्य के प्रति आकर्षण की वजह बेहतर बुनियादी ढांचा, कुशल श्रमबल और स्थिर सामाजिक परिस्थितियां हैं. यहां तक कि देश में हो रहे निवेश में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 10 फ़ीसदी की है, जबकि रोज़गार सृजन में इसका योगदान 15 फ़ीसदी का है. फिर इस राज्य में बेरोज़गारी बढ़ने के पीछे आख़िर क्या कारण हो सकते हैं. विदर्भ, कोंकण तथा खानदेश की दयनीय स्थिति क्षेत्र विशेष को तरजीह देने का ही परिणाम है. और हक़ीक़त यही है कि रोज़गार के अवसरों का सृजन होने के बावजूद यहां के बेरोज़गार या तो पलायन करने लगे हैं या रोज़गार के अभाव में जान देने लगे हैं.

अब सिंचाई का ही मामला लें. पुणे संभाग में 1994 से जून 2009 तक सिंचाई क्षमता 12 लाख 90 हज़ार 950 हेक्टेयर बढ़ी है. जो प्रतिशत के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र के बैकलाग के बराबर प्लस में है. कोल्हापुर संभाग में 1994 में सिंचाई क्षमता 501460 हेक्टेयर में थी, जो 2009 में बढ़ कर 9,62,990 हो गई. यहां 4,18,300 हेक्टेयर में खेती की जाती है. अब आते हैं अमरावती संभाग पर. अमरावती संभाग में 31,37,600 हेक्टेयर में खेती होने के बावजूद 2009 तक यहां सिर्फ़ 8,39,980 हेक्टेयर में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाई थी. यहां का सिंचाई बैकलाग पूरे राज्य में सबसे अधिक यानी 6.21 फ़ीसदी है. मराठवाड़ा संभाग का सिंचाई बैकलाग 2.44 जबकि नाशिक संभाग का 3.17 फ़ीसदी है. प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी यही स्थिति है. राज्य के 11 ज़िले ऐसे हैं, जहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत (46,492 रुपए वार्षिक) से भी कम है. राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय 74,027 रु. प्रति वर्ष है. नागपुर, रायगड़, ठाणे, पुणे, मुंबई की ही प्रति व्यक्ति आय राज्य के औसत से अधिक है.

वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट जारी होने के कुछ घंटों के भीतर कृषि विज्ञानी एम.एस. स्वामीनाथन ने आर्थिक सर्वेक्षण के हवाले से बताया था कि बैंक से क़र्ज़ मिलने की जटिल प्रक्रिया होने के कारण 46 प्रतिशत से अधिक किसान साहूकारों से ऋण लेते हैं. विदर्भ क्षेत्र में किसानों की आत्महत्याओं को किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा के तौर पर देखा गया है, वहां एक एकड़ ज़मीन पर चार हज़ार रुपए से अधिक बैंक ऋण नहीं देता, जबकि पश्चिम महाराष्ट्र में इतनी ही ज़मीन पर तीस हज़ार रुपए क़र्ज़ मिलता है. ऐसे में दोनों को एक तराजू में तौलना नीतिगत दोष की ओर इशारा करता है. किसी दौर में विकास दर सर्वाधिक अर्जित करने वाला प्रदेश विकास की रपट पट्टी पर नीचे की ओर सरकते जा रहा है, क्योंकि औद्योगिक विकास जमकर होने के बावजूद यहां की सरकारों ने अपने ही नागरिकों के साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया है. दोयम दर्जे का व्यवहार और सुविधाओं की कमी के कारण महाराष्ट्र के नक्शे पर आड़ी-तिरछी लक़ीरें अब उभरने को बेताब है.

स्थापना का एक और वर्ष बीतने को है. औपचारिकताएं निभाई जाएंगी. हालात से दूर शासन का गुणगान होगा. किसी को इस बात से कोई वास्ता नहीं कि अनुशेष क्यों बढ़ता जा रहा है. क्षेत्रीय असंतुलन की खाई क्यों इतनी चौड़ी होती जा रही है. रोना तब भी था, आज भी जारी है. एक ही प्रदेश में हिस्से-हिस्से पर डाका डालने की नीयत नहीं रहती तो विदर्भ का बैकलॉग नहीं बढ़ता, बिजली की समस्या नहीं होती, किसान आत्महत्या नहीं करते, सिंचन व्यवस्था बैगलॉग नहीं बढ़ता और रोज़गार की समस्या पर ध्यान दिया जाता तो आज पृथक विदर्भ की मांग नहीं उठती. आख़िर ऐसा क्यों न हो न सका? ऐसे में क्षेत्रीय असंतुलन को कैसे नकारा जा सकता है? पिछले कुछ सालों पर नज़र दौड़ाएं तो यह साफ़ नज़र आता है. सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं के पास ही होते हैं, विदर्भ के मंत्रियों के पास कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं होता.

भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के गत अधिवेशन में इस आशय का खुला ऐलान करके सनसनी फैला दी थी कि महाराष्ट्र में ही विदर्भ वालों के साथ भिखारियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है. गत वर्ष 20 मार्च की यह घटना है. राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी थी कि विदर्भ, कोंकण और मराठवाड़ा जैसे इलाक़ों के लिए बनाए गए वैधानिक विकास बोर्ड को रद्द करने की मांग उठी. इस संवेदनशील मुद्दे पर सत्ता दल के सदस्यों ने भी महाराष्ट्र में विकास को लेकर विदर्भ पर हो रहे अन्याय के पक्ष में आवाज़ उठायी और विकास के लिए करोड़ों रुपये उपलब्ध कराने वाले बोर्ड को रद्द न करने की चेतावनी दी. पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं पर उंगली उठाई जाती है, मगर वे हर बार तेज़ निकलते हैं. उनके तरीके बदल जाते हैं. धीरे-धीरे ऐसे तरीक़ों ने ही महाराष्ट्र की सूरत बदल दी है. नब्बे के दशक में देश के शीर्ष पांच राज्यों में रहने वाला महाराष्ट्र इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में उत्पादकता के मामले में टॉप टेन राज्यों में भी स्थान नहीं बना पा रहा है. सत्तर और अस्सी के दशक में जब राज्य में सर्वाधिक विकास दर का दौर था, तब राज्य ने जनसेवाओं के मद में ठीक से निवेश नहीं किया, जिसके कारण राज्य के निवासियों के जीवनस्तर में कोई सुधार नहीं आया. मुंबई परिक्षेत्र को छोड़ दें तो पूरे राज्य में नागरिकों की दशा दयनीय है. रोज़मर्रा की ज़रूरतें आज भी इनके लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं. कहने में कोई हर्ज नहीं कि 105 लोगों की शहादत और लंबे संघर्ष के बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बना, लेकिन इक्यावन साल बाद अगर बची है तो सिर्फ़ ताक़त बढ़ाने की सियासत, जो इस प्रदेश के हर वर्षगांठ पर तेज़ हो जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

संवेदनशील मुद्दे पर सत्ता दल के सदस्यों ने भी महाराष्ट्र में विकास को लेकर विदर्भ पर हो रहे अन्याय के पक्ष में आवाज़ उठायी और विकास के लिए करोड़ों रुपये उपलब्ध कराने वाले बोर्ड को रद्द न करने की चेतावनी दी. पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं पर उंगली उठाई जाती है, मगर वे हर बार तेज़ निकलते हैं. उनके तरीके बदल जाते हैं. धीरे-धीरे ऐसे तरीक़ों ने ही महाराष्ट्र की सूरत बदल दी है.

Shri Sachhidanand Shikshan Sanstha's

TAYWADE GROUP OF INSTITUTIONS

ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, KORADI

- B.A. (English, Marathi, Hindi Medium)
- B.Com. (English, Marathi, Hindi Medium)
- B.Sc. (Microbiology, Chemistry, Botany, Zoology, Computer Science, Physics, Maths)
- B.C.A. (Bachelor of Computer Application)
- B.C.C.A. (B.Com.(Computer Application)
- B.B.A. (Bachelor of Business Administration)

BHAURAOJI TAYWADE POLYTECHNIC KORADI
Approved by AICTE, DTE & Govt of Maharashtra

First Year Admission to Diploma Courses
Eligibility SSC (X) Passed candidates with 50% for Open & 45% for Reserved Category

BRANCHES
Civil Engineering
Computer Engineering
Electronics Engineering
Mechanical Engineering
Electrical Engineering
Chemical Engineering
Electronics & Telecommunication

Direct 2nd Year Admission
Eligibility HSC (Tech / Vocational) 50% for Open & 45% for Reserved Category HSC (MCVC) 60% ITI (2 yr course) 60%

Free Admission to SC/ST/DT/NT/VJ Students
50% Fees to OBC students

Salient Features :
• Sprawling Campus with separate playgrounds for different Outdoor Sports & independent Cricket Ground • Rich Central Library and independent study center. • State of

COUNSELING CENTER : COLLEGE CAMPUS KORADI, NAGPUR
COUNSELING CENTER OPEN FOR ALL DAYS INCLUDING SUNDAY & HOLIDAY
Contact for Admission : 9822716608, 9822703052, 9422102613, 9422145290, 07109-262204/262525

ARTS, COMMERCE & SCIENCE Jr. COLLEGE, KORADI
XI & XII
• ARTS (Marathi)
• Commerce (English, Marathi)
• Science with Biofocal (Electronics, Computer Sci)

COLLEGE OF PHARMACY, KORADI
Approved by AICTE, DTE & Govt of Maharashtra

B. Pharm. (1) First Year
Eligibility : (i) HSSC Science pass with 50% marks in PCB/PCM group (45% for Reserved category) & appeared in MHT-CET-2010 Or (ii) D.Pharm. pass with 50% Marks D.Pharm II year or (iii) Eligible as (i) without MHT-CET 10.

SACHHIDANAND INSTITUTE OF DIPLOMA IN PHARMACY, KORADI
Approved by AICTE, DTE & Govt of Maharashtra

D. Pharm
Eligibility : HSSC (STD XII) Science pass with

COLLEGE OF EDUCATION, KORADI
B.Ed. M.Ed.

ADHYAPAK VIDYALAYA, KORADI
D.T.Ed.

SHARIRIK SHIKSHAN MAHAVIDYALAYA, KORADI
B.P.E. B.P. Ed.

Shankarrao Chavhan Polytechnic College, Butibori (Proposed)

Dr. Baban Taywade
Chairman

एक मराठीभाषी प्रधानमंत्री चाहिए

सभी फोटो–प्रभात पाण्डेय

महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार मराठा नेता एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार को माना जाता रहा है. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने शरद पवार को प्रधानमंत्री पद के लिए खुला समर्थन देने की घोषणा की थी. राजनीतिक पंडितों को पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार ने इस पद को पाने की भरसक कोशिश की थी. उस वक़्त एनकेपी साल्वे ने उनकी मदद की थी, लेकिन पवार का मिशन सफल नहीं हो सका.

महाराष्ट्र की स्थापना की 50 वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है. मई 1960 को भाषावार प्रांत रचना के तहत महाराष्ट्र का गठन किया गया था. महाराष्ट्र में मुंबई तथा सीपी एंड बेरार प्रांत को शामिल किया गया था. मुंबई को राज्य में शामिल करने के लिए 105 संयुक्त महाराष्ट्रवादियों ने अपने जीवन की आहुती दी थी. मुंबई के साथ तत्कालीन मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर को भी ल में सम्मिलित किया गया था. आज मुंबई न केवल महाराष्ट्र की राजधानी है, बल्कि इसे देश की आर्थिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है.

इन 50 वर्षों में महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व प्रदान किया है. स्व. यशवंतराव चव्हाण, स्व. पंजाबराव देशमुख, स्व. शंकरराव चव्हाण ने महाराष्ट्र का नाम राष्ट्रीय राज में गर्व से ऊंचा किया है. इसी राज्य से शिवराज पाटील तथा मनोहर जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष जैसे गरिमामयी पद की शाोभा बढ़ाई है. एनकेपी साल्वे तथा वसंत साठे जैसे कद्दावर नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं. इन नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर देश की सेवा की, किंतु प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बन पाए.

मराठी भाषियों की हमेशा इच्छा रही है कि राजनीति के सर्वोच्च पद पर महाराष्ट्र से कोई आसीन हो. ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के किसी नेता को देश का सर्वोच्च पद प्राप्त नहीं हुआ. वर्तमान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील महाराष्ट्र के पिछड़े इलाके अमरावती की हैं. उन्हें देश की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है.

महाराष्ट्र की जनता गत कई वर्षों से एक ही सवाल कर रही है कि क्या वह किसी मराठीभाषी को प्रधानमंत्री के रूप में देख पाएगी? क्या महाराष्ट्र का एक भी नेता इस पद पर आसीन नहीं हो सकता? देश को सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से मिले हैं. इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा आसाम जैसे प्रदेशों से भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं. वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए हैं.

महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार मराठा नेता व राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार को माना जाता रहा है. महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने शरद पवार को प्रधानमंत्री पद के लिए खुला समर्थन देने की घोषणा की थी. राजनीतिक पंडितों को पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार ने इस पद को पाने की भरसक कोशिश की थी. उस वक़्त एनकेपी साल्वे ने उनकी मदद की थी, लेकिन पवार का मिशन सफल नहीं हो सका. कांग्रेस पार्टी ने पीवी नरसिंहराव को प्रधानमंत्री चुना था. सन 2009 में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाने का अभियान फिर एक बार तेज़ किया था. राजनीतिक पंडितों की मानें तो पवार की मंशा त्रिशंकु सरकार की स्थिति में विभिन्न दलों में कैसे अपने मित्रों की सहायता से सरकार बनाने की थी, किंतु बिल्ली के भाग्य से छींका नहीं फूटा और वह अपना मन मसोस कर रह गए. कांग्रेस के नेतृत्व संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार–2 को ज़बरदस्त कामयाबी मिली. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में ही सिमटकर रह जाना पड़ा. अब शरद पवार ने तो प्रधानमंत्री बनने के मंसूबे त्याग दिए, जान पड़ता है कि उनको अपनी तथा पार्टी की सीमित मर्यादाओं का भान हो गया है. राष्ट्र का नेतृत्व भरने के लिए मुट्ठीभर सांसद नहीं बल्कि सांसदों की लंबी फ़ौज चाहिए.

देखा जाए तो महाराष्ट्र से ऐसा कोई नेतृत्व फ़िलहाल नज़र नहीं आता है जो डॉ. मनमोहन सिंह की सत्ता बदलने के बाद उभरे. यदि गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी सत्ता की कुंजी हाथ में लेते हैं तो महाराष्ट्र के कांग्रेसियों को स्वप्न में भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं आएगा. हालांकि कांग्रेस हाईकमान यदि भविष्य में महाराष्ट्र को मौक़ा देने का विचार करे, तो 10 जनपथ के क़रीबी समझे जाने वाले शिवराज पाटील को स्थान मिल सकता है. सोनिया गांधी ने शिवराज पाटील को लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री पद की महती जवाबदारी संप्रग सरकार–प्रथम के शासनकाल में दी थी. मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के चलते उनको अपने पद की कुर्बानी देनी पड़ी. संप्रग–2 के गठन के समय उनको दरकिनार कर दिया गया था. कांग्रेस में यदि इस पद का कोई दूसरा दावेदार महाराष्ट्र से हो सकता है तो वह हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे. शिंदे भी मैडम सोनिया की गुड बुक में शामिल हैं. एक सामान्य पुलिस कर्मचारी से राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री पद का सफ़र तय करने वाले शिंदे को महाराष्ट्र का बड़ा दलित नेता माना जाता है.

भाजपा से नितिन गडकरी फ़िलहाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. नितिन गडकरी दिल्ली की राजनीति में अपनी जड़ें मज़बूत कर रहे हैं. दिल्ली की राजनीतिक बिसात में वे अब नए मोहरे नहीं रहे. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघे के मज़बूत सहारे के कारण उनको इस पद का मज़बूत दावेदार माना जा सकता है. महाराष्ट्र के पिछड़ावर्ग के नेता गोपीनाथ मुंडे को लोकसभा में विपक्ष का उपनेता बनाया गया है, लेकिन वे प्रधानमंत्री पद की रेस में नज़र नहीं आते और उनको महाराष्ट्र की राजनीति करने में ही आनंद आता है. इन दोनों के अलावा कोई ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, जिसकी ओर जनता आशा भरी निगाहों से देखे. प्रादेशिक दल यदि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात करें, तो दोनों पार्टियां आपस में एक–दूसरे की खच्ची करने में लगी हैं. शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे फ़िलहाल अपनी पार्टी की साख बृहन्मुंबई महानगर पालिका के आगामी चुनाव में बचाने मे लगे हैं. मनसे नेता राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है. दोनों दलों के सीमित संसाधन व राष्ट्रीय राजनीति में कम दखलंदाज़ी होने के कारण उनका दावा नज़र नहीं आता.

महाराष्ट्र में विचारवान, प्रगतिशील नेताओं की कमी नहीं है. प्रख्यात समाज सेवक अण्णा हजारे ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जनांदोलन छेड़कर संप्रग सरकार को हिला दिया. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र के हैं. लाखों दिलों पर राज करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर महाराष्ट्र की पावन माटी की हैं. समाज के हर क्षेत्र में महाराष्ट्र ने बाज़ी मारी है. यहां की जनता की मनोकामना है कि महाराष्ट्रीयन व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो. यह इच्छा कब पूरी होगी, अभी बता पाना मुश्किल है.

नंदिता सोनी
feedback@chauthiduniya.com

SANMARG SHIKSHAN SANSTHA

Our other Institutes

- Smt. Radhikatai Pandav College of Engineering, Nagpur
- Shri K. R. Pandav Dental College & Hospital, Bhandara
- Shri K. R. Pandav Ayurved Mahavidyalaya & Hospital, Nagpur
- Shri K. R. Pandav Polytechnic, Nagpur
- Shri K. R. Pandav Institute of Pharmacy, Nagpur
- Late Vasantdada Polytechnic (Part time YCMOU, Nashik)
- Shri Vasant B.Ed. College, Nagpur
- Shri Vasant D. Ed. College, Nagpur
- Shri K. R. Pandav Adhyapak Vidyalaya, Nagpur
- Late Vasantrao Naik B.P. Ed. College, Nagpur
- Late Vasantrao Naik B.P.E. College, Nagpur
- Late Mahadeorao Mahalle I.T.I., Nagpur
- St. George Convent, Hanuman Nagar, Nagpur
- Vision Center for Advance Computing Development, Nagpur
- Master of Labour Studies, Nagpur
- Radhika Vidya Bhawan, Nagpur
- Pandav College of Lib. & Information Science, Nagpur (Courses Offered - B.Lib.I.Sc., M.Lib.I.Sc.)
- Shri K. R. Pandav Mahavidyalaya, Nagpur (Courses Offered - B.C.S., B.C. A., B.B.A., B.Tech. (Applied Electronics), M.C.M., P.G.D.C.C.A., P.G.D.B.M., P.G.D.T.)

Founder & President of Sanmarg Shikshan Sanstha. Hon. Shri Krishnarao Pandav, Ex-Mayor Of Nagpur City, Ex- Member of Maharashtra State Legislative Council

Secretary Hon. Shri Kiran Pandav, Ex. President, Rashtrawadi Vidyarthi Congress (Maharashtra State), Ex-Vice President, N S U I, Nagpur, Ex-Chairman, Nagpur University

Treasurer Hon. Shri Girish Pandav, Senate Member, Nagpur University

NEAR DIGHORI NAKA, UMRER ROAD, NAGPUR-441 204 (M.S.)
✆ : 0712-3247108, 9373137424, 9373137540 FAX : 91-07103-276190 www.rpce.org email : info@rpcenagpur.org

सरकारी संरक्षण का अभाव

50 गिद्ध भी नहीं बचे

पर्यावरण प्रेमियों के लिए बुरी ख़बर है. पक्षी प्रेमियों की गिद्धों को बचाने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं. एक सर्वे के मुताबिक़ पूरे महाराष्ट्र में क़रीब 47 गिद्ध बचे हैं. क़रीब डेढ़ साल पहले गिद्धों की संख्या 200 आंकी गई थी. देश में गिद्धों की 179 प्रजातियां भूख और बीमारी के कारण विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं. इन प्रजातियों में व्हाइट बेक्ड, लांग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड प्रजातियां प्रमुखता से शामिल हैं. इस तेज़ी से विलुप्त होते गिद्ध वर्ष 2012 तक महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि प्रांतों से पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएंगे. 2015 तक पूरे भारतवर्ष से इनका नामोनिशान मिट जाएगा. केवल मृत जीव के मांस पर निर्भर रहने वाले गिद्धों की विलुप्ति 21वीं सदी के पर्यावरणीय इतिहास में बहुत बड़ी क्षति साबित होगी, क्योंकि गिद्धों की विलुप्ति एक पक्षी मात्र की विलुप्ति नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि मानवीय कचरे से पर्यावरण किस प्रकार ज़हरीला और जीवों के प्रतिकूल हो गया है. वर्तमान में गिद्ध रेस्क्यू और प्रजनन केंद्रों में ही सुरक्षित रह पा रहे हैं. गिद्धों की विलुप्ति में लोगों का जागरूक न होना और सरकारी लापरवाही दोनों ज़िम्मेदार हैं. महाराष्ट्र में गिद्धों को बचाने की दिशा में क़रीब डेढ़ साल पहले पर्यावरण प्रेमियों ने गढ़चिरोली ज़िले में रेस्क्यू कम ब्रीडिंग सेंटर (बचाव और सुरक्षित प्रजनन केंद्र) का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, पर वन विभाग के आला अधिकारियों ने केवल औपचारिकता निभाकर अपना पल्ला झाड़ लिया. गिद्धों के संरक्षण के लिए काम कर रही संस्था नेशनल एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स एंड रिसर्च के सचिव डॉ. अजय पोहरकर ने बताया कि पिछले वर्ष तक इनकी अनुमानित संख्या केवल 200 पाई गई थी, जिनमें से 80 गिद्ध गढ़चिरोली और 15 गिद्ध नागपुर ज़िले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मिले थे. उन्होंने गिद्धों की लगातार कम होती संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र वन विभाग के तत्कालीन प्रधान मुख्य वन सरंक्षक बी. मजूमदार को गिद्धों की बुरी स्थिति से अवगत कराया था और उन्हें केंद्र सरकार के मातहत काम करने वाली ग़ैर–सरकारी संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) द्वारा गढ़चिरोली में एक बचाव और प्रजनन केंद्र स्थापित करवाने की मांग की थी. लंबे समय के बाद मजूमदार ने उन्हें यह प्रस्ताव सरकार को भिजवाने की जानकारी दी थी. पर बाद में इसका कोई भी निष्कर्ष सामने नहीं आया तथा इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया. प्राणी और पादप के तंत्र में गिद्ध सबसे ऊपर के भोक्ता हैं. वह केवल मांस खाकर जीवित रहते हैं. यानी वह भोजन श्रृंखला में बाघ के समकक्ष हैं. आज बाघ वन विभाग द्वारा निर्धारित विलुप्तप्राय प्राणियों के श्रेणी विभाजन में सबसे ऊपर यानी प्रथम श्रेणी में हैं. यह श्रेणी क्रिटिकल एनडेंजर्ड की श्रेणी में आते हैं. सरकार और दुनिया भर की ग़ैर–सरकारी संस्थाएं बाघों को बचाने के लिए कराड़ों रुपए ख़र्च कर रही हैं. गिद्धों की संख्या बाघों से भी अधिक तेज़ी से कम हो रही है, लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान बहुत कम है. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा गिद्धों को बचाने के लिए बचाव और प्रजनन केंद्र चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं कहे जा सकते हैं.

कौवों के लिए मौत का पैग़ाम

गिद्धों की तरह कौवों की संख्या भी अनेक स्थानों पर घट रही है तो कहीं बढ़ रही है. यह कहीं केंद्रित तो कहीं विरल हो रहे हैं. डॉ. पोहरकर बताते हैं कि गिद्धों की विलुप्ति का कारण केवल मृत मवेशियों के मांस में पाई जाने वाली दवा डाइक्लोफिनेक का सेवन करना नहीं है बल्कि मलेरिया, किडनी फेल होना और भूख भी है. इस स्थिति को देखते कहा जा सकता है कि आने वाले दशक कौवों के लिए मौत का पैग़ाम लाने वाले हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पारदर्शिता की पटरी पर विकास यात्रा

मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है. यह विश्व का आर्थिक केंद्र हो, इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूं. मुंबई जैसे महानगरों के मुद्दे हट कर हैं. मुंबई जैसे शहर में लोग चुंबक की तरह खिंचे चले आते हैं. इसका भार यहां की नागरिक सुविधाओं पर पड़ता है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर नियोजन करना पड़ता है.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभाले पांच महीने पूरे हो चुके हैं. महाराष्ट्र दिवस के पूर्व चौथी दुनिया ने राज्य के विकास के प्रति उनके दृष्टिकोण पर एक ख़ास बातचीत की. प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश–

▶ क्या आप कोई मिशन लेकर चल रहे हैं?

मैंने जिन राजनीतिक परिस्थितियों में मुख्यमंत्री पद की बागडोर अपने हाथों में ली, वह सर्वज्ञात है. एक तो सरकार और राजनीति में उथल–पुथल चल रही थी तो दूसरी ओर प्रदेश में अतिवृष्टि और असामयिक वर्षा से फ़सलों को काफ़ी हानि पहुंची थी, किसी नए मुख्यमंत्री के लिए यह विकट समय था. लेकिन अब यह बीती बात हो गई. मेरा मानना है कि जो हो गया उस पर शोक करने की बजाय आगे क्या करना है, यह सोचना चाहिए. पिछले चार महीने में हमने महाराष्ट्र के बहुत से भागों और ज़िलों का दौरा किया. नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन अधिवेशन हुआ. मंत्रालय में लोकशाही दिन, जनता दरबार, मंत्रालय के दौरान मैं अनेक लोगों से मिला. इन मुलाकातों के बाद मुझे एक बात देखने को मिली कि आम जनता के मन में एक अविश्वास की भावना पैदा हुई है. कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होने वाला, ऐसी नकारात्मक भावना ने लोगों के मन में घर कर लिया है. नागरिकों के मन में फिर से विश्वास पैदा करने की चुनौती आज हम सबके सामने है. मैं नहीं मानता कि एक बार परिस्थिति बिगड़ गई तो वह कभी नहीं सुधरेगी. मुझे विश्वास है कि प्रामाणिक और सामूहिक प्रयासों से यह ज़रूर संभव होगा.

▶ राज्य में आपको कौन सी समस्याएं नज़र आती हैं?

महाराष्ट्र के सामने आज बहुत सारी समस्याएं हैं. विकास में क्षेत्रीय असंतुलन, सिंचाई परियोजनाएं, कृषकों के अनेक मुद्दे, बेरोज़गारी, सड़क आदि मूलभूत साधनों का विकास, बिजली की कमी, नक्सलवाद, समुद्र तटीय सुरक्षा, उद्योगों और निवेशकों की सुरक्षा आदि बहुत सी समस्याएं हैं. इन सभी को सुलझाकर महाराष्ट्र को देश में पहले स्थान पर लाना है. इनमें प्राथमिकता निश्चित करनी है. ये सभी मुद्दे किसी जादू की छड़ी से एक साथ नहीं सुलझने वाले हैं. मैंने इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए निश्चित अवधि के अंदर उपाय, योजनाएं और अनुमान तय करने के आदेश सभी सचिवों को दिए हैं. मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार कटिबद्ध है.

▶ आप अपने काम में किसे प्राथमिकता दे रहे हैं?

प्राथमिकता को ध्यान में रखकर हाल ही में दो बड़े निर्णय हुए हैं. नवी मुंबई में नये अंतरराष्ट्रीय विमानतल को और जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को मिली केंद्रीय वन और पर्यावरण विभाग की अनुमति, ये दो बड़े निर्णय हैं. मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है. यह विश्व का आर्थिक केंद्र हो, इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूं. मुंबई जैसे महानगरों के मुद्दे हट कर हैं. मुंबई जैसे शहर में लोग चुंबक की तरह खिंचे चले आते हैं. इसका भार यहां की नागरिक सुवधिाओं पर पड़ता है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर नियोजन करना पड़ता है. मुंबई महानगर की नागरिक सुविधाओं के मुद्दों पर प्राथमिकता से ध्यान देना होगा. मुंबई महानगरीय क्षेत्र के विकास का महात्वाकांक्षी कार्यक्रम मैंने अपने हाथ में लिया है.

▶ आप अपनी सरकार को किस दिशा में ले जाना चाहेंगे?

हमारे कार्य की दिशा महाराष्ट्र के संतुलित, न्यायपूर्ण और सामाजिक न्याय को लेकर चलने वाले विकास की ओर होगी. प्रशासन की पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी कामकाज के केंद्र बिंदु होंगे. भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, इसलिए सरकार राज्य की आर्थिक प्रगति और साधनों का विकास उसी गति से करने का प्रयास करेगी.

▶ सूचना अधिकार क़ानून को आप किस तरह देखते हैं?

केंद्र सरकार में रहते हुए चार साल मुझे सूचना अधिकार क़ानून क्रियान्वयन का अवसर मिला. प्रशासन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सूचना अधिकार क़ानून बनाया गया. देश के आर्थिक विकास के लिए प्रशासकीय पारदर्शिता आवश्यक है तथा बदलते दौर में प्रचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण है. मुझे लगता है कि समाज में जहां–जहां अच्छे काम चल रहे हैं, मीडिया पाठकों तक इसकी जानकारी पहुंचाता हैं और उसके सकारात्मक परिणाम होते हैं. यह ध्यान रखना चाहिए कि सूचना अधिकार जैसे प्रभावी हथियार के कारण प्रशासन की ग़लतियां खुलकर सामने आ जाती हैं. प्रशासन में पारदर्शिता लाने वाले इस क़ानून और आम जनता को मिले इसके अधिकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

▶ कोंकण, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा की समस्याएं अलग–अलग हैं. इन सभी को आप कैसे संजोएंगे?

कोंकण, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा आदि क्षेत्रों का भौगोलिक स्वरूप देखकर संतुलित विकास करना होगा. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, निरक्षरता भी ज़्यादा है–ऐसी परिस्थितियों में ही गठबंधन सरकार को काम करना है. इन क्षेत्रों का नियोजन करते हुए संतुलित और न्यायपूर्ण विकास करना होगा.

▶ बिजली की कमी दूर करने के लिए आप क्या क़दम उठाएंगे?

बिजली भारनियमन का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है. दस हज़ार मेगावॉट क्षमता वाले जैतापुर परमाणु ऊर्जा प्रकल्प को पर्यावरण विषयक मंजूरी मिलते ही हमने इस दिशा में ठोस क़दम उठाया है.

▶ कृषि क्षेत्र के लिए क्या योजनाएं हैं?

जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ वर्षों से देश के अनेक भागों में अनियमित और असामयिक वर्षा हो रही है. ऐसे में किसानों को नुक़सान भरपाई की स्थाई व्यवस्था के निमित्त फ़सल बीमा योजना को अधिक व्यापक बनाने हेतु केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है. वर्षा प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने तत्काल एक हज़ार करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है. विगत समय में मौसम परिवर्तन के कारण किसानों को नुक़सान सहना पड़ा. सड़कों को भी हानि पहुंची है. वर्षा और मौसम का अनुमान लगाना बहुत कठिन कार्य है. इसे देखते हुए केंद्र सरकार से अत्याधुनिक मौसम केंद्र स्थापित करने की विनती की गई है.

▶ कुपोषण से निपटने की क्या योजना है?

हमने मेलघाट में कुपोषण, बेरोज़गारी, पिछड़ापन ख़त्म करने का प्राथमिकता से निर्णय लिया है. मेलघाट और विदर्भ के पिछड़े ज़िलों के विकास पर भी मैंने गंभीरता से विचार किया है. अमरावती संभाग का मेलघाट क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा होने के कारण कुपोषण की विकट समस्या से ग्रस्त है. कुपोषण ख़त्म करने के लिए बालमृत्यु और मातृमृत्यु दर कम करने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए. इसके लिए शीघ्र ही योजनाएं आरंभ की जाएंगी. मेरा प्रयास केंद्र सरकार की ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, व्याघ्र प्रकल्प जैसी परियोजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना रहेगा. व्याघ्र प्रकल्प देश का एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है. इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे. इस परियोजना के तहत गांवों के पुनर्वास कार्यों को गति देने का निर्णय मैंने लिया है.

जनता को मुझसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं

एक विशेष परिस्थिति में मैंने मुख्यमंत्री पद की बागडोर हाथ में ली थी, इस कारण जनता को मुझसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं. लोगों के काम तेज़ी से, पारदर्शिता और अनुशासनबद्ध तरीके से करने की ज़रूरत है. आज लोगों के मन में सरकार और प्रशासन को लेकर संदेह व्याप्त है. मुझे इस संदेह को समाप्त कर महाराष्ट्र को फिर एक बार गौरवशाली प्रदेश बनाना है.

विकास के भरपूर अवसर

जैसी हमारे सामने चुनौतियां हैं, वैसे ही विकास के अवसर भी बहुत ज्यादा हैं. मैंने अवसरों का भरपूर लाभ लेकर विकास की दौड़ जारी रखने और जनता के सामने पारदर्शी सरकार की छवि पेश करने का निश्चय किया है. शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों से भी आम लोगों को मेरी ही तरह भिन्न अपेक्षाएं हैं. मैंने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि छोटी–छोटी बातों के लिए लोगों के काम न टाले जाएं, अधिकारी इसका बराबर खयाल रखें. ऐसा करने में यदि कार्यपद्धति में कुछ बदलाव करने पड़े तो वे निश्चित ही किए जाएंगे.

सतीश ललित
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र दिवस पर हार्दिक शुभ कामनाएं

रवि बालपांडे
जिला अध्यक्ष
वर्धा

महाराष्ट्र दिवस पर हार्दिक शुभ कामनाएं

अमर काळे
पूर्व आमदार
आर्वी

चौथी दुनिया
राष्ट्रीय साप्ताहिक चौथी दुनिया अब महाराष्ट्र से

राष्ट्रीय साप्ताहिक १६ पृष्ठों के साथ महाराष्ट्र के रंगीन ४ पृष्ठ
आज ही अपना अंक सुरक्षित करवाएं
मुंबई- 8097592411, पुणे- 9372922174, नागपुर- 9922412186
बुलढाणा- 9860933217, वाशिम - 9423430554, अकोला- 9822465812,
वर्धा- 9850738513, औरंगाबाद- 9762478014, यवतमाळ - 9767777917
महाराष्ट्र के लिए संपर्क : आशिर्वाद पब्लिकेशन प्रा. लि.
२७, पिसे कॉम्प्लेक्स, धंतोली रेलवे पुलियाँ, ग्रेट नाग रोड, नागपुर- ४४०००३
Ph.-0712- 2707414, 15 Fax:- 91-712-2752025 e-mail: chauthiduniyaa@gmail.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 25 अप्रैल–01 मई 2011

पत्रकारिता का सच वास्तव में एक जुनून है. इस क्षेत्र में खोने को बहुत कुछ है, मगर पाने के लिए मात्र संतुष्टि है.

चौथी दुनिया

महाराष्ट्र संस्करण का विमोचन

ऐतिहासिक संतरा नगरी के इतिहास में 9 अप्रैल का दिन एक और स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ गया, जब एक गरिमामय कार्यक्रम में चौथी दुनिया के महाराष्ट्र संस्करण का विमोचन हुआ. इस भव्य समारोह का साक्षी बना नागपुर का देशपांडे सभागृह. परम पूज्य राष्ट्र संत भैय्यूजी महाराज, पूर्व सांसद बनवारीलाल पुरोहित, राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा, वनराई के विश्वस्त गिरीश गांधी, नागपुर सुधार प्रन्यास के विश्वस्त आनंतराव घारड़, चौथी दुनिया के प्रमुख संपादक संतोष भारतीय, चौथी दुनिया के एडिटोरियल को–आर्डिनेटर डॉ. मनीष कुमार, चौथी दुनिया के उर्दू संस्करण की संपादक वासिम रशीद व शहर के गण–मान्य व्यक्तियों ने समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

प्रमुख अतिथि राष्ट्रसंत भैय्यूजी महाराज ने समाज में मीडिया की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने समाज में मीडिया को एक सशक्त प्रहरी निरूपित किया और कहा कि समाज से डर समाप्त करने में मीडिया सक्षम है. क्योंकि मीडिया समाज की संवेदनाओं को शब्दों में व्यक्त करता है. यह समाज का आईना है. समाज को दिशा देने के साथ ही समाज की विशेषताओं को भी सामने लाता है. उन्होंने संविधान के दो सशक्त स्तंभ न्यापालिका और मीडिया को वेदनाओं के समाधान का माध्यम निरूपित किया. उन्होंने कहा कि मीडिया समाज की वेदना सामने लाता है और न्यायपालिका उसे न्याय प्रदान करती है. देश में तेज़ी से पनपे उपभोक्तावाद, बाज़ारवाद का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में मीडिया की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है. बनवारीलाल पुरोहित ने क्षेत्रीय व सामाजिक असंतुलन का ज़िक्र करते हुए कहा कि सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत ही सर्वश्रेष्ठ है. उन्होंने चौथी दुनिया को आम जनता का सच्चा साथी निरूपित करते हुए कहा कि विमोचन अंक में ही इस अख़बार ने विदर्भ के किसानों के आंसू पोछने का काम किया है, जो इसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है. विजय दर्डा ने मीडिया से आह्वान किया कि ऐसे प्रयास किए जाएं, जिससे देश की जनता का लोकतंत्र से विश्वास न उठे. संतोष भारतीय ने विश्वास दिलाया कि इस मंच से जो अपेक्षाएं चौथी दुनिया से व्यक्त की गई हैं, उसे पूरा करने का पुरज़ोर प्रयास किया जाएगा.

डॉ. मनीष कुमार ने चौथी दुनिया का आशय स्पष्ट किया. उन्होंने अख़बार के इस नामकरण का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि पत्रकारिता व्यवसाय नहीं, एक मिशन है. दूसरी तरफ चौथी दुनिया उर्दू की वासिम रशीद ने तब और अब के बीच खड़े मुसलमानों की बेबसी पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने साफ़ कहा कि इस वर्ग की भावनाओं से हमेशा खेलने की ही कोशिश की गई. प्रस्ताविक भाषण में चौथी दुनिया, महाराष्ट्र संस्करण के प्रबंध संपादक प्रवीण महाजन ने पत्रकारिता क्षेत्र में अपने अनुभव लोगों के बीच बांटे. उन्होंने दो टूक कहा कि पत्रकारिता का सच वास्तव में एक जुनून है. इस क्षेत्र में खोने को बहुत कुछ है, मगर पाने के लिए मात्र संतुष्टि है. इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत आलोक मिश्रा (पुणे ब्यूरो), रवि मिश्रा (मुंबई ब्यूरो), संजीव चंन (वर्धा–यवतमाल ब्यूरो), अमिता नवघरे, शेखर वैद्य, रमेश मुलमुले ने किया. संचालन वरिष्ठ पत्रकार बाल कुलकर्णी और आभार प्रदर्शन चौथी दुनिया, महाराष्ट्र संस्करण के संपादकीय समन्वयक अंजीव पांडेय ने किया. इस अवसर पर डॉ. विलास डांगरे, महापौर अर्चना डेहनकर, उपमहापौर शेखर सावरबांधे, ज़िला परिषद के उपाध्यक्ष नितिन राठी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता, डॉ. बबनराव तायवाड़े, वीडीएनए के अध्यक्ष श्रीकृष्ण चांडक, पार्षद प्रगति पाटील, बटुकभाई ज्वेलर्स के राजेंद्र सेठ, दैनिक भास्कर के समूह संपादक प्रकाश दुबे, तरुण भारत के कार्यकारी संपादक गजानन निमदेव, लोकमत समाचार के कार्यकारी संपादक जयशंकर गुप्ता, सकाल के कार्यकारी संपादक श्रीपाद अपराजित, पुण्य नगरी के समाचार संपादक सचिन काटे, एनडीटीवी के ब्यूरो चीफ संजय तिवारी, पीटीआई के ब्यूरो चीफ जोसफ राव, उद्योगपति मितेश भांगड़िया, विजय जिचकार, रमेश बोरकुटे, जनमंच के प्रमोद पांडे, रजिस्ट्रार अरविंद पाटील, विश्वास इंदूरकर, डॉ. खेर, प्रा. गिरीश देशमुख, जल संसाधन के मुख्य अभियंता एम.ई. शेख, इंजीनियर्स रमेश वरधने, प्रकाश झलके, ललित इंगले, केशव तायड़े, श्रीकांत डोईफोडे, किशोर वरंभे, आर.एन. पैठनकर, शशिकांत डाहके, सर्वेश तिवारी, डॉ. किरण सावजी, एमकेएस ग्रुप के उपाध्यक्ष मोहन पांडे, लोकवाहिनी के संपादक शशि कुमार भगत, रमेश पिसे, संजय भेंडे, मनीष सोनी, महेश उपदेव, रामू भागवत, रमेश कुलकर्णी, डॉ. राजेंद्र सावजी, डॉ. डी.एम. सराफ, जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यकारी संचालक एस.डब्ल्यू. देशपांडे, अजय मोहता, सिदन्ना पाटील, किशोर सिंह रोटेले, राष्ट्र प्रकाश के कार्यकारी संपादक सुदर्शन चक्रधर, लोहिया अध्ययन केंद्र के हरीश अड्यालकर, चौथी दुनिया के आईटी सलाहकार भारत भूषण, विभागीय लेखापाल संगठन के सचिव अजय कुमार श्रीवास्तव, संजय पुरोहित, डॉ. विजय महाजन, उद्योगपतिगण राजेंद्र सावजी, विवेक महाजन, चारुदत्त सावजी, पटेल, डॉ. आरती व अशोक सावजी, निशिकांत काशीकर, वामा फार्मा के संचालक सतीश व्यवहारे, मनपा के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी वसंत पापड़े, संदीप देशमुख, चौधरी सर, सेवन हिल्स एडवर्टाइजिंग के तरुण निर्बाण, मंगलम एडवर्टाइजिंग के विवेक जुगादे, प्रा. पुनीता तिवारी, नारायण काशीकर, विक्रम पनकुले, रमेश पिसे, पूर्व उप ज़िलाधीश विनायक उपाध्ये, एसबीआई की नीलम पिल्ले, गंगाधर वकील, अजय तायवाड़े, किशोर डागा, राजकुमार टाक (मुंबई), बापू शेलारे (नासिक ब्यूरो), अजय श्रीवास्तव (सोलापुर ब्यूरो), गडलिंगे, धनंजय साबले (अकोला ब्यूरो), संदीप सुखधन (औरंगाबाद ब्यूरो), हनुमान रामावत (दिग्रस) सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक व मीडिया कर्मी उपस्थित थे.

राष्ट्र संत भैय्यूजी महाराज ने कहा कि समाज से डर समाप्त करने में मीडिया सक्षम है. क्योंकि मीडिया समाज की संवेदनाओं को शब्दों में व्यक्त करता है. यह समाज का आईना है. समाज को दिशा देने के साथ ही समाज की विशेषताओं को भी सामने लाता है. उन्होंने संविधान के दो सशक्त स्तंभ न्यापालिका और मीडिया को वेदनाओं के समाधान का माध्यम निरूपित किया. उन्होंने कहा कि मीडिया समाज की वेदना सामने लाता है और न्यायपालिका उसे न्याय प्रदान करती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 25 अप्रैल-01 मई 2011

www.chauthiduniya.com

"संजीवनी का है ऐलान,
झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

Website : sanjeevanibuildcon.in

PLOT

BUNGALOW

DUPLEX

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9973959681
9471356199
9431190351
9472727767
9471527830

अन्ना, नीतीश और बिहार

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

बड़ी मुश्किल है, सीएजी कहती है कि बिहार में वित्तीय अनुशासन की डोर ढीली है, अन्ना कहते हैं कि बिहार से सीखिए. गांवों में भ्रष्टाचार की जड़ें मज़बूत हुई हैं, अन्ना कहते हैं कि बिहार में ग्राम विकास में अच्छा काम हुआ. दरअसल, अन्ना व नीतीश तो दो धारा के लोग हैं. अन्ना शराबबंदी की बात करते हैं तो नीतीश ने गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवा दी. अन्ना दाग़ी मंत्रियों को हटाने की बात करते हैं तो नीतीश ऐसे मंत्रियों को संरक्षण दे रहे हैं. अन्ना को जनतंत्र पर भरोसा है तो नीतीश को अफसरतंत्र पर.

सरोज सिंह

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में इतिहास के नए पन्ने गढ़े जा रहे थे तो ठीक उसी दौरान बिहार में राजकोष को लगे 407 करोड़ के चूने का ख़ुलासा सीएजी द्वारा किया जा रहा था. सीएजी की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप किसी भी विभाग ने न तो उनके यहां हुई गड़बड़ी से महालेखाकार को अवगत कराया और न ही गबन के कारणों, परिस्थितियों और जवाबदेह व्यक्ति के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई का ब्योरा उपलब्ध कराया. सीएजी ने कहा है कि राज्य के 23 विभागों में 1021 ऐसे मामले पकड़े गए हैं, जिनमें सरकारी खजाने को 407 करोड़ का चूना लग गया है. रिपोर्ट में लंबित एसी डीसी बिल और आकस्मिता कोष की राशि के ग़ैरजरूरी कार्यों में उपयोग पर भी उंगली उठाई गई है.

अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार मिटाओ मुहिम के संदर्भ में उपरोक्त बातों का उल्लेख इसलिए भी ज़रूरी है कि इन्होंने नीतीश कुमार के कामों को सराहा है. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों को भी नीतीश कुमार के कामों का अनुशरण करना चाहिए. लेकिन लगता है कि अन्ना के सामने बिहार की ज़मीनी सच्चाइयों की सही तस्वीर नहीं है. पूर्व पार्षद पी के सिन्हा कहते हैं कि अन्ना व नीतीश तो दो धारा के लोग हैं. अन्ना शराबबंदी की बात करते हैं तो नीतीश ने गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवा दी. अन्ना दाग़ी मंत्रियों को हटाने की बात करते हैं तो नीतीश ऐसे मंत्रियों को संरक्षण दे रहे हैं. अन्ना को जनतंत्र पर भरोसा है तो नीतीश को अफसरतंत्र पर. उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट तो बानगी भर है. बिहार का आम आदमी भ्रष्टाचार की मार से रोज़ मर रहा है. जन्म प्रमाण पत्र से लेकर इंदिरा आवास का मामला हो या फिर लोन लेने से लेकर टेंडर देने की बात, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है. थाने में बिना पैसे दिए रिपोर्ट लिखवाना तक मुश्किल है. ऐसे में अगर अन्ना नीतीश के पक्ष में बोल रहे हैं तो इसका मतलब साफ़ है कि उन्हें सही जानकारी नहीं है. मैं तो चाहता हूं कि अन्ना बिहार आएं और यहां की आम जनता से पूछें कि भ्रष्टाचार का विष किस तरह इसे खोखला कर रहा है. विकास कार्यों में कमीशनखोरी का रेट उन्हें यहां आने पर पता चलेगा.

सीएजी की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि एसी डीसी बिल का चक्कर अभी ख़त्म नहीं हुआ है. सीएजी ने राजकोषीय घाटे की बढ़ोतरी और विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार पर सरकार को वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करने की सलाह दी है. ग़ौरतलब है कि जुलाई 2010 तक 11 हज़ार 854 करोड़ के डीसी बिल महालेखाकार को नहीं मिले थे. रिपोर्ट में मार्च के अंतिम दो दिनों में 6063 करोड़ सरेंडर करने पर भी सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट में अनुपूरक प्रावधानों को भी अविवेकपूर्ण करार दिया गया है. वर्ष 2009-10 में 53 हज़ार 533 करोड़ का बजट प्रावधान था, जबकि 42 हज़ार 988 करोड़ ही उपयोग हो सके. इस प्रकार 10545 करोड़ शेष रहते अनुपूरक प्रावधान में 5919 करोड़ लेने का कोई मतलब नहीं है. आकस्मिता निधि से 1175 करोड़ की निकासी की गई, लेकिन इसमें से 1015 करोड़ कार ख़रीदने और वेतन भत्ते पर ख़र्च कर दिए गए. एसी डीसी बिल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बहुत सारे मामले प्रकिया की वजह से भी हैं. लेकिन उनके अधिकारी दोष महालेखाकर पर ही मढ़ रहे हैं. वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने कहा कि डीसी विपत्र लंबित रहने का मुख्य कारण जमा करने के समय महालेखाकार कार्यालय द्वारा विपत्रों की प्रारंभिक जांच नहीं करना है. जबकि ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र कहते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित 716 मामलों का उल्लेख किया गया है. ब्योरा मांगा गया है, हम अविलंब कठोर कार्रवाई करेंगे. जबकि लोजपा के प्रधान महासचिव राधवेंद्र कुशवाहा का आरोप है कि जो डीसी बिल जमा किए जा रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर फ़र्ज़ी हैं. मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके. राजद नेता रामबिहारी सिंह का मानना है कि सरकार ने बड़े पैमाने पर पैसे का गोलमाल किया है. नीतीश के स्वागत सत्कार में भी अफसरों ने पैसे लुटा दिए अब उन्हें हिसाब देते नहीं बन रहा है. सरकार की नीयत अगर साफ़ है तो एसी डीसी मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश करे. वैसे इससे संबंधित एक याचिका हाईकोर्ट में दायर भी की गई है.

बड़ी मुश्किल है, सीएजी कहती है कि बिहार में वित्तीय अनुशासन की डोर ढीली है, अन्ना कहते हैं कि बिहार से सीखिए. गांवों में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुई हैं, अन्ना कहते हैं कि बिहार में ग्राम विकास में अच्छा काम हुआ. दरअसल अगर इन सारी चीजों को राजनीतिक चश्मे से अलग होकर देखें तो एक राय यह बनती नज़र आती है कि राज्य के लोगों ने इस तरह के भ्रष्टाचार के साथ जीना सीख लिया है. यह क्यों हुआ कि बिहार के लोगों ने ज़हर पीने की आदत डाल ली. देश को रास्ता दिखाने वाला बिहार आज अपनी ईमानदारी साबित नहीं कर पा रहा है. एक उदाहरण पेश है. पटना के एक व्यस्त बाज़ार में चाय की दुकान करने वाले शख्स की प्रतिक्रिया सुनिए. क्या करें हजूर, दुकान लगाने का पैसा देते हैं, शाम को जब दुकान बंद करते हैं तो कमाई में कमीशन देते हैं. ज़िंदगी चलानी है, करना पड़ता है. अब इसके बाद इस चाय दुकानदार से कोई सवाल पूछना बेमानी होती. ज़िंदगी ने भ्रष्टाचार के साथ जीना सिखा दिया. नीतीश कुमार अपनी दूसरी पारी में भ्रष्टाचार मिटाने का ऐलान कर रहे हैं. कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के घरों में स्कूल खोलेंगे. ऐसी ही कुछ बातें अन्ना हजारे को अच्छी लगी होंगी और उन्होंने उनकी तारीफ कर डाली. लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार के कैंसर से नीतीश कुमार भी वाक़िफ़ हैं. सीएजी की रिपोर्ट भी आंखें खोलती है. इशारा करती है कि राज्य में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. एसी डीसी बिल का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है. रोज़मर्रा के कामों में भ्रष्टाचार आम आदमी को खोखला कर रहा है. बिहार की योजना आकार बढ़ा है, पैसे ज़्यादा ख़र्च हो रहे हैं. विकास कार्यों को अंजाम देने वालों का एक सिंडिकेट है जो विभागवार काम करता है. भ्रष्टाचार ऐसे सिंडिकेट को ताक़त देता है और आम आदमी का पैसा कुछ ख़ास पॉकेटों में चला जाता है. यह नई बात नहीं है पर दुख की बात ज़रूर है, क्योंकि 2010 का जनादेश मांग करता है कि यह कहानी ख़त्म हो ताकि आम आदमी इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी जी सके. कोई चाय वाला यह न कहे कि ज़िंदगी चलानी है तो करना पड़ता है. नीतीश कुमार ख़ुद कई बार कह चुके हैं कि भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ लड़ाई कठिन है, पर हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं. बिहार का आम आवाम भी यही चाहता है कि भ्रष्टाचार के रोग से यह सूबा मुक्त हो, ताकि सबको जीने व आगे बढ़ने के समान अवसर मिले. लड़ाई बड़ी और लंबी है, पर बिहार के लोगों ने कई मौकों पर अपने आप को साबित किया है. अपनी दूसरी पारी में नीतीश कुमार अगर इस रोग का इलाज करने के लिए ईमानदारी से पहल करेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें जनता और ताक़त देगी. नहीं तो बिहार की जनता फिर अन्ना से पूछेगी, आपने यह क्या कह दिया.

बिहार का आम आदमी भ्रष्टाचार की मार से रोज़ मर रहा है. जन्म प्रमाण पत्र से लेकर इंदिरा आवास का मामला हो या फिर लोन लेने से लेकर टेंडर देने की बात, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है. थाने में बिना पैसे दिए रिपोर्ट लिखवाना तक मुश्किल है. ऐसे में अगर अन्ना नीतीश के पक्ष में बोल रहे हैं तो इसका मतलब साफ़ है कि उन्हें सही जानकारी नहीं है. मैं तो चाहता हूं कि अन्ना बिहार आएं और यहां की आम जनता से पूछें कि भ्रष्टाचार का विष किस तरह इसे खोखला कर रहा है. विकास कार्यों में कमीशनखोरी का रेट उन्हें यहां आने पर पता चलेगा.

feedback@chauthiduniya.com

गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने तथा सीवरेज सिस्टम को दुरूस्त करने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बक्सर ज़िले के लिए 74.94 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृत करना एक सार्थक क़दम माना जा रहा है.

इस किताब में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ करते हुये जे.पी. सिंह ने कई आपत्तिजनक बातें लिखी हैं.

एक नज़र

बगहा में सांस्कृतिक महोत्सव

भारतीय संस्कृति नववर्ष के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक जागरण महोत्सव बगहा के बॉम्बे बाज़ार में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया. इस महोत्सव में पंद्रह सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया. एसेम्बली आफ़ गॉड रामपुर राजकीय मध्य विद्यालय, दी चम्पारण चैप्टर, कस्तूरबा विद्यालय, बनवासी कल्याण आश्रम आदि विद्यालयों के बच्चों ने प्रमुख रूप से अपनी कला का प्रदर्शन किया. वार्षिक पत्रिका सृजन का लोकार्पण किया गया. समारोह का उदघाटन अधिशासी अभियंता विजय कुमार अलबेला, डॉ. नरेन्द्र चौधरी आदि ने किया.

निगम पार्षदों को शराब और कपड़े

गया नगर निगम अपनी अजीबो-ग़रीब हरकतों के लिये हमेशा चर्चा में रहा है. हाल के दिनों में भी निगम पार्षदों को तोहफ़े के रूप में सफारी सूट के कपड़े, साड़ी, मिठाई के साथ अच्छी क्वालिटी की शराब और नगद राशि एक पैकेट में भेट की गई. इस बात की चर्चा शहर में बड़े ज़ोरों से है तथा कई पार्षदों ने इस बात को स्वीकार किया. बताया जाता है कि गया नगर निगम में अपने मतलब को साधने के लिये निगम पार्षदों के मुखिया और उप-मुखिया की ओर से उक्त तोहफ़े भेंट किये गये. कुर्सी बचाने और सशक्त स्थायी समिति की बैठक में अपने मन मुताबिक़ बातें मनवाने के लिये निगम पार्षदों को तोहफ़े देकर उपकृत किया गया .

अभाविप की नगर कार्यसमिति गठित

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की समस्तीपुर नगर इकाई का सम्मेलन काशीपुर स्थित मॉर्डन स्टडी सेन्टर में आयोजित हुई, जिसमें वर्ष 2011-12 के लिए नगर कार्यसमिति का गठन किया गया. संगठन के उपाध्यक्ष रवीन्द्र मोहन राजन ने बताया कि प्रो. विनोद कुमार चौधरी को अध्यक्ष, अजीत कुमार को नगर मंत्री, राजीव कुमार, रवीन्द्रनाथ, शक्ति सिंह, मीसा रानी, नीरज कुमार सत्यार्थी को नगर सह मंत्री, निशुलता को नगर छात्रा प्रमुख, कुंजबिहारी वर्मा को कार्यालय मंत्री, कुमार अतुल को कोष प्रमुख बनाया गया है. अरविंद कुमार, ऋचा सिन्हा, चांदनी कुमारी, मधुलता, चंदन कुमार भारद्वाज, रंजीत राय को कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया है.

शिक्षा के लिए श्रमदान से सड़क

जहानाबाद के लोगों ने अपने स्कूली बच्चों को वर्षों की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक पहल की है. टोले में एक प्राथमिक स्कूल पर पहुंचने के लिए कोई सुलभ रास्ता नहीं था. बच्चों को टूटी-फूटी गलियों से होकर स्कूल जाना पड़ता था. टोले के महादलितों ने इस समस्या से निजात पाने के लिए कई दफ़ा स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से गुहार भी लगाई थी, परन्तु कोई फ़ायदा नहीं हुआ. आख़िरकार बिना निराश हुए महादलितों ने अपने बच्चों की राह खुद बनाने का निर्णय लिया. महादलित परिवारों के स्त्री-पुरुषों ने मिलकर अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए लगभग पांच सौ फीट सड़क बनाने का निर्माण श्रमदान से कर दिया.

राष्ट्रीय मानचित्र पर आएगी पंचायत

उत्तर बिहार के गौरवपूर्ण शिक्षण संस्थान के प्रोग्रेसिव सेन्ट्रल हाई स्कूल, पटसा (समस्तीपुर) के निदेशक एवं शिक्षाविद् रामकिशोर राय अपनी पंचायत को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने हेतु कृतसंकल्पित हैं. ग्राम पंचायत राज औरा पटसा को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के वायदे के साथ मुखिया पद की चुनावी जंग में कूदे राय के समर्थकों का कहना है कि पंचायत में समुचित बिजली एवं सिंचाई व्यवस्था के अलावा हर ज़रूरतमंद परिवार को शौचालय की व्यवस्था कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. जल जमाव से मुक्ति हेतु पक्के नाले का निर्माण, जल स्तर में लगातार गिरावट को देखते हुए पेयजल हेतु पानी टंकी का निर्माण एवं सुव्यवस्थित जलापूर्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पटसा के अपग्रेडेशन सहित गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ- साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तरीय बेहतर शिक्षा का माहौल बनाकर पंचायत की शत प्रतिशत जनता को साक्षर बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे. कैमरा चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी बाजी अपने नाम करने हेतु राय समर्थकों की भीड़ के साथ पंचायत के लोगों का विश्वास हासिल करने में जुटे हैं. **- चौथी दुनिया ब्यूरो**

न्याय के लिए भटकता चिकित्सक

सुशासन में भी न्याय के तमाम दरवाजे खटखटा चुके हैं गया के चिकित्सक डॉ. धर्मेन्द्र प्रसाद, परन्तु उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है. उन्होंने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अपोलो रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिये गया शहर में क़रीब पाच कठ्ठा ज़मीन 2006 में ख़रीदी थी. ज़मीन के कागज सही हैं, दाखिल खारिज होकर राजस्व रसीद भी कट रही है, बावजूद इसके कुछ असमाजिक तत्व भूमि पर निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं. अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर धर्मेन्द्र प्रसाद को तंग किया जा रहा है. नाम सुशासन का भले हो रहा हो, गुंडागर्दी तो अभी जारी है. **- सुनील सौरभ**

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, which is Govt. of India registered, Regd. No. 03-09284 of 2000-2001.
- ISO 9001:2000 certified, Regd. No. CCPL/QMS/C1487
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where Practicals are conducted.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where one full paper of 100 marks on petroleum is taught.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where students of Industrial Safety Management Course of Patna University & Magadh University get Practical Training.

FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday

Excellent Placement with Handsome Salary

Website : www.psfsm.com

410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph : 0612-6455019, Mob. : 9334107607, 9835042835, 9234729075

शिक्षा के नाम पर व्यापार हो रहा है

बिहार आज शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है. स्कूल-कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थानों में लड़कियों का प्रतिशत बढ़ा है. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के परिणाम अब सामने आने लगे हैं, लेकिन सरकारी उदासीनता से समस्तीपुर ज़िले में शिक्षा माफ़िया दिन दूनी रात चौगुनी की गति से फल-फूल रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो दूर रही ज़िला मुख्यालय स्थित बड़े-बड़े नामचीन शिक्षण संस्थान छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों के आर्थिक दोहन-शोषण में जुटे हैं. विभागीय अधिकारी इनपर नकेल कसने में अक्षम साबित हो रहे हैं. मार्च-अप्रैल का महीना छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ होता है. इन दिनों छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों में सीबीएसई पैटर्न शिक्षा हासिल करने की धुन सवार है. लेकिन जिस प्रकार इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में विषयों की त्रुटि हुई है और सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है. इसे देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किसी भी परीक्षा के लिए हर विद्यालय के छात्र-छात्रा एवं अभिभावक सकते में आ गये हैं. शिक्षा माफ़ियाओं का केंद्र रहे समस्तीपुर में राज्य के विभिन्न ज़िलों के छात्रों का नामांकन और रजिस्ट्रेशन होता है [illegible]. ज़िले के नामी गिरामी चर्चित स्कूलों (सीनियर सेकेंड्री) द्वारा 10वीं और 12वीं में जितने छात्रों का नामांकन लिया जाता है, उससे कई गुना अधिक को परीक्षा में शामिल कराया जाता है. ऐसे छात्र-छात्रा पढ़ते कहीं और हैं, परीक्षा किसी दूसरे संस्थान के माध्यम से देते हैं. ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को नहीं है. पिछले वर्ष 12वीं परीक्षा का निरीक्षण करने आए बोर्ड के अधिकारियों ने एक प्रतिष्ठित स्कूल में इसके विद्यालय का नाम तथा पता पूछा. परीक्षार्थी द्वारा विद्यालय का नाम तो बताया गया लेकिन उक्त विद्यालय समस्तीपुर शहर में कहां है, इसकी जानकारी नहीं दी गई. सच्चाई से पेश आने पर छात्र ने बताया कि रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा फ़ॉर्म जमा करने के समय अभिभावक ने किस प्रकार और कहां से भरवाया, इसकी जानकारी उसे नहीं है. ज़िला मुख्यालय के अलावा [illegible] दलसिंगसराय, ताजपुर, पटोरी आदि स्थानों पर भी शिक्षा का व्यवसाय काफ़ी फल-फूल रहा है. निजी स्कूल संचालकों की कार्यप्रणाली को देखकर शिक्षा के बाज़ारीकरण के आरोपों को झुठलाया नहीं जा सकता. ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए निजी शिक्षण संस्थानों की बाढ़ सी आ गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवासीय विद्यालयों की [illegible]. संचालक जितनी गुणवत्तापूर्ण सुविधा देने का वायदा करते हैं, उसका आधा भी नहीं दे पाते हैं. आवासीय सुविधा के नाम पर अभिभावकों से जहां 1500-2500 तक की राशि ली जाती है, वहीं उनके रहने सोने के लिए एसबेस्टसयुक्त लॉज की व्यवस्था की गई है. जहां हॉस्टल के भवन चुस्त-दुरुस्त हैं, वहां बच्चों को भोजन गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रहा है. ऐसे हॉस्टलों के अधिकांश बच्चे एवं अभिभावक ग्रामीण परिवेश के होते हैं, इसलिए उन्हें लच्छेदार बातों से गुमराह किया जाता है. ज़िले के [illegible] गांव की सुनीता देवी बताती हैं कि उनके पति गोहाटी में काम करते हैं. अच्छी शिक्षा हेतु उन्होंने बच्चों को रोसड़ा के एक आवासीय स्कूल में दाखिला दिलाया हुआ है. नये शैक्षणिक सत्र में दूसरी एवं तीसरी कक्षा के एक बच्चे का किताबी खर्च 1800 रुपये तक में हुआ है. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किताब के अलावा स्कूल ड्रेस, बैग, टाई एवं अन्य आवश्यक सामग्री स्कूल से ही ख़रीदने को बाध्य किया गया है.

ज़िला मुख्यालय स्थित मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंक, रेलवे, एसएससी आदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करा रहे बड़े-बड़े संस्थान भी बाहरी चकाचौंध, आधुनिक एवं सह शिक्षा की आड़ में छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों को गुमराह कर रहे हैं. कई नामचीन कोचिंग संस्थान सह सीनियर सेकेंड्री स्कूल [illegible]. शहर के प्रमुख स्थलों पर लगे होर्डिंग्स में बड़े-बड़े एवं भव्य काल्पनिक भवनों को संस्थान का भवन बताते हुए एयर कंडीशन सुविधा समेत विभिन्न प्रकार के दावे किये जाते हैं. कोचिंग संस्थान द्वारा एसी का प्रचार इस प्रकार किया जाता है, मानो वह विद्या का मंदिर न होकर आवासीय होटल हो. [illegible]

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

शहर के प्रमुख स्थलों पर लगे होर्डिंग्स में बड़े-बड़े एवं भव्य काल्पनिक भवनों को संस्थान का भवन बताते हुए एयर कंडीशन सुविधा समेत विभिन्न प्रकार के दावे किये जाते हैं. कोचिंग संस्थान द्वारा एसी का प्रचार इस प्रकार किया जाता है, मानो वह विद्या का मंदिर न होकर आवासीय होटल हो.

समस्तीपुर

गया

भू-माफ़ियाओं के शिकंजे में शहर

सुनील सौरभ

गया देश के प्राचीनतम शहरों मे से एक है. इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता से देश हीं नही दुनिया के लोग भी अच्छी तरह से वाक़िफ़ हैं. हिंदू धर्मावलंबी यहां अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिये पिंडादान करने आते हैं, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया के बौद्ध धर्मावलंबी भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध-गया को नमन करने यहां आते रहते हैं. इस्लाम धर्मावलंबी भी गया के पीर बाबा तथा बिथो शरीफ स्थित मखदुम बाबा की मजार पर मत्था टेकने गया आते हैं. दिल्ली के बाद गया ही ऐसी जगह है, जहां विशाल जामा मस्जिद है. सिख गुरुनानक देव, गुरु तेग बहादुर आदि से जुड़े स्थल पर श्रद्धा अर्पित करने यहां पहुंचते हैं. जैन धर्मावलंवियों से जुड़े भी अनेक स्थल गया के आस-पास हैं. इस प्रकार कहा जाए तो गया सभी धर्मों का समन्वय स्थल है. इन सब ख़ूबियों के बावजूद भी यहां का विकास समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा है. अतिक्रमण ने शहर की ख़ूबसूरती को बदसूरती में तब्दील कर दिया है. यह प्रशासनिक इच्छा शक्ति का अभाव एवं निष्क्रियता का परिणाम ही है कि शहर के प्राचीन तथा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों पर भी अतिक्रमणकारियों ने क़ब्ज़ा कर लिया है. वस्तुत: गया भू-माफियाओं के लिये एक अच्छा अभ्यारण्य बन चुका है. सर्वे किया जाए तो मंत्री से लेकर विधायक, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न क्षेत्रों के दबंग लोग अतिक्रमणकारियों की सूची में शामिल नज़र आएंगे. शहर की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिये पिछले दो दशक में अनेक बार अभियान चलाये गये लेकिन परिणाम सिफ़र रहा. प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी ने शहर में अतिक्रमणकारियों का मनोबल बढ़ाया है. यही कारण है कि सरकारी भूमि की तो बात छोडिये, नदी-पहाड़ तक का लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. गया शहर के आस-पास स्थित ब्रह्मयोनी, रामशिला, प्रेत-शिला, ढुंगेश्वरी समेत अनेक पहाड़ियों को वैध-अवैध रूप से तोड़े जाने के मामले को लेकर यहां के एक सामाजिक कार्यकर्ता स्व. राणा मुनेश्वर सिंह ने उच्चतम न्यायालय तक लड़ाई लड़ी थी और इन पहाड़ियों को बचाया था. लेकिन आज इन पहाड़ियों का भी तेज़ी से अतिक्रमण किया जा रहा है. मगध की जीवन रेखा कही जाने वाली फल्गु नदी के तट पर बसा है गया शहर. इस नदी के दोनों किनारे खाली पड़ी भूमि पर क़ब्ज़ा करने का अभियान तेज़ी से चल रहा है. यहां तक कि फ़र्ज़ी हुक्मनामा और नकली काग़ज़ात बनाकर भू-माफियाओं के द्वारा शहर के पंचायती अखाड़ा क्षेत्र, मानपुर का भुसंडा मेला क्षेत्र, फल्गु के पूर्वी तट, रामशिला क्षेत्र, ब्रह्मयोनी की तराई में कपिल-धारा क्षेत्र, ब्रहयोनी जानेवाले मार्ग में अवैध रूप से अतिक्रमण कर पूरी की पूरी कॉलोनी बसा दी गई है. ऐतिहासिक भुसंडा पशु-मेला की भूमि को भू-माफियाओं के ज़िम्मे सौपने में गया में पदस्थापित एक उच्च अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण थी. हालांकि ज़िलाधिकारी संजय सिंह के प्रयास तथा प्रमंडलीय आयुक्त राणा अवधेश के आदेश के बाद किसी तरह भुसंडा मेला की ज़मीन बच गई. गया के गोदावरी महल्ला स्थित है प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर, जहां राज्य के अनुसूचित जाति जन जाति कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी का निवास है. मांझी लंबे समय से कांग्रेस, राजद, जदयू के विधायक-मंत्री रहते आ रहे हैं. इन पर भी यह आरोप लगता रहा है कि अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुये चित्रगुप्त मंदिर की भूमि तथा आस-पास स्थित सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कर मकान बना लिया है. सरकारी जांच रिपोर्ट तथा काग़ज़ातों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार एवं मंदिर की भूमि का अतिक्रमण कर मकान बनाया गया है. इसी चित्रगुप्त मंदिर से सटा है हाथिया डुबाव तालाब, जिसे 3-4 साल के अंदर अतिक्रमणकारियों ने क़ब्ज़े में ले लिया है. इसी मंदिर के ठीक सामने पूर्व दिशा में स्थित संक्रामक रोग अस्पताल को भी अतिक्रमणकारियों ने नहीं बख्शा. इसी प्रकार नूतन नगर में शहर के पुराने हरानचन्द्र उच्च विद्यालय एवं कन्या मध्य विद्यालय के नाम आवंटित सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कर लिया गया है. शेष बची भूमि को भी बेचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तत्कालीन ज़िला पदाधिकारी संजय सिंह के प्रयास और सदर अनुमंडलाधिकारी परितोष कुमार की तत्परता ने सरकारी भूमि को अवैध रुप से बेचने से बचाया. के पी रमैया जब मगध प्रमंडल के आयुक्त बनकर आए तो उन्होंने अतिक्रमण के ख़िलाफ़ ज़ोरदार अभियान चलाया, लेकिन यह बहुत दिन तक नहीं चला. जब एस एम राजू गया के ज़िला पदाधिकारी थे तो उन्होने शहर में अतिक्रमण के ख़िलाफ़ मुकम्मल कारवाई की थी, जिसका नमूना आज भी चौक पर उनके अतिक्रमण अभियान में तोड़ी गई इमारतों में देखा जा सकता है. गया शहर को आज भी इंतजार है एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी का, जो भू-माफियाओं के चंगुल से ऐतिहासिक स्थलों एवं सरकारी भूमि को मुक्त करा सके.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

गोगरी पंचायत में कालाज़ार ने पांव पसारे

खगड़िया अनुमंडल के गोगरी पंचायत में कालाज़ार का कहर जारी है. गोगरी पंचायत के लतामबाड़ी में कालाज़ार ने पांव पसार लिया है. सरकारी अस्पताल में अब तक मात्र दो मरीजों की ही पहचान हो सकी है. जिसमें लतामबाड़ी निवासी सुदाम सिंह की पत्नी आशा देवी एवं इंद्रदेव यादव शामिल हैं. वहीं सूत्रों के अनुसार गांव के शोभा देवी, अरुण सिंह, रमेश, आजाद सिंह आदि लोग बुखार से पीड़ित हैं. इस विषय पर जब चिकित्सा पदाधिकारी अरुण सिन्हा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि फ़िलहाल दो लोगों में कालाजार पाया गया है.

अक्टूबर तक होगा कॉलेजों का ग्रेडेशन

मोतिहारी में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.राजेन्द्र मिश्र ने कहा कि नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल से सभी कॉलेजों को अक्टूबर तक ग्रेडेशन दिलाने की कोशिश की जाएगी. इसके लिए सितम्बर में नैक की टीम यहां आएगी. एमएस कालेज में नैक के कार्यों के बारे में बताने के लिए विश्वविद्यालय टीम एक सादे समारोह को संबोधित कर रही थे. उन्होंने इस कॉलेज शिक्षकों व कर्मचारियों को उत्प्रेरित करते हुए कहा कि उनकी कोशिश होगी कि यह ए ग्रेड का हो. इसके लिए उन्होंने शिक्षकों व कर्मियों को कॉलेज घर की तरह सजाने-संवारने की नसीहत देते हुए कहा कि आप संसाधनों का सही इस्तेमाल करें, अन्य आवश्यक कमी को भी पूरा किया जाएगा. कॉलेज में पावर की कमी को लेकर उन्होंने एक हाई पावर जेनरेटर ख़रीदने की स्वीकृति देने की घोषणा की. इस मौके पर वरीय शिक्षक डॉ. नरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ. शंभूशरण सिंह, अविनाश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे.

वाणी के संयम से चित्त निर्मल : निरंजनानंद

वासंती नवरात्र के पावन अवसर पर मुंगेर में मां भगवती की आराधना एवं व्रत कर नर नारी जीवन के संतापों से मुक्ति की याचना कर रहे हैं. वहीं चंडिका मंदिर के बाद माधोपुर स्थित दसभुजी मां के मंदिर में स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने धर्म व अध्यात्म को, भौतिक जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग बताया. इस अवसर पर स्वामी जी ने बताया कि साधना जीवन में शक्ति भरती है और दुखों से मुक्त करती है. समारोह में दसभुजी स्थान समिति के महामंत्री दीपक कुमार, शिव कुमार रूंगटा सहित सैकड़ों लोग भगवान की अस्था में डूबे रहे.

लेटलतीफी के विरोध में धरना

महनार का सी.डी.पी.ओ. कार्यालय जब बारह बजे दिन में भी नहीं खुला तो इससे आक्रोषित सामाजिक कार्यकर्ता रामकिशोर सिंह मुख्य द्वार पर ही गमछा बिछा कर धरने पर बैठ गए और वहीं पर लेट गए. लोगों की भीड़ भी वहां जमा हो गयी किन्तु महज पचास कदम की दूरी पर बैठे एसडीओ को इसकी भनक तक नहीं लगी. बीस सूत्रीय अध्यक्ष ने भी कार्यालय का निरीक्षण किया व इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से की. इस बाबत जब डी.एम. से पूछा गया तो उन्होंने ज़िला प्रोग्राम पदाधिकारी से बात कराई, जिन्होंने बताया कि सी.डी.पी.ओ सस्पेन्ड हो चुकी है तथा कार्यालय खुलने में अनियमितता पर चपरासी के विरुद्ध कार्रवाई होगी. **-चौथी दुनिया ब्यूरो**

कुंवर सिंह की जयंती पर कई कार्यक्रम

सहरसा प्रखंड के स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह व उनके सेनापति रहे शहीद पीर अली की जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारी की गई. इस अवसर पर आनंद कार्यालय के जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं व गणमान्य नागरिकों की बैठक हुई. बैठक में सर्वसम्मति से चार सत्र में जयंती समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया. सेवा निवृत्त भूपेन्द्र नारायण सिंह को अध्यक्षता व प्रो. विद्यानंद मिश्र के संचालन बैठक में उपस्थित थे. पूर्व सांसद लवली के नेतृत्व में बाबू वीर कुंवर सिंह व पीर अली की जयंती पर एमएलटी कॉलेज से हाथी, घोड़ा आदि के साथ जुलूस निकालकर नगर भ्रमण कर हॉल पहुंचने का निर्णय लिया गया. बैठक में विधान पार्षद इसराइल राईन, गोपाल क्षा, चमन सिंह, यशवंत सिंह, सतीश सिंह, रोहिनी दास आदि मौजूद थे. **- अजय कुमार**

रंगनाथ दे रहे हैं कड़ी टक्कर

महनार प्रखंड के हसनपुर दक्षिणी पंचायत से मुखिया के पद पर रंगनाथ सिंह के नामंकन कर अन्य उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देने में लगे हैं. इस बारे में रंगनाथ सिंह ने बताया कि वह इसके पूर्व भी इसी पंचायत से मुखिया थे तथा अपने कार्यकाल में बिना भेदभाव के कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कराया है. दूसरी तरफ जिप क्षेत्र सं.- 36 से मो. जलील ने भी धुआंधार जनसम्पर्क अभियान चला कर क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है. इसी क्षेत्र से मनोज सिंह ने भी विभिन्न गांवों का दौरा कर बदलाव की बयार ला दी है. **-अन्जुम परवेज**

कैसे साफ़ होगी गंगा

पवित्र गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए बक्सर में स्वीकृत की गई 74.94 करोड़ रुपये की महात्वाकांक्षी योजना की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है. क्योंकि इस योजना के तहत उसी सीवरेज सिस्टम को दुरूस्त किया जाएगा जिस पर 25 साल पहले ख़र्च किए गए करोड़ों रुपये बेकार हो गए और गंगा मैली की मैली रह गयी. लिहाज़ा गंगा सफ़ाई के लिए कारगर तथा व्यावहारिक सामाधान खोजे जाने के बदले असफल साबित हुई योजना पर करोड़ों ख़र्च करने की योजना संदिग्ध ही लग रही है.

गंगा को प्रदूषण मुक्त करने तथा सीवरेज सिस्टम को दुरूस्त करने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बक्सर ज़िले के लिए 74.94 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृत करना एक सार्थक क़दम माना जा रहा है, क्योंकि गंगा में गिरने वाले कचड़े तथा प्रदूषित जल से जलीय जीव मर रहे हैं तथा मानवीय स्वास्थय पर भी असर पड़ रहा है. केन्द्र सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान के तहत बक्सर में गंगा सफ़ाई योजना का काम 1985 में शुरू हुआ था. दो चरणों में इस योजना के तहत लगभग 20 सौ करोड़ रूपये ख़र्च हुए थे. बक्सर में दो सीवरेज शोधन प्लांट बनाए गये. शहर के ताड़का नाले तथा सारिमपुर के पास दो-दो एमएलडी शोधन क्षमता वाले पम्प लगाये गये. दोनों पम्प को मिलाकर एक मेन नाला बनाया गया और इससे शहर के नालों को जोड़ दिया गया. ताड़का नाले से पम्प के द्वारा गंदा पानी सारिमपुर भेजा जाता था. वहां गंदा पानी एक बड़े कुंभा में संग्रहित किया जाता था और वहीं पर पानी का शोधन किया जाता था. 1990 में निर्माण कार्य पूरा हो गया और क़ायदे से चार-पांच वर्षों तक शोधन का काम होता रहा. लेकिन बिजली के अभाव में सीवरेज शोधन करने वाले पम्प समय पर चालू नहीं होते हैं. इससे नालियां ध्वस्त हो गईं और गंदे पानी का बहाव भी रूक गया. गंदी नालियों का मुंह गंगा की ओर कर दिया गया है. इस सिस्टम को चलाने के लिए बिहार राज्य जल पार्षद बोर्ड द्वारा तीन कर्मचारियों को तैनात किया गया था. वो आज भी बेकार पड़े हैं. एक बार बिगड़ जाने के बाद फिर किसी ने खोज ख़बर नहीं ली और पवित्र पावन गंगा लगातार ज़हरीली होती चली गयी. फिर जब गंगा सफ़ाई का ख्याल आया तो इसी सिस्टम पर करोड़ों रुपये जाया करने की कवायद शुरू हो गई.

जानकार बताते हैं कि इस योजना की सबसे बड़ी खामियां यह हैं कि इसमें शहर की सभी नालियां नहीं जुड़ पाई थीं. 25 वर्षों के दौरान शहर की आबादी चार गुना बढ़ गयी और शहर का उत्तरी भाग गंगा के किनारे ही बसा है. इस भाग के हज़ारों घरों का गंदा पानी गंगा में ही गिरता है. भौगोलिक बनावट ऐसी है, जिससे सभी नलों को सीवरेज के मेन नालों में जोड़ने की संभावना नहीं दिखती है. दूसरी सबसे बड़ी समस्या शवों के अंतिम संस्कार की है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, बक्सर की गंगा में शवों का संस्कार करने कई ज़िलों से लोग यहां आते हैं. फिर संस्कार के नाम पर जले और अर्द्धजले शवों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है. विद्युत शवदाह गृह तो है नहीं. फिर भी गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बनी योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए अभियंताओं के दल ने बक्सर आकर पूरी स्थिति का मुआयना किया. अब देखना यह है कि नेक प्रयास के तहत शुरू हुई गंगा मुक्ति योजना कहां तक सफल होती है.

बक्सर

जय मंगल पाण्डेय feedback@chauthiduniya.com

सड़कों पर कुचलती ज़िंदगी

नवल किशोर सिंह

सूबे की सड़कें ख़ून की प्यासी होती जा रही हैं. सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. झारखण्ड से गुज़रने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर बड़े व्यवसायिक वाहनों के टक्कर से होने वाले हादसों में बेतहाशा वृद्धि की ओर किसी का ध्यान नहीं है. एक अनुमान के मुताबिक़ झारखण्ड में प्रतिदिन 15 मौतें सड़क हादसों में हो रही हैं. सड़कें और राष्ट्रीय राजमार्ग लोगों की मौत का तीसरा बड़ा कारण है. एक सर्वेक्षण के मुताबिक़ पिछले दस वर्षों में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या में 40 फ़ीसदी वृद्धि हुई है. पूरे देश के आंकड़ों पर ग़ौर करें तो वर्ष 2008 में एक लाख अठारह हज़ार लोग सड़क हादसे में मारे गए हैं. वहीं वर्ष 2009 में एक लाख 36 हज़ार लोग सड़क दुर्घटना के कारण मौत की आगोश में समा गये. एक अनुमान के मुताबिक़ झारखण्ड में प्रतिदिन दस से बारह लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हो रही है. लगभग 4 से 5 हज़ार लोग प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं. आंकड़े बताते हैं कि भारत पूरे विश्व में सड़क दुर्घटना में अव्वल है. झारखण्ड में पटना-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग, रांची-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग, रांची-टाटा राष्ट्रीय मार्ग, हजारीबाग-गया राजमार्गों पर मुख्य रूप से सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा अधिक है. झारखण्ड में सड़क सुरक्षा अन्य राज्यों की तुलना में सबसे खराब है इससे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 2 से 3 फ़ीसदी का नुक़सान हो रहा है. वहीं दूसरी तरफ दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे मृतक अपने परिवार के लिए ताउम्र त्रासदी छोड़ जाते हैं.

राज्य में सुरक्षा प्रावधान अपर्याप्त है और इस संबंध में सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारण नहीं किया गया है. परिवहन जागरूकता अभियान पर पहल नहीं की जा रही है. सड़क सुरक्षा नियमों एवं परिवहन अधिनियमों का अनुपालन नहीं होने से यह समस्या बढ़ती जा रही है. राज्य में सड़क सुरक्षा विषयों पर गोष्ठियों का आयोजन महज पांच सितारा होटलों के वातानुकूलित कमरों तक ही सिमट कर रह जाता है. ग़ौरतलब है कि भू-परिवहन किसी भी राज्य के आर्थिक ढांचे को मज़बूती प्रदान कर सही आकार देता है. महानगरों के विकास के लिए अच्छी सड़कें ज़रूरी है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं. सड़क सुरक्षा की ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है. महानगरों के विकास के लिए कितनी भी सड़कें बना लें, कितने ही फ्लाई ओवर बना लें, लेकिन जब तक सड़क सुरक्षा के मामलों में जनता जागरूक नहीं होगी और यातायात नियमों का शक्ति से अनुपालन नहीं किया जायेगा, तब तक ये सड़कें ख़ून की प्यासी बनी रहेंगी. इसका लाभ कम नुक़सान ज़्यादा उठाना पड़ रहा है.

हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण के आधार पर यह पता चला है कि 99 फ़ीसदी सड़क दुर्घटनाओं का कारण शराब या अन्य नशे का सेवन करके वाहन चलाना है. सर्वेक्षण से यह भी खुलासा हुआ है कि 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की आकस्मिक मौत का सबसे बड़ा कारण सड़क दुर्घटना है. महानगरों में शिक्षित, संभ्रांत एवं आधुनिक जीवन शैली अपनाने वाले लोग रहते हैं पर यह विडंबना ही कही जाएगी कि इसी महानगरों के नागरिक गलत ड्राइविंग के लिए बदनाम हैं. झारखण्ड के ग्रामीण इलाक़ों में सड़क दुर्घटनायें नगण्य हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है. झारखण्ड में वाहनों की संख्या का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है. राज्य गठन के दस वर्षों के बाद लगभग पांच लाख छोटे-बड़े वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं. सड़कें बढ़ी नहीं वाहनों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है. नशा सेवन कर गाड़ी चलाना, तेज़ रफ्तार से वाहन चलाना, सही प्रशिक्षण न होना, ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना आदि ऐसे मुख्य वजह हैं, जिसके कारण सड़क हादसे में मरनों वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. सड़क दुर्घटना का एक कारण ड्राइवरों का अशिक्षित होना भी है. क्योंकि सड़कों पर लगे दिशा-निर्देशों को वह पढ़ नहीं सकते. झारखण्ड में सड़क निर्माण में सही तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जाता. यातायात नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता. लाइसेंसिंग प्रणाली दुरुस्त नहीं है. पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर शिकंजा नहीं कसा जाता. इस वजह से भी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. राज्य गठन के बाद आबादी बढ़ी, वाहन बढ़े, लेकिन सड़कें वही रहीं. झारखण्ड सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व सड़क हादसों में हो रही मौतों पर गंभीर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना के शिकार लोगों का समुचित उपचार करने और उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छह जगहों पर ट्रॉमा सेंटर बनाने का निर्णय लिया था. तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री भानू प्रताप शाही ने इसके लिए बाक़ायदा एक कमेटी का गठन भी किया था. स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्रॉमा सेंटर के लिए टेंडर भी निकाला गया. समुचित राशि भी आवंटित की गयी. लेकिन यह महत्वाकांक्षी योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी. ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के पीछे यह मंशा थी कि सड़क हादसों के शिकार लोगों को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके, जिससे दुर्घटना के शिकार हो रहे लोगों की संख्या में कमी हो सके. लेकिन रिम्स परिसर स्थित राज्य का एकमात्र ट्रॉमा सेंटर स्थापना के बाद से ही लकवाग्रस्त है.

feedback@chauthiduniya.com

जे.पी.सिंह की किताब पर प्रतिबंध क्यों नहीं ?

गांधी विरोधी विचार पर बिहार सरकार का विरोधभासी रवैया

महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं. उनके विरोध में कुछ भी बोलने वाला भारतवासियों का दोस्त नहीं हो सकता है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी यही मानना है. महात्मा गांधी के विरोध में अगर अमेरिका में कोई कुछ बोलता है तो एक सच्चे और अच्छे भारतीय नागरिक होने की वजह से नीतीश कुमार को बुरा लगता है. बुरा लगना स्वाभाविक भी है. अमेरिकी लेखक के गांधी विरोधी विचार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो टिप्पणी आई है, उससे गांधी जी के प्रति उनका सम्मान सामने आया है. लेकिन दूसरे ही क्षण जब इसी तरह का दूसरा पहलू सामने आता है तो मुख्यमंत्री की लंबी चुप्पी बहुत सारी बातें कह जाती है. जनार्दन प्रसाद सिंह उर्फ़ जे.पी.सिंह बिहार के रहने वाले हैं. उन्होंने एक किताब लिखी है. किताब का नाम है *आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन*. ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ करते हुये जे.पी. सिंह ने कई आपत्तिजनक बातें लिखी हैं. अविभाजित हिन्दुस्तान के मुसलमानों को राष्ट्रीयता की मुख्य धारा में जोड़ने वाले सर सैयद अहमद खां तथा सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा जैसी अमर कृति के रचयिता डॉ. अल्लामा इकबाल पर सांप्रदायिकता का लांछन तो लगाया ही है साथ

किताब के विरोध में पटना के गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन में सभी धर्म एवं सम्प्रदाय के लगभग 450 बुद्धिजीवियों, कवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, काव्यकारों, कथाकारों एवं प्राध्यापकों ने भाग लिया.

ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी नहीं बख़्शा गया है. क्या महात्मा गांधी हरिजन विरोधी थे? जी हां, जे.पी.सिंह यही मानते हैं. उनकी किताब के पृष्ठ सं- 160 में यही लिखा हुआ है. जे.पी.सिंह कोई जाने माने लेखक नहीं हैं. सिंह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का हुनर जानते हैं. आप राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक हैं. ज़ाहिर है इतने बड़े पद पर बैठने वाला आदमी ज़िम्मेदार पदाधिकारी ही हो सकता है. लेकिन महात्मा गांधी पर कीचड़ उछालकर भी वह निदेशक, उच्च शिक्षा के पद पर बने हैं, यह आश्चर्य की बात है. बार-बार मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयास भी बेकार सावित हो जाता है. यही वह मुकाम है, जहां महात्मा गांधी के प्रति मुख्य मंत्री नीतीश कुमार की श्रद्धा और सम्मान एक अनसुलझी पहेली जैसी लगने लगती है. गांधी विरोधी अमेरिकी लेखक के विचार पर आपत्ति जताने और गांधी विरोधी लोकसेवक जे.पी. सिंह की आपत्तिजनक कथनी पर चुप्पी साध लेने जैसा दोहरा पैमाना कैसे चलेगा. जे.पी. सिंह ने अपनी किताब में केवल राष्ट्रीय अस्मिता को ही आघात नहीं पहुंचाया है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन नाम की पुस्तक के माध्यम से राष्ट्रनिर्माता तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां और इक़बाल की राष्ट्रभक्ति पर उंगली उठाकर स्वस्थ समाज को नफ़रत की आग में झोंकने की कोशिश की है. इसके ख़िलाफ़ पिछले दिनों ऑल बिहार उर्दू जर्नलिस्ट फोरम के तत्वाधान में एक दिवसीय राजस्तरीय धरना, प्रदर्शन तथा राजभवन मार्च का आयोजन किया गया. इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल, बिहार देबानन्द कुंवर को एक मेमोरेंडम देकर उनसे अनुरोध किया गया कि साझी संस्कृति की परम्परा को आघात पहुंचाने और समाज में द्वेष तथा नफ़रत की आग को भड़काने वाली इस पुस्तक की ख़रीद बिक्री पर अविलम्ब पाबन्दी लगाने और इसके लेखक तथा बिहार की सुशासन वाली सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक जे.पी.सिंह को अविलम्ब पदमुक्त करते हुए उन पर कार्यवाई चलाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया जाए. किताब के विरोध में पटना के गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर आयोजित धरना प्रदर्शन में सभी धर्म एवं संप्रदाय के लगभग 450 बुद्धिजीवियों, कवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों, काव्यकारों, कथाकारों एवं प्राध्यापकों ने भाग लिया. धरने को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के लेखक जे.पी.सिंह ने आधुनिक भारत के निर्माण तथा सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में सर सैयद अहमद खां और डॉ. इकबाल जैसे महान लोगों का जो योगदान रहा है, उस पर जानबूझ कर पर्दा डालने और नफ़रत की आग को हवा देने की कोशिश की है. इससे नागरिक समाज, विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग में काफ़ी असंतोष है.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com